चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 09 फरवरी–15 फरवरी 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

फ़ायदे में रहा अमेरिका

गणतंत्र दिवस के मौक़े पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर चल रहे कई साल पुराने गतिरोध को समाप्त करने पर सहमति बन गई. इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साझा बयान में हुई. इस समझौते को लेकर मीडिया इतना उत्साहित था कि पहले ही यह ख़बर सूत्रों के हवाले से टेलीविज़न चैनलों पर फ्लैश होने लगी. साथ ही इस समझौते को सरकार की बड़ी कामयाबी के रूप में पेश किया जाने लगा. लेकिन, क्या इसे सरकार की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है? क्या जो आशंकाएं इस समझौते को लेकर लोगों के मन में थीं, वे समाप्त हो गई हैं? आज जबकि परमाणु ऊर्जा पर आश्रित बड़े उत्पादक देश अपने परमाणु रिएक्टर बंद कर रहे हैं, तो भारत नए रिएक्टर लगाने की होड़ में क्यों लग गया है? क्या भारत की ऊर्जा की मांग परमाणु ऊर्जा के बगैर पूरी नहीं हो सकती है? एक और अहम सवाल यह कि क्या परमाणु प्लांट आतंकवादियों और दुश्मन देशों के लिए एक आसान टारगेट नहीं बन जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब जानना ज़रूरी है.

फ़ोटो : प्रभात पाण्डेय

शफीक आलम

भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते की बुनियाद 2005 में वाशिंगटन में पड़ी थी, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पहली बार दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग पर सहमति बनाने की बात की थी. यह समझौता, जिसे 123 समझौता कहा जाता है, 2008 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस के दस्तखत के साथ अमल में आया था. वर्ष 2005 और 2008 के दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताओं के बाद नवंबर 2006 में अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका-भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग और अमेरिकी अतिरिक्त प्रोटोकॉल कार्यान्वयन अधिनियम पारित किया था. इन क़ानूनों के मुताबिक, भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग के लिए अमेरिका ने अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की कुछ शर्तों में छूट दे दी थी, जिसमें प्रमुख था भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मुक्त कर देना. इस समझौते का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत का बहिष्कार समाप्त कर दिया. लेकिन, यह समझौता अपने शुरुआती दिनों से ही विवादों में घिरा रहा है.

भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग पर समझौता पहली यूपीए सरकार हर क़ीमत पर करना चाहती थी. उसकी उत्सुकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए दो बार अपनी कुर्सी दांव पर लगाई. अंत में यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहीं वामपंथी पार्टियों ने इस समझौते को लेकर अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन दूसरी पार्टियों के समर्थन से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी. सोनिया गांधी ने 2007 में हरियाणा की एक रैली में इस समझौते का विरोध करने वाले लोगों को शांति और विकास का दुश्मन करार दिया था. बहरहाल, विपक्ष (जिसमें वामपंथी और भाजपा दोनों शमिल थे) दुर्घटना की स्थिति में उत्तरदायित्व के सवाल पर सरकार को घेरता रहा. इसी दबाव के मद्देनज़र सरकार ने अंत में सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 पारित कराया. इस एक्ट के सेक्शन 17(बी) में एक प्रावधान रखा गया था, जिसके मुताबिक, अगर सप्लायर की खामियों या उसके कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कोई परमाणु हादसा होता है, तो ऑपरेटर (यानी सरकार) सप्लायर कंपनी से मुआवज़ा वसूल करेगी. इस पर अमेरिका को ऐतराज़ था. वहीं दूसरी तरफ़ अमेरिका यह चाहता था कि वह भारत में अपने परमाणु सप्लाई और तकनीक की निगरानी करे. ज़ाहिर है, भारत इसके लिए तैयार नहीं था. अमेरिका का यह भी आरोप था कि भारत का नागरिक परमाणु समझौता इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ़ सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से इस समझौते को संचालित नहीं किया जा सका था.

मौजूदा समझौते (सहमति) के मुतबिक़, अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट गया है और अब भारत के परमाणु संयंत्रों की केवल आईएईए के मानकों के तहत ही निगरानी हो सकेगी. बदले में भारत ने क़ानून में बदलाव किए बिना ही इस बात पर सहमति जता दी है कि दुर्घटना होने की स्थिति में मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी ऑपरेटर (सरकार) और एक स्वतंत्र बीमा कंपनी की होगी. सरकार का कहना है कि कुल 1500 करोड़ रुपये का बीमा दिया जाएगा, जिसमें 750 करोड़ रुपये की राशि का बीमा एक सामान्य बीमा कंपनी करेगी और 750 करोड़ रुपये सरकार वहन करेगी. ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि अगर यही काम करना था, तो फिर इस समझौते को लागू करने के लिए इतने दिनों तक इंतज़ार क्यों किया गया या इसे यह माना जाए कि सरकार अमेरिका और सप्लायर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है?

2010 में इस क़ानून के संसद में पेश किए जाने के समय भाजपा ने वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते का विरोध किया था. लोकसभा में विपक्ष की नेता और वर्तमान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने देश को धोखा दिया है. लेकिन सरकार बदली, तो उनके सुर भी बदल गए. हालांकि, सितंबर 2014 तक उनकी पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रही. विदेश मंत्री बनने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का हवाला देते हुए कहा था कि सरकार सप्लायर लाइबिलिटी क़ानून में संशोधन नहीं करेगी, लेकिन इस दृश्य के बदलने में अधिक समय नहीं लगा.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

परमाणु ऊर्जा : कुछ तथ्य

- अमेरिका में कुल 104 परमाणु संयंत्र हैं. 1979 की थ्री-माईल आईलैंड दुर्घटना के बाद कोई दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया गया.
- दुनिया के 31 देशों में कुल 430 व्यवसायिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं.
- अब तक कुल तीन बड़े परमाणु संयंत्र हादसे हुए हैं, थ्री-माईल आईलैंड (1979), चेर्नोबेल (1986) और फुकुशीमा डाइची (2011).
- दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 27 जून, 1954 को भूतपूर्व सोवियत संघ के ओब्निन्स्क में स्थापित हुआ था.
- अमेरिका का पहला व्यवसायिक परमाणु जनरेटर शिपिंग पोर्ट रिएक्टर पेनसिलवेनिया में 1957 में शुरू हुआ था.
- अमेरिका का परमाणु संयंत्र का कचरा परमाणु संयंत्र के पास ही ठंडे पानी के पूल और सूखे हुए बक्सों में रखा जाता है. सरकार इसे युक्का पर्वत, नेवड़ा में ज़मीन के अंदर गाड़ना चाहती है, लेकिन पड़ोसी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं.
- अमेरिका में तक़रीबन 71 हज़ार टन परमाणु कचरा है.
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र को इस्तेमाल हो चुके यूरेनियम और रेडियोधर्मी कचरा हटाने के लिए हर 18-24 महीने में एक बार बंद करना पड़ता है.
- तारापुर एटॉमिक पॉवर स्टेशन (टीएपीएस) भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जिसका निर्माण 1962 में शुरू हुआ था और उसने 1969 में उत्पादन करना शुरू कर दिया था.
- यूरेनियम के एक फ्यूल पेलेट (छोटा टुकड़ा) में 480 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस, 807 किलोग्राम कोयला या 149 गैलन आयल के बराबर ऊर्जा होती है.

ओबामा के दौरे का विरोध भी हुआ... पेज-04

अरबों रुपये बकाया, चोरी और उस पर सीनाजोरी पेज-06

नीतीश और मांझी आमने-सामने पेज-07

साई की महिमा पेज-12

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

फ़ायदे में रहा अमेरिका

पृष्ठ एक का शेष

साझा बयान : बहरहाल, 25 जनवरी के साझा बयान के दौरान जब जलवायु परिवर्तन पर चीन–अमेरिका सहमति के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया कि क्या वह जलवायु परिवर्तन पर चीन–अमेरिका सहमति का दबाव महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत किसी देश के दबाव में नहीं आता, लेकिन दबाव है. दबाव है, आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ जलवायु देने का, स्वच्छ ऊर्जा देने का. उनका आशय यह भी था कि जलवायु परिवर्तन पर भारत गंभीर है और इस मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड से हटने को भी तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका से अपारंपरिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग आवश्यक है. यह सच्चाई है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता और इसके रिएक्टर बिना रुके महीनों तक चल सकते हैं. परमाणु ऊर्जा पर अधिक निर्भरता कार्बन उत्सर्जन में कमी की वजह हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव और इस पर होने वाले व्यय को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. अब सवाल यह उठता है कि क्या परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में रखा जा सकता है? चेर्नोबिल और फुकुशीमा की घटनाओं को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है. साथ ही परमाणु संयंत्र से निकले कचरे को ठिकाने लगाने में काफी खर्च होता है और इसे रेडिएशन मुक्त होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं. लिहाज़ा ये किसी भी समय ख़तरा उत्पन्न कर सकते हैं. परमाणु संयंत्र के बहुत सारे ख़तरों में से एक यह भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ऊर्जा के दूसरे विकल्पों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं.

परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता कम करने का प्रयास : परमाणु ऊर्जा उत्पादक कंपनियों के सुरक्षा के लाख दावों के बावजूद इसके ख़तरे से किसी को इंकार नहीं हो सकता. यह हादसा कितना भयानक हो सकता है, इसकी मिसालें भी मौजूद हैं. 1986 में उक्रेन की चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना की भयावह तस्वीर आज भी लोगों के ज़ेहन में ताज़ा है. इसी तरह 1979 की थ्री–माईल आइलैंड परमाणु दुर्घटना ने परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर सवालिया निशान लगा दिया था. जापान की फुकुशीमा परमाणु दुर्घटना तो अभी हाल की घटना है. बहरहाल, अमेरिका की थ्री–माईल आइलैंड दुर्घटना के बाद परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चलाने वाले अनेक देशों ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास शुरू किए. इस मामले में स्वीडन पहला देश था, जिसने 1980 में पहली बार अपने परमाणु ऊर्जा प्लांटों को फेज–आउट करने लिए जनमत संग्रह कराया था. उसके बाद स्वीडन की संसद ने 2010 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा प्लांट बंद करने का लक्ष्य रखा. परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता के मामले में स्वीडन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है. इस देश के कुल उत्पादन की 40 प्रतिशत ऊर्जा परमाणु रिएक्टर से आती है. बहरहाल, ऊर्जा प्रतिस्पर्द्धा की वजह से 2010 में इस क़ानून में संशोधन किया गया, लेकिन इस देश में अब भी परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है. स्वीडन की सत्ता में भागीदार दो पार्टियों सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी के बीच समझौता हुआ है, जिसमें शत–प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने लिए एक कमीशन गठित किया गया है और परमाणु ऊर्जा को सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है.

उसी तरह जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्पेन भी परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं. जापान की फुकुशीमा परमाणु दुर्घटना के बाद जर्मनी ने अपने कई रिएक्टर बंद कर दिए हैं. फ्रांस परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है. वहां के राष्ट्रपति फ्रांसुवा ओलांद ने तो परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता में कटौती को अपना चुनावी मुद्दा बनाया था. फुकुशीमा परमाणु दुर्घटना के बाद जापान में भी इसके ख़िलाफ़ जनमत तैयार हो रहा है और सरकार पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कमी का बेहद दबाव है. अमेरिका में कुल विद्युत उत्पादन का केवल 19 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से हासिल होता है. हालांकि, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा

उत्पादन में कमी करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1979 की थ्री–माईल आइलैंड परमाणु दुर्घटना के बाद यहां कोई नया रिएक्टर कमीशन नहीं हुआ है. साथ ही प्राकृतिक गैस की क़ीमतों में कमी के कारण अब परमाणु ऊर्जा और गैस से चलने वाले बिजली घरों के उत्पादन की लागत लगभग बराबर है. इन तथ्यों से यह नतीजा निकालना मुश्किल नहीं है कि एक तरफ़ दुनिया के विकसित देश परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ भारत जैसे विकासशील देशों में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की जैसे होड़ लगी है. मिसाल के तौर पर चीन 2020 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता तीन गुना करना चाहता है.

अगर विश्व में ऊर्जा की खपत और उत्पादन पर एक नज़र डाली जाए, तो यह पता चलेगा कि नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के बावजूद दुनिया में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कुल ऊर्जा उत्पादन में कम हुई है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) के मुताबिक, दुनिया के कुल बिजली उत्पादन का महज 11 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है, यह 1982 के बाद से सबसे कम है. बहरहाल, अगर पूरी दुनिया को एक साथ मिलाकर देखा जाए, तो परमाणु ऊर्जा के बिना भी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं. लेकिन, यह संभव नहीं है, क्योंकि अलग–अलग देशों की ऊर्जा ज़रूरतें अलग–अलग हैं.

परमाणु संयंत्र स्थापित करने का खर्च : परमाणु ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती दिनों में अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन लेविस स्ट्रॉस ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब परमाणु ऊर्जा की वजह से बिजली की क़ीमत कम हो जाएगी. अमेरिका में परमाणु ऊर्जा के प्रसार का विरोध करने वाली एक संस्था के मुताबिक, 2002 और 2008 के दरम्यिान एक परमाणु रिएक्टर बनाने का खर्च दो से चार अरब डॉलर था, जो 2008 में बढ़कर नौ अरब डॉलर हो गया. भारत 2013 में अमेरिका से अल्ट्रा मॉडर्न वेस्टिंगहाउस एपी–1000 न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने के लिए सौदेबाजी कर रहा था. तीन लाख करोड़ रुपये की लागत के इस रिएक्टर को मीठीविर्दी (गुजरात) में स्थापित करने की योजना है. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉ. गोपाल कृष्णन के मुताबिक, फ्रांसीसी परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन का खर्च 30–35 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होगा, अमेरिका के एपी–1000 परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन का खर्च 20–25 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होगा. जबकि इसी क्षमता की ताप विद्युत योजना के लिए कार्बन उत्सर्जन नियंत्रक तकनीक का खर्च पांच से सात करोड़ रुपये आएगा. परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़े तमाम ख़तरों के बावजूद अगर सरकार इससे अपनाना ही चाहती है, तो क्या प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में घरेलू टेक्नोलॉजी को नहीं आजमाया जा सकता है?

क्या है ख़तरा : परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना कितनी भयानक हो सकती है, इसकी मिसालें मौजूद हैं. इस सिलसिले में आम तौर पर थ्री–माईल आइलैंड, चेर्नोबिल और फुकुशीमा परमाणु संयंत्र दुर्घटनाओं के नाम लिए जा सकते हैं. लेकिन, लीकेज की छोटी–छोटी घटनाएं आम तौर पर होती रहती हैं. चूंकि परमाणु संयंत्र में कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित दुर्घटना बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है, इसलिए परमाणु संयंत्र स्थापित करने से पहले कुछ बिंदुओं पर भी ग़ौर करना ज़रूरी है. आतंकवादियों के लिए ये आसान लक्ष्य हो सकते हैं. इस भय को सिरे से ख़ारिज नहीं किया जा सकता है कि आतंकवादी हमारे परमाणु संयंत्रों पर 9/11 की तरह का कोई हमला नहीं कर सकते. साथ में पाकिस्तान और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिनके लिए ये संयंत्र आसान लक्ष्य बन जाएंगे. पाकिस्तान ने तो भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपने परमाणु हथियार का विकल्प हमेशा खुला रखने की बात की है. तो इसकी क्या गारंटी है कि वह एक–दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करने के समझौते की अवहेलना नहीं करेगा. इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक आपदा भी दुर्घटना की वजह हो सकती है. फुकुशीमा की घटना भूकंप और सुनामी की वजह से घटी थी. भारत सरकार ने फिलहाल दो परमाणु संयंत्रों की स्थापना के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को चुना है. गुजरात भूकंप के अधिक ख़तरे वाले क्षेत्र में आता है. महाराष्ट्र को भूकंप के लिहाज़ से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन 1993 के लातूर के भूकंप ने इस अवधारणा को ग़लत साबित कर दिया. ऐसे में इन दो राज्यों में परमाणु संयंत्र स्थापित करना कहां तक उचित है.

कितनी परमाणु ऊर्जा मिलेगी : भारत में बिजली उत्पादन के मामले में परमाणु ऊर्जा का स्थान सबसे नीचे है. कोयला आज भी भारत में बिजली उत्पादन का सबसे प्रमुख ईंधन है. भारत में कुल बिजली उत्पादन में कोयले की 59.51 प्रतिशत, पनबिजली की 16.33 प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जा की 12.70 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस की 9.06 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा की 1.90 प्रतिशत और तेल की 0.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है. भारत ने 2032 तक 63 हज़ार मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. अगर विकसित देश परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो 2032 तक बहुत सारे देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर निर्भरता से मुक्त हो जाएंगे. ऐसे में भारत का चीन के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन की होड़ में शामिल होना अमेरिकी और पश्चिमी देशों की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने से अधिक कुछ भी नहीं है. और, जो लक्ष्य स्थापित किए गए हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि 2033 तक भी परमाणु ऊर्जा ताप ऊर्जा और दूसरी अपरंपरागत ऊर्जा का स्थान नहीं ले पाएगी.

जहां तक ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का सवाल है, तो उसके उत्पादन में खर्च अधिक होता है, लेकिन हाल के वर्षों में दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत के एक बड़े हिस्से में सौर ऊर्जा के उत्पादन की लागत पारंपरिक ऊर्जा के तक़रीबन बराबर हो गई है. भारत में सोलर पैनलों की क़ीमतों में पिछले पांच वर्षों में 75 प्रतिशत तक कमी आई है. यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा लागत पारंपरिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी. वहीं पवन ऊर्जा देश के कई हिस्सों में ताप संयंत्रों से प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में पहुंच गई है. ऐसे में सरकार का यह कहना कि अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा चुनना ज़रूरी है, तर्कसंगत नहीं लगता. ■

क्या हुआ था चेर्नोबेल, फुकुशीमा और थ्री–माईल आईलैंड में?

पच्चीस साल पहले, 26 अप्रैल की सुबह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा लोगों ने देखा. यूक्रेन के चेर्नोबेल पावर प्लांट का एक रिएक्टर फट गया. दो धमाकों ने रिएक्टर की छत उड़ा दी और उसके अंदर के रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर बह निकले. बाहर की हवा रिएक्टर के अंदर पहुंच गई. नतीजतन आग लग गई, जो नौ दिनों तक धधकती रही, क्योंकि रिएक्टर के चारों ओर कांक्रीट की दीवार नहीं बनी थी, इसलिए रेडियोधर्मी मलबा वायुमंडल में फैल गया. इस दुर्घटना में जो रेडियोधर्मी किरणें निकलीं, वे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 100 गुना अधिक थीं. अधिकतर मलबा चेर्नोबेल के आसपास के इलाकों में गिरा, जैसे यूक्रेन, बेलारूस और रूस. परंतु रेडियोधर्मी पदार्थों के कण उत्तरी गोलार्ध के तक़रीबन हर देश में पाए गए. इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई और अगले कुछ महीनों में 38 अन्य लोग रेडियोधर्मी बीमारियों के कारण काल के गाल में समा गए. 36 घंटे के अंदर क़रीब 59,430 लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इस भयानक दुर्घटना के कारण दो लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा. धरती का एक बड़ा भाग प्रदूषित हुआ और अनेक लोगों को रोजी-रोटी का नुक़सान हुआ. 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार, क़रीब छह लाख लोग तीव्र रेडियोधर्मिता के शिकार बने और उनमें से 4,000 लोगों की कैंसर से मौत हो गई. इस पूरे प्रकरण में 200 अरब डॉलर का संभावित नुक़सान हुआ. इसके अलावा, जीवित लोगों की मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ा, उसे नहीं मापा जा सकता है. हादसे के बाद कई लोग शराबी हो गए और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली. चेर्नोबेल दुर्घटना के अलावा अन्य कई परमाणु संयंत्र हादसे हो चुके हैं. सबसे पहली दुर्घटना 12 मार्च, 1952 को कनाडा स्थित चाक रिवर फसिलिटी में घटी. एक कर्मचारी ने ग़लती से दाब नियंत्रक संयंत्र के चारों वाल्व खोल दिए. परिणामस्वरूप संयंत्र का ढक्कन उड़ गया और बहुत अधिक मात्रा में परमाणु कचरे से दूषित शीतलन जल बाहर फैल गया. दूसरा हादसा 29 सितंबर, 1957 को रूस के पहाड़ी इलाके में स्थित मायक प्लूटोनियम फसिलिटी में हुआ. यह हादसा तो चेर्नोबेल से भी ख़तरनाक माना जाता है. शीतलन संयंत्र में खराबी आ जाने के कारण गरम परमाणु कचरा फट पड़ा. 2,70,000 लोग और 14,000 वर्ग मील क्षेत्र रेडियोधर्मी विकिरण की चपेट में आ गए. इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र का विकिरण स्तर बहुत अधिक है और प्राकृतिक जल स्रोत आज भी नाभिकीय कचरे से दूषित हैं. इंग्लैंड स्थित विंड स्केल न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के हादसे में विकिरण रिसाव के कारण 200 वर्ग मील क्षेत्र दूषित हो गया. 1975 को जर्मनी में लुब्मिन न्यूक्लियर प्लांट में खराबी आ गई, परंतु एक बड़ी दुर्घटना होते-होते बच गई. 1979 में अमेरिका में पेन्सिल्वेनिया का थ्री माईल आइलैंड हादसा भी शीतलन संयंत्र में खराबी आ जाने के कारण हुआ. आसपास के लोगों को समय रहते वहां से निकाल लिया गया, परंतु फिर भी इस इलाके में कैंसर और थायराइड के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा बच्चों की मृत्यु दर में भी इजाफा हुआ है. तोकैमुरा हादसा जापान में 1999 में घटित हुआ, जब आणविक ईंधन बनाने के लिए ग़लती से नाइट्रिक एसिड में बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम मिला दिया गया. 5.2 पाउंड के स्थान पर 35 पाउंड. फलस्वरूप नाभिकीय विखंडन विस्फोट 20 घंटे तक अनवरत होता रहा. संयंत्र के 42 कर्मचारी हानिकारक विकिरण के शिकार हुए, जिनमें से दो की मृत्यु हो गई.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 49
दिल्ली, 09 फरवरी–15 फरवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901
एडिटर इंवेस्टिगेशन
प्रभात रंजन दीन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

ओबामा की यात्रा से

भारत को क्या मिला

नवीन चौहान

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तीन दिवसीय भारत यात्रा समाप्त हो गई. गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहले असैन्य परमाणु समझौते को अमलीजामा पहनाने की राह में पिछले छह सालों से आड़े आ रहे दो बड़े मुद्दों के गतिरोध को दूर कर लिया गया. इस मसले पर मोदी और बराक ओबामा के बीच आपसी सहमति बनी. अंतत: समझौता संपन्न हो गया. फिलहाल असैन्य परमाणु समझौता भारत–अमेरिका के बीच आपसी समझ का केंद्र बिंदु है, जिसके मुकाम पर पहुंचने पर दोनों देशों के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ है. इससे दोनों देशों के बीच नए आर्थिक अवसर भी तैयार हुए हैं, जिसकी एक झलक ओबामा की इस यात्रा के दौरान दिखाई भी दी. इससे भारत को आर्थिक विकास की राह पर ले जाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प भी बढ़े हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल 2014 के सितंबर माह में हुई अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने असैन्य परमाणु समझौते को अमलीजामा पहनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी. इसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के कॉन्टेक्ट ग्रुप का गठन किया था. इस कॉन्टेक्ट ग्रुप के बीच तीन दौर की बातचीत हुई. हादसों की सूरत में परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति करने वाले देश की ज़िम्मेदारी और परमाणु संयंत्रों के लिए अमेरिका एवं अन्य देशों द्वारा ईंधन पर नज़र रखने जैसे राह में रोड़ा बन रहे मुद्दों को सुलझा लिया गया. अमेरिका न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रैक करने की अपनी मांग से पीछे हट गया है. भारत लगातार यह कहता रहा है कि उसकी यह मांग अवांछित दखलंदाज़ी है. अब भारत पूर्व की तरह आईएईए की निगरानी में रहेगा. मोदी और ओबामा के बीच दोनों मसलों पर सहमति बन गई कि परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की दशा में उपकरण आपूर्ति करने वाली अमेरिकी कंपनी या कंपनियों की जवाबदेही को कम कर दिया जाए. इसके लिए भारत सरकार इंश्योरेंस पूल का गठन करेगी, जिसके तहत मुआवजे की राशि दी जाएगी. यानी अमेरिकी कंपनियों की जवाबदेही एक प्रकार से न के बराबर कर दी गई है. इस इश्योरेंस पूल के तहत कुल राशि 1500 करोड़ रुपये होगी. 750 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र की चार बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जुटाएंगी और बाकी के 750 करोड़ रुपये का भार भारत सरकार पर होगा. दुनिया में कई देश अपने यहां प्लांटों में कोई हादसा होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए ऐसे 26 इश्योरेंस पूल बना चुके हैं. दोनों देश वाणिज्यिक सहयोग की दिशा में अपने क़ानून के अनुरूप, अपने अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी दायित्व और तकनीकी व वाणिज्यिक व्यवहारिकता के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं. भारत को चरणबद्ध तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार एग्रीमेंट जैसे चार ग्रुपों की सदस्यता दिलाने में अमेरिका ने समर्थन करने की घोषणा की है.

रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अगले दस सालों के लिए नए डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं. डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव (डीटीटीआई) के अंतर्गत चार रक्षा उपकरणों के निर्माण की दोनों देशों के बीच सहमति हुई है. दोनों देश मिलकर 4 डिफेंस प्रोजेक्ट बनाएंगे. इन प्रोजेक्टों में साझा सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारियों का आदान–प्रदान और सैन्य अदला–बदली शामिल है. चार प्रोजेक्टों में नई पीढ़ी के रावेन यूएवी, सी 130 सैन्य परिवहन विमानों के लिए विशेषज्ञ किट्स, मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पॉवर सोर्स, यूनीफॉर्म इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन इंसेम्बल इंक्रीमेंट–2 के संयुक्त विकास और उत्पादन की बात शामिल है. दोनों देश जेट इंजन प्रौद्योगिकी की डिजाइनिंग और विकास के साथ ही विमान वाहक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक कार्य दल बनाने पर भी सहमत हुए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच इस मुद्दे पर भी सहमति बनी है कि अमेरिका पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा. अमेरिका ने ग़ैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में दो अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है. परमाणु ऊर्जा के अलावा दोनों देश क्लीन एनर्जी के 100 गीगा वाट सौर ऊर्जा कार्यक्रम में रुचि दिखाई है. वहीं मोदी ने अमेरिकी निवेशकों को भरोसा दिया कि निवेश से जुड़ी खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा.

दोनों देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है. दोनों देशों में उच्चस्तरीय द्विपक्षीय निवेश संधि और टोटलाइजेशन एग्रीमेंट पर फिर से बात शुरू होगी. अमेरिका टोटलाइजेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के लिए राजी हो गया है. यदि बात बन जाती है, तो अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को सालाना 18 हज़ार करोड़ रुपये तक का रिफंड मिल सकेगा. दरअसल, यह वह रकम है, जो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय सोशल सिक्योरिटी के नाम पर देते हैं, लेकिन वर्क वीजा ख़त्म होने पर उन्हें यह रकम वापस नहीं मिलती है. दूसरी तरफ़ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वह भारतीयों के लिए एच–1 बी वीजा नियमों को और आसान बनाएंगे.

अमेरिका ने भारत में चार अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है. यह निवेश सामाजिक विकास के क्षेत्र में किया जाएगा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी अमेरिका मदद करेगा. अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टम में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया है. कारोबारी रिश्तों के साथ–साथ दोनों नेताओं के बीच नज़दीकियां भी बढ़ी हैं. जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा तथा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत के लिए हॉटलाइन शुरू की जाएगी. ओबामा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद में सुधार के पक्ष में है, जिसमें भारत को भी जगह मिलनी चाहिए. दुनिया भर के शांति मिशनों में भारत की अहम भूमिका रही है. दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए उसे और व्यापक भूमिका निभानी चाहिए. ■

navinonline2003@gmail.com

समझौते के मुख्य बिंदु

- परमाणु समझौते पर दोनों देश आगे बढ़े.
- भारत द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों पर सहमति बनी.
- इंश्योरेंस पूल बनाया जाएगा, जिसमें देश की चार बड़ी बीमा कंपनियां शामिल होंगी.
- न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रैकिंग की शर्त से अमेरिका पीछे हटा.
- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए अमेरिका समर्थन करेगा.
- मोदी और ओबामा तथा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के बीच हॉटलाइन शुरू होगी.
- विज्ञान, तकनीक, इनोवेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल्स के मसले पर दोनों देश सहयोग करेंगे.
- आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे.
- डिजिटल इंडिया पर भारत का अमेरिका सहयोग करेगा.
- डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव (डीटीटीआई) को डिफेंस पॉलिसी ग्रुप के तहत बढ़ाया जाएगा.

रिसर्च, डेवलपमेंट, मेन्युफेक्चरिंग और स्थापना के संबंध में भी एक–दूसरे का सहयोग करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत

श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

आधुनिक युग की शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार

आई.टी. और ई–शासन के विकास में अग्रसर उत्तर प्रदेश

twitter.com/cmofficeup facebook.com/cmouttarpradesh youtube.com/user/upgovtofficial

http://information.up.nic.in

बन रहा है आज, सँवर रहा है कल

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

ओबामा के दौरे का विरोध भी हुआ...

प्रकाश करात का आरोप था कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के ज़िम्मेदारी वाले क्लॉज को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की निगरानी और न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल को लेकर माकपा की कई चिंताएं थीं. करात का कहना था कि फ्रांस और रूस ने भारत के साथ परमाणु रिएक्टर बेचने का करार किया है, लेकिन अमेरिका इससे पहले इस क्लॉज़ को बदलवाना चाहता है. भारत मुआवज़े के लिए हमारी बीमा कंपनियों के ज़रिये अमेरिकी कंपनियों को राहत देने का रास्ता खोलने की कोशिश में है, जो बिल्कुल ग़लत होगा. ग़ौरतलब है कि यह आशंका का सच भी साबित हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है, लेकिन यहां भगवान के विरोध की भी परंपरा है. यही वजह है कि बहु-प्रचारित ओबामा का दौरा हुआ तो, लेकिन उसका विरोध भी हुआ. यह अलग बात है कि पहले की तुलना में विरोध की आवाज़ थोड़ी मद्धिम रही. इसकी राजनीतिक वजहें भी हैं. आज देश में विपक्ष की कमजोर स्थिति, खासकर वामपंथी पार्टियों की दुर्दशा की वजह से विरोध का स्वर उतना तीव्र नहीं गूंजा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोकतंत्र में कमजोर विरोध की आवाज़ को स्थान ही न मिले. यह ज़रूरी है कि कम से कम विरोध की बुनियादी वजहों पर ज़रूर चर्चा हो. लेकिन, मौजूदा राजनीतिक हालात में इसकी गुंजाइश कम ही दिखती है.

पहले यह जानते हैं कि विरोध के स्वर कहां से निकले? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के पूर्व ही अमेरिकी हितों के लिए काम कर चुकी है और ओबामा की यह यात्रा उसी क्रम का एक हिस्सा है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव प्रकाश करात का आरोप था कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के ज़िम्मेदारी वाले क्लॉज को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की निगरानी और न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल को लेकर माकपा की कई चिंताएं थीं. करात का कहना था कि फ्रांस और रूस ने भारत के साथ परमाणु रिएक्टर बेचने का करार किया है, लेकिन अमेरिका इससे पहले इस क्लॉज़ को बदलवाना चाहता है. भारत मुआवज़े के लिए हमारी बीमा कंपनियों के ज़रिये अमेरिकी कंपनियों को राहत देने का रास्ता खोलने की कोशिश में है, जो बिल्कुल ग़लत होगा. ग़ौरतलब है कि यह आशंका सच भी साबित हुई. मौजूदा बिल में प्रावधान था कि अगर रिएक्टर में हादसा होता है, तो उसे चलाने वाली कंपनी के साथ बेचने वाली कंपनी पर भी मुआवज़े के लिए दावा किया जा सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर कई विवाद थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. सरकार समेत बीमा कंपनियां अब मुआवज़े का भुगतान करेंगी. इसके अलावा विरोध इस बात का भी था कि रिएक्टरों में इस्तेमाल और रिसाइकिल होने वाले ईंधन पर भी अमेरिका निगरानी रखना चाहता है. वैसे सरकार ने अमेरिका की इस मांग को ग़ैर ज़रूरी बताया है और इसे नहीं माना है.

कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी ओबामा दौरे के लिए दिल्ली और आगरा को नो फ्लाइंग जोन बनाने पर आपत्ति जताई. राज बब्बर ने कहा कि हम अपने आकाश और अपने मेहमानों को सुरक्षित करने में सक्षम हैं, लेकिन ओबामा के दौरे में इस सुरक्षा व्यवस्था को विदेशी शक्तियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है. यह अलग बात है कि बाद में ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया था. दिलचस्प रूप से जहां एक तरफ़ भारत सरकार की सभी एजेंसियां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को सफल बनाने की कोशिश कर रही थीं, वहीं भाजपा के ही एक सांसद चौधरी बाबूलाल ओबामा के काफिले का रास्ता रोकने की योजना बना रहे थे. वह आगरा में वकीलों के साथ थे, जो ओबामा के दौरे का विरोध कर रहे थे. वकीलों ने धमकी दी थी कि वे ओबामा को ताजमहल में दाखिल नहीं होने देंगे. वकीलों की मांग थी कि केंद्र सरकार आगरा में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करे. यह अलग बात है कि बाद में ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया. इसके बाद भी अपनी मांग को लेकर वकीलों ने आगरा में प्रदर्शन किया. इस सबके अलावा, बराक ओबामा की भारत यात्रा का नक्सली संगठनों ने भी विरोध किया. नक्सलियों ने बाज़ार में दिनदहाड़े बैनर-पोस्टर टांगकर इस यात्रा का विरोध किया. गढ़चिरौली-महाराष्ट्र के कुआकोंडा थाना अंतर्गत ग्राम मोखपाल में लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार के दौरान माओवादियों ने दिनदहाड़े पहुंच कर बैनर और पोस्टर लगाए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, नक्सलियों का एक समूह दिन के 11 बजे हाट में आकर जगह-जगह पोस्टर लगा गया. माओवादियों ने बैनर-पोस्टर में 26 जनवरी को बंद का आह्वान भी किया था.

बहरहाल, ओबामा का दौरा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है. न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल पर भी सहमति बन चुकी है. आपदा की स्थिति में मुआवज़े की सीधी ज़िम्मेदारी से अमेरिकी कंपनियों को मुक्त कर दिया गया. भारत सरकार और बीमा कंपनियां मुआवज़े की ज़िम्मेदारी संभालेंगी. उक्त संगठनों का विरोध इस मायने में कहीं से भी कारगर साबित नहीं हुआ. अथवा यूं कहें कि उक्त विरोध सिर्फ़ विरोध के लिए थे या रस्म निभाने के लिए. नक्सली संगठनों को किनारे रख दें, तो राजनीतिक दलों की ओर से भी सिर्फ़ बयानबाजी हुई. किसी भी राजनीतिक दल (विपक्ष) ने न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल जैसे अहम मुद्दे पर अपनी बात जोरदार तरीके से नहीं रखी. हां, वामपंथी पार्टी सीपीआई और उसके कुछ संगठनों ने सड़कों पर ज़रूर थोड़े-बहुत प्रदर्शन किए. शायद विपक्ष अभी भी हताशा की स्थिति से बाहर नहीं निकल सका है. इसी का नतीजा है कि न सिर्फ़ न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल, बल्कि भूमि अधिग्रहण और कोयले पर आए अध्यादेश आदि पर भी विपक्ष की ओर से कोई जोरदार विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे हैं. कम से कम किसी राजनीतिक दल को इन मुद्दों पर सड़क पर उतर कर अपनी बात कहते हुए नहीं देखा गया. अब देखना यह है कि विपक्ष संसद के भीतर क्या करता है?■

ओबामा की भारत यात्रा

पाकिस्तानी चैनल सामान्य रहे, प्रिंट मीडिया बौखलाया

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का दौरा करते रहे हैं. वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा भी 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आ चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जनवरी 2015 में उनका यह दूसरा भारत दौरा था. ओबामा के हाल के दौरों में यह ऐसा पहला दौरा रहा, जब पाकिस्तान और उसका प्रिंट मीडिया वास्तव में बौखला उठा. वैसे अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंदाज़ सामान्य था, जो कि आश्चर्य की बात है. आइए देखते हैं, क्या और कैसी है पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया की बौखलाहट...

ए.यू.आसिफ

वर्ष 2003 की बात है. यह पत्रकार दक्षिण एशिया के अन्य पांच पत्रकारों के साथ अमेरिका के दौरे पर था. उस दौरान अमेरिकी प्रशासन के कुछ ज़िम्मेदारों से बातचीत करने का अवसर मिला, जिसमें यह महसूस हुआ कि सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान उसकी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि उसका प्रिय है. यही कारण रहा कि दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड मुंबई के रेजिडेंट एडिटर तमल बंदोपाध्याय के साथ यह पत्रकार अमेरिकी प्रशासन के ज़िम्मेदारों से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले अधिक अहमियत देने का कारण मालूम करता रहा. मगर, वे सिर्फ़ यह कहकर सवाल टालते रहे कि यह इस समय अमेरिका के हित में है. जाहिर-सी बात है कि अमेरिका का उस समय यह दृष्टिकोण दक्षिण एशिया के शिष्टमंडल में मौजूद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार महमूद शाम और उनके एक अन्य पत्रकार मित्र को बहुत भा रहा था. यही कारण था कि उस समय वे अमेरिकी प्रशासन के ज़िम्मेदारों से इस तरह मिल रहे थे कि जैसे वे उनके अपने खास और चहेते हों. अमेरिकी प्रशासन का यह दृष्टिकोण कमोबेश भारत में मोदी के सत्ता में आने से पूर्व तक बरकरार रहा. मगर, मोदी के पिछले वर्ष अमेरिका दौरे के दौरान और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन के दृष्टिकोण में अचानक परिवर्तन देखा जाने लगा. फिर जनवरी 2015 में ओबामा के भारत के दूसरे दौरे के दौरान इस परिवर्तन का पूर्ण रूप से प्रदर्शन हुआ. और फिर अमेरिकी दृष्टिकोण में इस परिवर्तन पर भूतकाल में पाकिस्तान के अमेरिकी मित्र जैसे दिखने वाले प्रिंट मीडिया में जो कुछ आया, वह उसकी बौखलाहट का द्योतक है.

प्रसिद्ध पाकिस्तानी उर्दू दैनिक जंग अपने संपादकीय-क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका के तहत लिखता है कि अमेरिका ने आशा के ठीक मुताबिक राष्ट्रपति ओबामा के नई दिल्ली दौरे के दौरान भारत पर मेहरबानियों की बारिश करके क्षेत्र के अन्य देशों को यह संदेश दिया है कि इस क्षेत्र में भारत ही उसका पसंदीदा मोहरा है. कई संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान को भारत का भरोसेमंद सहयोगी बताया और कहा कि भारत से बेहतर संबंध अमेरिकी विदेश नीति में सर्वोच्च है. विश्लेषण करने वाले ने अमेरिका-भारत संबंध के इस नए रुख को क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के आगे बांध बनाने की एक चेष्टा बताया और यह संदेश दिया कि इससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा, जो कि विश्व शांति के लिए लाभदायक नहीं होगा. यह अखबार आगे लिखता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों परमाणु शक्तियां हैं, जो कि आपस में दोस्ती के गहरे रिश्तों में जुड़ी हुई हैं. भारत अमेरिका की सहायता से इन दोनों को नीचा दिखाकर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है. दुर्भाग्य से अमेरिका भी चीन से भयभीत है और उसके स्थान पर भारत को आगे लाना चाहता है. इस मामले में पाकिस्तान के हितों को वह बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर रहा है.

दैनिक एक्सप्रेस अपने संपादकीय-दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन और अमेरिकी प्राथमिकताएं के तहत लिखता है कि अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों के हवाले से महत्वपूर्ण क़दम बढ़ाए गए हैं. दोनों राष्ट्रों के बीच सिविल एवं परमाणु व्यापार शुरू करने का सौदा तय पाया गया है. बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के बाद चार बड़ी घोषणाएं की गईं. अमेरिका ने भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने का समर्थन भी कर दिया अमेरिका और भारत के बीच अरबों डॉलर की परमाणु एवं सुरक्षा संबंधी व्यापार संधि से दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति खुले रूप से निश्चित हो जाती है कि वह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भारत को अपना सहयोगी बना रहा है और इसके द्वारा इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाना चाहता है. इसका साफ़ मतलब है कि भारत, जिसका अमल व दखल अफगानिस्तान में पहले ही मौजूद है, अब उसमें अमेरिकी छतरी तले और अधिक वृद्धि होगी. अमेरिका की भारत से होने वाली रक्षा संधियों के बाद क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है.

दैनिक नवा-ए-वक्त में उसके स्तंभकार असर चौहान की लेखनी पाकिस्तान की बौखलाहट को और भी खुले रूप से दर्शाती है. वह लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब सत्ता संभाली, तो मीडिया ने उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा बताया था. दुनिया भर के मुसलमान खुश हो गए थे कि जनाब ओबामा निस्संदेह ईसाई हैं,

लेकिन हुसैन के नाम की लाज अवश्य रखेंगे. लेकिन, सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के अवसर पर जब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चौबीस घंटे में पूरे प्रोटोकॉल के साथ दो बार भेंट की और इस्लामिक जगत की एकमात्र परमाणु शक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ को समय नहीं दिया, तो पता चला कि हुसैन का नाम तो मात्र दिखावा था. 25 जनवरी को राष्ट्रपति ओबामा जब दूसरी बार भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, तो नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल के तमाम नियम तोड़कर उनका अभिनंदन किया और उनके साथ गभट-गभट जिच्छियां (गलबहियां) डालकर अपने समीप खड़ी अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. मोदी जी ने राष्ट्रपति ओबामा पर डोरे डालने के लिए और अधिक कमाल दिखाया मिशेल ओबामा को एक सौ मूल्यवान बनारसी साड़ियां तोहफे में देकर. एक साड़ी की क़ीमत सवा लाख रुपये बताई जाती है. राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी एवं भारत के कश्मीरी शत्रु हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित कराने का विश्वास दिलाया. इस अख़बार को यकीन है कि इसके बावजूद सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य चीन अमेरिका की इस इच्छा को पूरा नहीं होने देगा.

पाकिस्तान का प्रसिद्ध समाचार-पत्र जसारथ अपने संपादकीय में पाकिस्तानी कूटनीति पर दु:ख व्यक्त करते हुए लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने अपने दौरे के पहले ही दिन भारतीय परमाणु कार्यक्रम की निगरानी से हटने और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने की घोषणा कर दी. शुरुआती तौर यह समाचार भारतीय मीडिया की तरफ़ से जारी हो रहा था, परंतु तुरंत बाद ही प्रेस कांफ्रेंस द्वारा इसकी सरकारी हैसियत भी साफ़ कर दी गई. इसका मतलब यह हुआ कि भारत की ओर से कश्मीर में हस्तक्षेप, मानवाधिकार की अवहेलना और पाकिस्तान में नकारात्मक सरगर्मियां जैसे आरोपों की कोई हैसियत नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ पहले से तय किए गए बहुत-से मामलों में एक-दो का पहले ही दिन ऐलान कर दिया. इसका दूसरा मतलब यह है कि पाकिस्तान की कूटनीति भी शून्य रही. अगर कोई कूटनीति थी, तो शून्य रही. वरना हुआ होगा, जो होता आया है. यह अख़बार आगे लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत दौरा एक ऐसे समय में किया गया है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध अपनी क्षमता से बढ़कर युद्ध लड़ रहा है. उन लोगों से भी युद्ध छेड़ दिया गया है, जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं और अपने ही राष्ट्र के मदरसों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी गई है. यही नहीं, ऐसे क़ानून भी बना दिए गए हैं, जिनसे पूरे राष्ट्र में बेचैनी है और यह सब अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है. लेकिन, अद्भुत बात तो यह है कि अमेरिका खुश होने की बजाय भारत पर ही मेहरबान होता जा रहा है.

सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने ओबामा की भारत यात्रा को चीन के उदय होने के विरुद्ध एशिया को फिर से संतुलित करना करार दिया और यह महसूस किया कि ओबामा और मोदी के एशिया, प्रशांत एवं हिंद महासागर के संबंध में संयुक्त बयान से पाकिस्तान के लिए आइंदा नाजुक भूमिका का अंदाज़ा होता है. एक अन्य अंग्रेजी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय में मोदी-ओबामा की बॉडी लैंग्वेज पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका- भारत संबंध एक नए दृष्टिकोण तक पहुंच चुके हैं. इस समाचार-पत्र ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंध की तुलना अमेरिका-भारत संबंध से करते हुए कहा कि पिछले छह महीनों में पाकिस्तान-अमेरिका के बीच संबंध बढ़े हैं, लेकिन इस हद तक नहीं बढ़े, जैसे भारत और अमेरिका के बीच इस समय है. पाकिस्तान के तमाम उर्दू एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर ओबामा की भारत यात्रा को विशिष्ट स्थान दिया और अपने-अपने अंदाज़ के आलोचनात्मक संपादकीय लिखे. लेकिन, वहां के टीवी चैनलों ने सामान्य अंदाज़ अख्तियार किया. उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओबामा को मुख्य अतिथि बनाए जाने को इतिहास रचना बताया और इस दौरे को लाइव दिखाया. टीवी चैनल आज, जियो टीवी, एआरवाई, एक्सप्रेस दुनिया एवं डॉन टीवी ने अपने प्रत्येक बुलेटिन में टेलीफोन पर पाकिस्तानी शहरों और नई दिल्ली में मौजूद भारतीय पत्रकारों के साक्षात्कार के साथ कवरेज किया. आज टीवी के सद्दाम तुफैल हाशमी ने तो यहां तक कहा कि ओबामा की भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए भी सकारात्मक थी. मेरा विचार है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस समाचार को सामान्य अंदाज़ में दिखाया.■

feedback@chauthiduniya.com

देश के 66वें गणतंत्र दिवस के मौक़े पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ मुख्य समारोह इस बार कई मायनों में अद्वितीय रहा. समारोह के मुख्य अतिथि थे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा. बदलते भारत की सांस्कृतिक विविधता और वैज्ञानिक कुशलता दुनिया को दिखाने का यह एक अहम मौक़ा था. महिला सशक्तिकरण इस समारोह का केंद्रीय विषय था. सेना के तीनों अंगों (जल, थल और वायु) और अर्द्ध सैन्य बलों की महिला टुकड़ियां राजपथ पर पुरुषों के साथ क़दम से क़दम मिलाती दिखीं. उन्होंने देश और दुनिया को संदेश दिया कि नारी अब अबला नहीं, बल्कि सबला है. हमारे फोटो पत्रकार प्रभात पांडेय ने गणतंत्र दिवस समारोह को अपने कैमरे की नज़र से कुछ यूं देखा...

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly
Chauthi Duniya
Santosh Bhartiya
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

हरिद्वार स्थित भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता स्वामी हठयोगी जी महाराज ने कहा कि बाबा रामदेव की कथनी और करनी में ज़मीन–आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि गाय का दूध शुद्ध कहकर उसे पचहत्तर से सौ रुपये किलो और गाय का घी शुद्ध बताकर बाज़ार भाव से सौ रुपये अधिक मूल्य पर बेचना जनता की जेब पर डाका नहीं है, तो क्या है? उन्होंने कहा कि पतंजलि पीठ में भर्ती मरीजों से पांच सितारा होटल का किराया वसूला जाता है. रामदेव पक्के व्यापारी हैं, उनमें योगी का कोई गुण नहीं दिखता है.

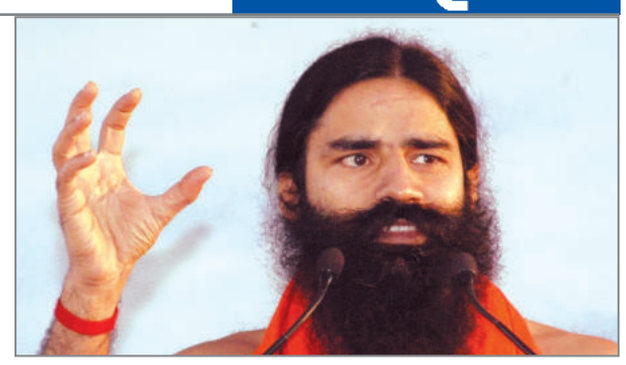

उत्तर प्रदेश में बिजली की बदहाली

अरबों रुपये बकाया, चोरी और उस पर सीनाजोरी

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में बिजली को बड़ा मुद्दा बनाएगी. इसकी तैयारियां चल रही हैं, भूमिका बन रही है और कोयले के कोटे में कटौती के नाम पर केंद्र को लगातार घेरने की कोशिशें हो रही हैं. राज्य का ऊर्जा सेक्टर भीषण संकट में है. मुख्य वजह है, आकंठ भ्रष्टाचार और हर माह करोड़ों रुपये की बिजली चोरी. अरबों रुपये का बकाया उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर को डुबो रहा है. बकाएदारों की सूची में बड़े उद्योगपति, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, चीनी मिलें शामिल हैं. नेताओं, नौकरशाहों, न्यायाधीशों और पहुंच वालों पर भी बिजली का करोड़ों का बकाया है, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान अपने किले के बड़े–बड़े छेद ढंकने की तरफ़ नहीं है. वह मध्यम वर्ग और निम्न–मध्यम वर्ग पर तमाम किस्म के दबाव रखकर वसूली कर रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश के उन तमाम नए–पुराने मुहल्लों में घुसने का साहस नहीं कर रही, जहां बिजली की चोरी खुलेआम होती है. राज्य सरकार बकाया वसूली में भी तुष्टिकरण की नीति अख्तियार कर रही है, जिसे लेकर लोगों में नाराज़गी है.

आधिकारिक दस्तावेज़ बताते हैं कि केवल लखनऊ में ही उपभोक्ताओं पर तक़रीबन 600 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. इनमें घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं. बकाएदारों में अमीनाबाद, चौक, अपट्रॉन और ऐशबाग डिवीजनों के उपभोक्ता अधिक हैं. लेकिन, इनमें वह बड़ी जमात शामिल नहीं है, जो डंके की चोट पर कटिया–कनेक्शन से बिजली जलाती है और चोरी की बिजली से ही अपने उद्योग–धंधे भी चलाती है. उपभोक्ताओं से बकाया राशि न वसूल पाने के कारण बोझ बढ़ता जा रहा है. वसूली न हो पाने की एक बड़ी वजह ग़लत बिलिंग है और विभागीय इंजीनियरों एवं कर्मचारियों की मनमानी भी. बिजली विभाग के कर्मचारी ही लोगों से रिश्वत लेकर उन्हें ग़लत कनेक्शन जारी करते हैं. लखनऊ समेत प्रदेश भर में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं. अभी हाल में आलमबाग क्षेत्र में कई ऐसे उपभोक्ताओं के नाम उजागर हुए, जिन पर लाखों का बकाया होने के बावजूद दूसरे नाम से कनेक्शन जारी कर दिए गए. ऐसे मामले लखनऊ के अमीनाबाद, चौक, नक्खास, चौपटिया, ठाकुरगंज, हुसैनगंज, ऐशबाग, कानपुर रोड जैसे इलाकों में ज़्यादा पाए गए.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ के अमीनाबाद डिवीजन में 7,458 लाख, चौक डिवीजन में 8,783 लाख, अपट्रॉन डिवीजन में 2,228 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसी तरह ऐशबाग डिवीजन में 3,703 लाख, सेस प्रथम में 7,935 लाख, सेस द्वितीय में 6,446 लाख, सेस तृतीय में 1,916 लाख रुपये बकाया हैं. हुसैनगंज डिवीजन में 7,360 लाख, राजभवन डिवीजन में 420 लाख, चिनहट डिवीजन में 1,637 लाख, गोमती नगर में 519 लाख, राजाजीपुरम डिवीजन में 305 लाख, महानगर डिवीजन में 997 लाख, लखनऊ विश्वविद्यालय उपकेंद्र डिवीजन में 647 लाख, कानपुर रोड डिवीजन में 590 लाख, वृंदावन डिवीजन में 465 लाख, रेजीडेंसी डिवीजन में 8,411 लाख, ठाकुरगंज डिवीजन में 5,259 लाख, इंदिरानगर डिवीजन में 61 लाख, मुंशी पुलिया डिवीजन में 555 लाख, बख्शी का तालाब में 981 लाख, डालीगंज डिवीजन में 316 लाख, रहीम नगर डिवीजन में 725 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है.

विभागीय अधिकारी बिजली चोरी को लाइन लॉस की शब्दावली में फंसाकर मामला दबा देते हैं. कथित लाइन लॉस के मामले में चौक, अमीनाबाद, ठाकुरगंज, अपट्रॉन डिवीजन अव्वल हैं. विभाग के आंकड़े बताते हैं कि हुसैनगंज डिवीजन में 68 फ़ीसद, राजभवन डिवीजन में 43 फ़ीसद और अमीनाबाद में 20 फ़ीसद बिजली लाइन लॉस में बर्बाद हो जाती है. चिनहट में 49 फ़ीसद बिजली लाइन लॉस में दिखाई जाती है. सरकार खुद बताती है कि राज्य में हर महीने 400 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली चोरी होती है. यानी बिजली चोरी के चलते विद्युत निगम को 400 करोड़ रुपये का नुक़सान हर महीने हो रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में 71.32 फ़ीसद, कबीना मंत्री आजम खां के गृह ज़िले रामपुर में 52.44 फ़ीसद, बुंदेलखंड के जालौन में 60.34 फ़ीसद बिजली चोरी हो रही है. गौतम बुद्ध नगर अकेला ऐसा ज़िला है, जहां बिजली चोरी सबसे कम 7.85 फ़ीसद है. प्रदेश सरकार बिजली चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, लखनऊ में 31.61, उन्नाव में 27.16, सीतापुर में 26.46, हरदोई में 25.11, लखीमपुर खीरी में 30.10, फैजाबाद में 41.84, अंबेडकर नगर में 36.62, सुल्तानपुर में 27.68, बाराबंकी में 29.81, छत्रपति शाहूजी नगर में 22.06, गोंडा में 53.08, बहराइच में 30.64, श्रावस्ती में 38.62, वाराणसी में 31.75, गाजीपुर में 47.40, जौनपुर में 39.03, चंदोली में 36.86, मिर्जापुर में 39.35, संत रविदास नगर (भदोही) में 58.64, सोनभद्र में 37.53, आजमगढ़ में 67.11, मऊ में 43.80, बलिया में 21.69, गोरखपुर में 34.46, महाराजगंज में 2.81, देवरिया में 36.06, कुशीनगर में 45.94, बस्ती में 38.55, संत कबीर नगर में 40.79, सिद्धार्थ नगर में 40.62, सहारनपुर में 44.30, मुजफ्फर नगर में 33.78, शामली में 59.78, मेरठ में 32.20, बागपत में 45.23, गाज़ियाबाद में 19.15, पंचशील नगर में 44.17, गौतम बुद्ध नगर में 7.85, बुलंद शहर में 40.92, बिजनौर में 32.87, मुरादाबाद में 32.72, संभल में 61.46, रामपुर में 52.44, ज्योति बा फूलेनगर में 51.30, मथुरा में 36.77, आगरा में 33.59, फिरोजाबाद में 42.82, मैनपुरी में 62.10, अलीगढ़ में 31.16, महामाया नगर में 53.24, एटा में 32.79, कांशीराम नगर में 23.19, बरेली में 37.45, बदायूं में 34.28, शाहजहांपुर में 44.16, पीलीभीत में 35.65, फर्रुखाबाद में 58.32, औरैया में 38.53, कानपुर नगर में 28.93, कानपुर देहात में 36.08, प्रतापगढ़ में 34.45, फतेहपुर में 33.99, कौशांबी में 35.23, इलाहाबाद में 32.68 और कन्नौज में 63.08 फ़ीसद बिजली चोरी हो रही है. बुंदेलखंड के झांसी में 43.33 फ़ीसद बिजली चोरी हो रही है. जबकि ललितपुर में 55.55, हमीरपुर में 26.44, जालौन में 60.34, महोबा में 50.15, बांदा में 32.76 और चित्रकूट में 48.59 फ़ीसद बिजली चोरी की जा रही है. हमीरपुर ज़िले के मौदहा में सबसे ज़्यादा 34 फ़ीसद बिजली चोरी हो रही है. पूरे उत्तर प्रदेश में 33.98 फ़ीसद लाइन लॉस का सीधा मतलब है कि बिजली चोर राज्य सरकार को हर महीने 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुक़सान पहुंचा रहे हैं.

बिजली का बिल न अदा करने पर छोटे–मोटे उपभोक्ताओं पर कहर बरपाने वाली सरकार बड़े–बड़े बकाएदारों से वसूली में नाकाम है. क़रीब डेढ़ सौ ऐसे बड़े बकाएदारों के नाम सरकार के समक्ष पेश हो चुके हैं, जिन पर क़रीब डेढ़ हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है. सरकार इनसे वसूली करने के बजाय इनके नाम छिपाने में अधिक रुचि लेती है. बड़े बकाएदारों की इस सूची में उद्योगपतियों, सरकारी संस्थानों, नेताओं, नौकरशाहों और न्यायाधीशों के नाम शामिल हैं. जो सरकारी संस्थान अपने यहां बिना अग्रिम भुगतान लिए घुसने तक नहीं देते, उन पर भी करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाया हैं. सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं उनके परिवारीजनों के नाम से संचालित होने वाली कंपनियों पर क़रीब 20 करोड़ रुपये की बकाएदारी है. कनेक्शन कटने के बाद भी उन्हें बिजली की आपूर्ति जारी है. बकाएदारों की सूची में लखनऊ स्थित ऐसे सरकारी भवन भी शामिल हैं, जो सीधे सरकार से जुड़े हैं. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि मध्यांचल के 170.10 करोड़, पश्चिमांचल के 567.54 करोड़, पूर्वांचल के 90.63 करोड़, दक्षिणांचल के 139.81 करोड़ और केस्को के 38.93 करोड़ रुपये बकाया हैं. लखनऊ स्थित विधायक निवास (दारुलशफा) पर डेढ़ करोड़, बहुमंजिला मंत्री आवास पर 1.49 करोड़, तीनों वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर लगभग चार करोड़, बहुमंजिला इंदिरा भवन पर 2.6 करोड़ और जवाहर भवन पर 1.69 करोड़ रुपये बकाया हैं. ■

चोरी की बिजली से सत्ता के घर रौशन

सत्ता के अलमबरदारों के राजनीतिक और पैतृक गढ़ों में बिजली चोरी सबसे अधिक है. यानी सत्ता के शीशे के घर चोरी की बिजली से रौशन हो रहे हैं. इस बिजली चोरी को सरकार लाइन लॉस की संज्ञा देती है. इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ जैसे ज़िलों में सबसे ज़्यादा लाइन लॉस है. प्रदेश के 16 ज़िलों में 50 फ़ीसद और 14 ज़िलों में 40 फ़ीसद से ज़्यादा लाइन लॉस है. रामपुर, संभल, शामली और जेपी नगर में 50 फ़ीसद से ज़्यादा लाइन लॉस दर्ज किया जा रहा है. मैनपुरी बिजली चोरी में अव्वल है. कन्नौज दूसरे, इटावा तीसरे और फिरोजाबाद चौथे स्थान पर है. सत्ता और सपा प्रमुख के गृह क्षेत्र इटावा का वितरण खंड–दो पूरे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी 58 फ़ीसद तक बिजली चोरी कर रहा है. आंकड़े बताते हैं कि दक्षिणांचल क्षेत्र में आगरा के बाद सबसे ज़्यादा बिजली इटावा को ही दी गई, लेकिन बिल सबसे कम वसूला जा सका.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

पद्म अवॉर्ड को लेकर रामदेव की किरकिरी

राजकुमार शर्मा

योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा पद्म अवॉर्ड की घोषणा से पहले ही उसे लेने से इंकार करके मीडिया में छा जाने की कोशिश अब उनके गले की फांस बन गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि बाबा रामदेव झूठ बोलने और ढकोसला करने में माहिर हैं. उनका नाम पद्म अवॉर्ड की सूची में था ही नहीं, फिर भी इंकार का नाटक करके उन्होंने मीडिया में चर्चा पाने का प्रयास किया. कांग्रेस के दिल्ली दरबार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि रामदेव को बेनकाब करने की ज़िम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने बड़ी सोची–समझी रणनीति के तहत किशोर उपाध्याय को सौंपी है. उपाध्याय इन दिनों पूरी जोरदारी के साथ रामदेव की घेरेबंदी कर रहे हैं. काला धन के मुद्दे पर कांग्रेस रामदेव को आरएसएस का मुखौटा सिद्ध करना चाहती है.

मीडिया में यह ख़बर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चाहते हैं कि बाबा रामदेव को पद्म अवॉर्ड मिले. बस, यहीं पर रामदेव को प्रचार पाने का मौक़ा मिल गया. कहा गया कि सरकार रामदेव को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने पर विचार कर रही है. सूत न कपास, जुलाहे से गुत्थम–गुत्था वाली कहावत चरितार्थ करते हुए बाबा रामदेव ने कहना शुरू कर दिया कि वह महसूस करते हैं कि बतौर योगी उन्हें किसी पुरस्कार या सम्मान से दूर रहना चाहिए. ग़ौरतलब है कि बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ करोड़ों–अरबों का व्यापार करती है. रामदेव की पहचान अब एक उद्यमी संत के रूप में होती है. ऐसे में, बाबा रामदेव का यह कहना कि मुझे निस्वार्थ भाव से काम करने दिया जाए और सम्मान के लिए किसी अन्य योग्य शख्स को चुना जाए, हास्यास्पद लगता है. जानकार कहते हैं कि रामदेव की दृष्टि स्वयं को विश्व योग गुरु बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित है. इसलिए उन्होंने काला धन के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और नरेंद्र मोदी का गुणगान करते घूम रहे हैं.

किशोर उपाध्याय ने कहा कि अगर अगले तीस दिनों में बाबा रामदेव ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन देश में वापस लाने का वादा पूरा नहीं किया, तो प्रदेश कांग्रेस आंदोलन करेगी. उपाध्याय ने कहा कि बाबा रामदेव ने तालकटोरा स्टेडियम में यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए जनता से कहा था कि यदि उनकी मनचाही सरकार केंद्र में बनी, तो वह 30 दिनों में विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन वापस ले आएंगे. इसलिए कांग्रेस ने बीती 29 जनवरी को हरकी पैड़ी हरिद्वार में वादा निभाओ धरने के ज़रिये उन्हें जनता से किए गए वादे की याद दिलाई. कांग्रेस की मांग है कि रामदेव अपना वादा पूरा करें या फिर देश की जनता से माफी मांगें.

किशोर उपाध्याय ने कहा कि अगर अगले तीस दिनों में बाबा रामदेव ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन देश में वापस लाने का वादा पूरा नहीं किया, तो प्रदेश कांग्रेस आंदोलन करेगी. उपाध्याय ने कहा कि बाबा रामदेव ने तालकटोरा स्टेडियम में यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए जनता से कहा था कि यदि उनकी मनचाही सरकार केंद्र में बनी, तो वह 30 दिनों में विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन वापस ले आएंगे.

दूसरी ओर, हरिद्वार स्थित भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता स्वामी हठयोगी जी महाराज ने कहा कि बाबा रामदेव की कथनी और करनी में ज़मीन–आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि गाय का दूध शुद्ध कहकर उसे पचहत्तर से सौ रुपये किलो और गाय का घी शुद्ध बताकर बाज़ार भाव से सौ रुपये अधिक मूल्य पर बेचना जनता की जेब पर डाका नहीं है, तो क्या है? उन्होंने कहा कि पतंजलि पीठ में भर्ती मरीजों से पांच सितारा होटल का किराया वसूला जाता है. रामदेव पक्के व्यापारी हैं, उनमें योगी का कोई गुण नहीं दिखता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महादलितों की ताकत का पूरा फ़ायदा नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान में उठाया और 2010 के चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली. जो वोट बैंक पहले लालू प्रसाद के इशारे पर काम करता था, वह नीतीश कुमार के साथ हो गया. राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद के कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह भी रही. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बातों से ही हम अनुसूचित जाति की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. मांझी कहते हैं कि अनुसूचित जाति को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है. बिहार में डेढ़ करोड़ एससी हैं.

नीतीश और मांझी आमने-सामने

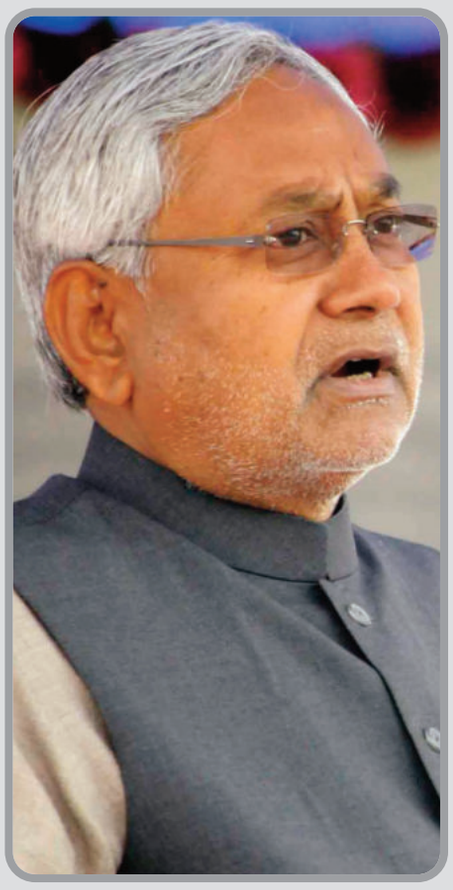

सरोज सिंह

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के साथ आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. अपनी बेबाक बयानबाजी से नीतीश कुमार को कई बार बैकफुट पर ला चुके जीतन राम मांझी ने इस बार उनकी सोशल इंजीनियरिंग में सेंध लगाकर सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है. अपनी लगभग नौ साल की सत्ता में नीतीश कुमार ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का ढिंढोरा पीटा, अब उसे मांझी ठीक नहीं बता रहे हैं. मांझी कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों को दलित और महादलित में नहीं बांटना चाहिए. पासवान जाति में भी ग़रीबी कम नहीं है, इसलिए उसे अलग रखना ग़लत है. महादलित आयोग एवं महादलित विकास मिशन से महादलित और दलित को एक करने की सिफारिश की बात भी मांझी कह रहे हैं. उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के ठीक बाद महादलित आयोग का गठन कर दलितों को दो भागों में बांटा था. पासवान को छोड़कर शेष 21 जातियों को महादलित में शामिल कर लिया गया. दलितों के इस बंटवारे का उस समय काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर कहा कि वह अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे.

महादलितों की ताकत का पूरा फ़ायदा नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान में उठाया और 2010 के चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली. जो वोट बैंक पहले लालू प्रसाद के इशारे पर काम करता था, वह नीतीश कुमार के साथ हो गया. राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद के कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह भी रही. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बातों से ही हम अनुसूचित जाति की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. मांझी कहते हैं कि अनुसूचित जाति को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है. बिहार में डेढ़ करोड़ एससी हैं. इस हिसाब से सवा करोड़ मतदाता इस समुदाय से हैं. सवा करोड़ मतदाता हमारे पास रहें, तो बिहार की राजनीति को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे. अगर हम सतर्क रहें, तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री भी कोई महादलित ही होगा. बिहार में 54 लाख मुसहर हैं. मुसहर अगर वोट की ताकत को समझ जाएं, तो वे सूबे की राजनीति को अकेले नियंत्रित कर सकते हैं. मांझी कहते हैं कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को शिक्षा के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा. जिनकी साक्षरता दर कम होगी, वे एक श्रेणी में होंगे. कहने का आशय यह कि जीतन राम मांझी अब दलितों की व्यापक गोलबंदी के अभियान में गंभीरता से लग गए हैं. पासवान जाति का अलग रहना उन्हें खल रहा था.

पिछली जनगणना के अनुसार, बिहार में पासवानों की संख्या 46 लाख 29 हज़ार 411 है. मांझी की सोच है कि महादलितों के साथ अब पासवान की गोलबंदी भी ज़रूरी है, ताकि अनुसूचित जाति की ताकत और भी धारदार बनाई जा सके. मांझी इसमें दोहरा फ़ायदा देख रहे हैं. पहला फ़ायदा यह है कि नीतीश कुमार से खफा पासवानों का एक बड़ा तबका उनके साथ हो सकता है. पिछले नौ सालों में पासवान बिरादरी सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकी. इसका गुस्सा उसमें बरकरार है. दूसरा फ़ायदा यह हो सकता है कि अपने इस सधे हुए क़दम से वह राम विलास पासवान की ताकत भी कुछ कम कर सकते हैं. मांझी के इस क़दम का भाजपा ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है. सुशील मोदी कहते हैं कि वह मांझी के इस क़दम का दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. रालोसपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तो अनर्थ कर दिया था. दलितों का बंटवारा करके उन्होंने अन्याय किया था. अब मांझी की घोषणा से साफ़ हो गया है कि हमारी मांग सही थी. पासवान बिरादरी का पिछले नौ सालों तक जो हक़ नीतीश कुमार ने छीना है, उसका दंड वोट के तौर पर पासवान समाज नीतीश कुमार को देगा.

ललन पासवान का दावा है कि पूरा पासवान समाज एनडीए के पक्ष में गोलबंद है और हमारी पार्टी के प्रति उसका भारी समर्थन है. राजनीतिक दावों से अलग हटकर अगर हम लोग मांझी द्वारा दलित एवं महादलित के विलय की घोषणा की चुनावी राजनीति के फलाफल पर विचार करें, तो साफ़ हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई शिकार कर दिए. जानकार बताते हैं कि जीतन राम मांझी पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि वह नीतीश कुमार के नीतिगत निर्णयों से कोई छेड़छाड़ न करें, लेकिन दलितों को एकजुट करने के निर्णय से साफ़ हो गया है कि मांझी कोई भी दबाव सहने को तैयार नहीं हैं. महादलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उछाल कर उल्टे वह नीतीश कुमार पर ही दबाव बना रहे हैं. सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी उनका साथ दे रहे हैं. मंशा बहुत साफ़ है कि दलितों की गोलबंदी के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं, ताकि आगामी चुनाव में अपने हिसाब से गोटियां सेट की जा सकें. पूर्व विधान पार्षद एवं राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि दरअसल, मांझी की लड़ाई उच्च पिछड़ावाद के ख़िलाफ़ है. अगड़ी जातियों से उनका कोई मतभेद नहीं है. अगड़ी जाति के नेता और मंत्री तो मांझी के क़दमों की सराहना कर रहे हैं. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में जिस उच्च पिछड़ावाद को बढ़ावा दिया, उससे दलित और महादलित समुदाय का बड़ा तबका हाशिये पर चला गया. वास्तव में जीतन राम मांझी उन्हीं की आवाज़ बनकर उभरे हैं.

बकौल मणि, जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि ग़रीब के बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वह उन तबकों से सीधा संवाद करते हैं, जिनकी उपेक्षा लालू और नीतीश के कार्यकाल में हुई. लालू प्रसाद के कमजोर होने के बाद दलित तबके को लग रहा है कि जीतन राम मांझी ही उसकी भावनाओं को आवाज़ दे रहे हैं. अगर मांझी दलित और महादलित का विलय करा देते हैं, तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी. यही वजह है कि कोई भी दल या नेता अब मांझी को हल्के में नहीं ले रहा है. पासवान बिरादरी को मिलाने का पासा फेंककर मांझी ने अपनी ताकत और भी बढ़ा ली है. यह ताकत अब इतनी बड़ी हो गई है कि चुनावी गणित को उल्टा-सीधा कर सकती है. अब यह मानकर चला जा रहा है कि नीतीश खेमा मांझी पर जवाबी वार ज़रूर करेगा. देखना दिलचस्प होगा कि मांझी गुट उस हमले का जवाब कैसे देता है. उधर, मांझी के इस क़दम से पासवान खेमे में बेचैनी है. अभी तक यह माना जा रहा था कि लगभग छह फ़ीसद आबादी वाली यह बिरादरी राम विलास पासवान के इशारे को ही समझती है, लेकिन मांझी के मास्टर स्ट्रोक ने इस गणित को उलझा कर रख दिया है. ■

ललन पासवान का दावा है कि पूरा पासवान समाज एनडीए के पक्ष में गोलबंद है और हमारी पार्टी के प्रति उसका भारी समर्थन है. राजनीतिक दावों से अलग हटकर अगर हम लोग मांझी द्वारा दलित एवं महादलित के विलय की घोषणा की चुनावी राजनीति के फलाफल पर विचार करें, तो साफ़ हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई शिकार कर दिए. जानकार बताते हैं कि जीतन राम मांझी पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि वह नीतीश कुमार के नीतिगत निर्णयों से कोई छेड़छाड़ न करें, लेकिन दलितों को एकजुट करने के निर्णय से साफ़ हो गया है कि मांझी कोई भी दबाव सहने को तैयार नहीं हैं. महादलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उछाल कर उल्टे वह नीतीश कुमार पर ही दबाव बना रहे हैं. सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी उनका साथ दे रहे हैं. मंशा बहुत साफ़ है कि दलितों की गोलबंदी के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं, ताकि आगामी चुनाव में अपने हिसाब से गोटियां सेट की जा सकें. पूर्व विधान पार्षद एवं राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि दरअसल, मांझी की लड़ाई उच्च पिछड़ावाद के ख़िलाफ़ है.

feedback@chauthiduniya.com

कमल मोरारका

भाजपा को एक चेहरे की ज़रूरत थी. अगर मैं भाजपा का हमदर्द होता, तो कहता कि ऐसा करना ग़लत है. आपके खुद के कई नेता हैं, उन्हें मौक़ा दीजिए. आपके पास विजय गोयल हैं. वह भले कोई करिश्माई नेता न हों, लेकिन वह पार्टी को लीड करें. हारें या जीतें, उन्हें मौक़ा दीजिए. अगर जीतते हैं, तो पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक मौक़ा मिलना चाहिए. आपने मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऐसा उम्मीदवार उधार ले लिया, जो पैसे पर युद्ध लड़ने वाले सैनिक की तरह है और जिसके भीतर कोई देशभक्ति नहीं है. एक ऐसा सैनिक, जो सिर्फ़ पावर और पैसे के लिए युद्ध लड़ता है. अगर वह मुख्यमंत्री बन भी जाती हैं, तो क्या कर पाएंगी? क्या वह आरएसएस या भाजपा के आइडिया में विश्वास रखती हैं या फिर सत्ता के लालच में आ गईं?

ओबामा की यात्रा अच्छी थी, सफल नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आए और चले गए. यह यात्रा दो कारणों से अभूतपूर्व थी. अपने कार्यकाल के दौरान दो बार भारत आने वाले वह पहले राष्ट्रपति हैं और इससे पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कभी नहीं आया था. इन दोनों घटनाओं का स्वागत है. हालांकि, इस यात्रा का मीडिया कवरेज और उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया-बताया गया. मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों एक अतिथि की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने के लिए मीडिया इतना समर्पित दिखा. हमारे प्रधानमंत्री की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है. जाहिर-सी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं, तो सुरक्षा तो होगी ही. वास्तव में इतना सब कुछ दिखाकर आप अपनी सुरक्षा लीक कर देते हैं और ग़लत लोगों को जानकारी देते हैं. मुझे लगता है कि प्रेस काउंसिल या अन्य किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इंतजाम तीन-चार घंटे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. मुख्य बात थी कि इस यात्रा से पहले परमाणु करार की बात हो रही थी. जो भी लोग इस डील से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है. लेकिन, मीडिया ने इस तरह बताया, मानों कोई महान उपलब्धि हासिल कर ली गई है.

राष्ट्रपति ओबामा अपने शब्दों को लेकर बहुत सावधान थे. उन्होंने कहा कि हमने आपसी समझ को बेहतर बनाने में सफलता पाई है. यह सही है. दूसरी बात, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्ष के प्रतिरोध के बावजूद यह डील करना चाहते थे. उन्होंने इसके लिए कुछ सवालिया तरीके (सांसदों का समर्थन हासिल करने के मामले में) अपनाए, लेकिन उन्होंने संसद में यह डील पारित की. मुझे याद है कि कैसे संसद के भीतर यशवंत सिन्हा ने इसका जोरदार विरोध किया था और ऐसी बातों का जिक्र किया था, जिनसे भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को उन चिंताओं को लेकर आश्वस्त किया था. हम जैसे लोगों को लगा कि यह डील नहीं हो सकती, क्योंकि जो शर्तें थीं, वे अमेरिका नहीं मानता और भारत उनसे पीछे नहीं हट सकता था. अब क्या हुआ? मैं आश्वस्त हूं कि अमेरिकी सरकार जो चाहती है, उससे पीछे नहीं जा सकती और आप उससे पीछे नहीं हट सकते, जिसका वादा संसद से कर चुके हैं. इसलिए आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं. यह बीच का रास्ता है कि जो ज़िम्मेदारी अमेरिकी कंपनी नहीं स्वीकार रही है, उसे भारतीय बीमा कंपनियों और सरकार को सौंप दिया गया.

यह किस तरह का सौदा (डील) है? हम मूर्ख हैं, यदि यह सोचते हैं कि इस डील से हम कुछ हासिल कर लेंगे. अगर परमाणु करार के पक्ष में खड़े लोगों के मुताबिक यह डील हो जाती है, तब भी देश की बिजली की आवश्यकताओं का केवल सात से आठ फ़ीसद हिस्सा ही इससे पूरा हो पाएगा. अगर यह सात-आठ फ़ीसद परमाणु ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हम बिजली के बिना मर नहीं जाएंगे. तथाकथित स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा सिर्फ़ सात से आठ फ़ीसद ही है. इसलिए परमाणु करार बिजली की ज़रूरत को पूरा नहीं करता. यह भारतीय एवं अमेरिकी कंपनियों को बहुत सारा पैसा खर्च करने और कमाने में मदद करता है. एक भारतीय कंपनी लार्सन टुब्रो ने पहले से ही जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह के बीच हुए नाभिकीय सौदे के वक्त एक बड़ा निवेश कर दिया था. आज तक वह पैसा यूं ही पड़ा हुआ है. उसे उम्मीद है कि कुछ होगा. अमेरिकी कंपनियों से भारतीय कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे. कुल मिलाकर यह एक कॉरपोरेट डील है.

इस कॉरपोरेट सौदे के लिए एक संप्रभु सरकार कहां तक जाती है, यह एक बड़ा सवाल है. जो भाजपा कल तक इसका विरोध करती थी, आज वह इसे आगे ले जाना चाहती है. यह तो कहिए कि कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया और उसके प्रवक्ता ने कहा कि इसे हमने ही शुरू किया था, इसलिए इसका विरोध नहीं करेंगे. इसके अलावा, ओबामा की यात्रा से और कुछ बाहर निकल कर नहीं आया है. मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा कि किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका से कोई सेंटा क्लाज आएगा और सबके लिए गिफ्ट लाएगा. यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि ओबामा हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने, दूसरी बार भारत आए. बस इतना ही. इससे अधिक कुछ नहीं. मोदी सरकार के दौरान अन्य मेहमान भी आ चुके हैं और अभी कई आएंगे भी. नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से नेटवर्क स्थापित करके बहुत शानदार काम किया है. लेकिन, हमेशा इसे इस रूप में देखना कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, यह पुराने दिनों की निर्भरता वाली बात है. अब अंतर-आत्मनिर्भरता का दौर है. आज अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, हमें अमेरिका की ज़रूरत है. उसी तरह जापान को हमारी और हमें जापान की ज़रूरत है. इसलिए सार्वजनिक जीवन में या मीडिया के लोगों का खुद को

> राष्ट्रपति ओबामा अपने शब्दों को लेकर बहुत सावधान थे. उन्होंने कहा कि हमने आपसी समझ को बेहतर बनाने में सफलता पाई है. यह सही है. दूसरी बात, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्ष के प्रतिरोध के बावजूद यह डील करना चाहते थे. उन्होंने इसके लिए कुछ सवालिया तरीके (सांसदों का समर्थन हासिल करने के मामले में) अपनाए, लेकिन उन्होंने संसद में यह डील पारित की.

नीचा देखने-दिखाने वाला रवैया बहुत दु:खद है. वैसे, कुल मिलाकर यह एक अच्छी यात्रा थी, लेकिन इसे सफल कहना मूर्खतापूर्ण होगा.

दूसरी अहम बात. दिल्ली में विधानसभा चुनाव है. इसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं. दिल्ली एक राज्य भी नहीं है, यह एक संघ राज्य क्षेत्र है. किसी को क्या फ़र्क़ पड़ता है कि यहां कौन जीतता है, क्या होता है? दिल्ली सरकार के अधीन क़ानून और व्यवस्था नहीं है, भू-उपयोग का अधिकार नहीं है. इस पर आख़िर इतना हो-हल्ला क्यों? क्योंकि, यह राजधानी है. भाजपा को अब लग रहा है कि आम चुनाव के बाद तुरंत चुनाव करा देना चाहिए था. मोदी लहर में आसानी से जीत मिल जाती. अब वह मौक़ा हाथ से निकल चुका है. तब तो वह दलबदल को प्रोत्साहित करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी. ऐसा हुआ नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भाजपा ने चुनाव कराने का निर्णय लिया. अब एक बार फिर जब उसे यह महसूस हुआ कि वह जीत नहीं सकती, तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी को सामने लेकर आ गई. एक ऐसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस सेवा में तो सफल नहीं हुई. हां, उनके दो दावे हैं. एक यह कि वह देश की पहली महिला आईपीएस हैं और दूसरा यह कि उन्हें फिलीपींस जैसे देश से रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिला हुआ है और वह भी पुलिस सेवा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के लिए. इस सबसे वह कैसे मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो गईं? लेकिन, मीडिया में उनकी एक छवि है और उन्हें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके साथ रहकर उन्हें इस दौड़ में शामिल होने का मौक़ा मिल गया.

भाजपा को एक चेहरे की ज़रूरत थी. अगर मैं भाजपा का हमदर्द होता, तो कहता कि ऐसा करना ग़लत है. आपके खुद के कई नेता हैं, उन्हें मौक़ा दीजिए. आपके पास विजय गोयल हैं. वह भले कोई करिश्माई नेता न हों, लेकिन वह पार्टी को लीड करें. हारें या जीतें, उन्हें मौक़ा दीजिए. अगर जीतते हैं, तो पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक मौक़ा मिलना चाहिए. आपने मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऐसा उम्मीदवार उधार ले लिया, जो पैसे पर युद्ध लड़ने वाले सैनिक की तरह है और जिसके भीतर कोई देशभक्ति नहीं है. एक ऐसा सैनिक, जो सिर्फ़ पावर और पैसे के लिए युद्ध लड़ता है. अगर वह मुख्यमंत्री बन भी जाती हैं, तो क्या कर पाएंगी? क्या वह आरएसएस या भाजपा के आइडिया में विश्वास रखती हैं या फिर सत्ता के लालच में आ गईं? इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप एक राजनीतिक दल हैं. लेकिन, कांग्रेस का नाम लेना बंद करें. यह कहना बंद करें कि कांग्रेस सिर्फ़ सत्ता चाहती है. यह कहना बंद करें कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए. मुझे कोई शिकायत नहीं है. मैं राजनीतिक दल में विश्वास रखता हूं, मैं बराबर की प्रतिस्पर्द्धा में विश्वास रखता हूं, लेकिन यह मत कहिए कि हम एक अलग पार्टी हैं. यह सब बेकार की बातें हैं. इसलिए यह मत कहिए कि हमने किरण बेदी को लाकर कोई बड़ा काम कर दिया. उनकी विचारधारा, उनका आदर्श, उनका विजन क्या है, हमें नहीं मालूम. और, इसी सबके लिए वे अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हैं. यह कहते हैं कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, वह सिर्फ़ बिजली-पानी के दाम कम करने की बात कहते हैं. लेकिन, आम आदमी इन बातों को अपने लाभ के रूप में देखता है. आम आदमी सोचता है कि वह केवल बड़ी बातें नहीं करते.

क्या भाजपा ऐसा वादा कर रही है? क्या किरण बेदी ने अपनी कोई सूची बनाई है कि वह क्या-क्या करेंगी? केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को उनके अधीन नहीं करेगी. क्या इसके बिना वह बलात्कार की घटनाएं रोक लेंगी? मेरे हिसाब से दिल्ली चुनाव एक मज़ाक बनकर रह गया है. कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा. फिर भी देखते हैं कि नतीजा क्या रहता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

दिल्ली जितनी परिवार (संघ) की अंदरूनी लड़ाई के लिए अहम है, उतनी ही अहम आप और भाजपा के बीच की लड़ाई है. अगर साक्षी महाराज, घर वापसी और रामजादे के रहते भाजपा अपनी पिछली कामयाबी दोहराती है, तो वह भाग्यशाली होगी. संघ परिवार को अल्पसंख्यकों से नफरत हो सकती है, लेकिन उनके वोट चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, जैसा कि हमने जम्मू-कश्मीर में देखा, जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने से वंचित रह गई.

अभी दिल्ली दूर है...

रजनी कोठारी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले समाजशास्त्री थे. यह रजनी कोठारी ही थे, जिन्होंने हमें पश्चिमी विचारधारा के बजाय भारतीय वास्तविकताओं के आधार पर अपनी राजनीति को परखने का तरीका सिखाया. उनके विचार में कांग्रेस तंत्र एक सर्व-समावेशी और अखिल भारतीय तंत्र था, जिसने यह साबित किया कि अंग्रेजी भाषी वर्ग के खोखले अलंकृत विचारों के अतिरिक्त भी भारत की वास्तविक राजनीति को समझने और उस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है. कांग्रेस तंत्र की रुचि विभिन्न जातीय एवं क्षेत्रीय समूहों को पार्टी में शामिल करने में थी. हालांकि, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की विचारधाराएं स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन पार्टी यह चाहती थी कि उक्त समूह उसकी हिमायत करें. बहरहाल, वर्ष 1947 एवं 1969 के दौरान कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाए रखा और वह भारत को एक खुला एवं साहिष्णु लोकतंत्र देने में कामयाब रही, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी को फलने-फूलने का भरपूर मौक़ा मिला. लेकिन कांग्रेस के इस तंत्र को उस समय झटका लगा, जब इंदिरा गांधी ने पार्टी को विभाजित कर दिया. अब हमारे सामने पार्टी के बजाय एक पारिवारिक व्यवसाय था, जहां सबसे ऊंचा पद केवल बेटे या बेटी को ही मिल सकता था और चाटुकारिता एकमात्र विचारधारा बन गई थी. अब यह तंत्र समाप्त हो गया है. इसके बारे में अब हमें सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है.

वर्तमान में एक नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है और इस व्यवस्था का जन्म शायद दिल्ली में हो. किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने पर बहुत सारी सतही टिप्पणियां की गईं. लोगों को शायद यह नज़र नहीं आ रहा है कि 1969 में कांग्रेस तंत्र के टूटने के बाद जन आंदोलनों से कई नई ताक़तें राजनीति में आई थीं, जिन्होंने उस तंत्र को चुनौती दी थी. जेपी आंदोलन की वजह से जनता (परिवार) पार्टी वजूद में आई थी. इस पार्टी में बिखराव ने अनगिनत पार्टियों को जन्म दिया था, जिनमें से कुछ का आज की राजनीति के अधिकतर हिस्से पर क़ब्ज़ा है. आज की भाजपा ने खुद को जनसंघ से जनता पार्टी में बदल दिया, वही हाल जनता दल के विभिन्न धड़ों का था, जो अभी पूरे जोश से एक होने की कोशिश कर रहे हैं. अगला जन आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ. इस आंदोलन के परिणाम जेपी आंदोलन की तरह आश्चर्यजनक नहीं थे, लेकिन इसने जो दीया जलाया था, उसमें अभी रौशनी बाकी है. अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी इसी आंदोलन की उपज हैं, लेकिन अब वे दो अलग-अलग पार्टियों का हिस्सा हैं, जो अनावश्यक बयानबाज़ी का कारण बन रही हैं. अब जबकि कांग्रेस की खानदानी दुकान बंद हो गई है, इसलिए अब नए नेता केवल जन आंदोलनों से ही आ सकते हैं. ये आंदोलन एक व्यापक गठजोड़ होते हैं, जिनमें कोई एक विचारधारा नहीं होती. केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ही कार्यकर्ता और काम करने में यकीन रखने वाले शख्स हैं. वे मौजूदा शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं और उन पर विचारधारा बाहरी लेप ही नज़र आती है. वे केवल सत्ता में रहते हुए ही प्रभावी रह सकते हैं.

आज से 13 महीने पहले दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के अच्छे प्रदर्शन ने देश को स्तब्ध कर दिया था. मीडिया ने इसे बहुत कवरेज दिया. मध्यम वर्ग, जो कांग्रेस से आहत था और भाजपा के बारे में अनिश्चित, उसने सोचा कि केजरीवाल के रूप में उसका बेड़ा पार करने वाला मिल गया. लेकिन अफ़सोस, जनता के स्नेह ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को घमंडी बना दिया. उन्होंने एक विपक्षी पार्टी की तरह व्यवहार करते हुए सत्ता छोड़ दी और आम चुनाव में पूरे देश में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए. इसी दौरान एक अधिक अनुभवी मुख्यमंत्री ने भाजपा को केंद्र में रखते और सबका विकास का नारा देते हुए चुनावी राजनीति के नक्शे को पुन: रेखांकित करना शुरू किया था. उसने मध्य वर्ग को आश्वस्त किया और ग़रीबों को उसमें आशा की किरण नज़र आई. उसने अपनी पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाया. उसने बड़ी उम्मीदें जगाई हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए उसे चौबीसों घंटे काम करना पड़ रहा है. जैसे-जैसे उसकी पार्टी एक के बाद एक राज्य में चुनाव जीत रही है, वैसे-वैसे उसका परिवार (संघ) उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है. विकास और बेहतर शासन व्यवस्था के बजाय परिवार अल्पसंख्यकों से संबंधित अपने पागलपन और प्राचीन भारत के इतिहास में उलझा रहेगा.

> वर्तमान में एक नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है और इस व्यवस्था का जन्म शायद दिल्ली में हो. किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने पर बहुत सारी सतही टिप्पणियां की गईं. लोगों को शायद यह नज़र नहीं आ रहा है कि 1969 में कांग्रेस तंत्र के टूटने के बाद जन आंदोलनों से कई नई ताक़तें राजनीति में आई थीं, जिन्होंने उस तंत्र को चुनौती दी थी.

दिल्ली जितनी परिवार (संघ) की अंदरूनी लड़ाई के लिए अहम है, उतनी ही अहम आप और भाजपा के बीच की लड़ाई है. अगर साक्षी महाराज, घर वापसी और रामजादे के रहते भाजपा अपनी पिछली कामयाबी दोहराती है, तो वह भाग्यशाली होगी. संघ परिवार को अल्पसंख्यकों से नफरत हो सकती है, लेकिन उनके वोट चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, जैसा कि हमने जम्मू-कश्मीर में देखा, जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने से वंचित रह गई. ऐसे में किरण बेदी का पार्टी में शामिल होना महत्वपूर्ण है. इससे साबित होता है कि भाजपा काम करने वाली पार्टी है, न कि उपद्रव करने वालों की पार्टी है. भाजपा भी कांग्रेस की तरह एक व्यापक तंत्र बनने की इच्छा रखती है और इसके लिए उसे दिल्ली का चुनाव प्रभावकारी तौर पर जीतना होगा. अब सवाल है कि क्या यह संभव है? ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, मोईन जैसे लोगों से देश को बचाइए

> जी बिजनेस एक फॉलोअप सीरीज चला रहा है. इसमें मोईन कुरैशी को लेकर दो एपिसोड किए गए और दोनों एपिसोड यह बताते हैं कि देश का पूरा अर्थतंत्र उन लोगों के आगे-पीछे घूम रहा है, जिनका अर्थतंत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अर्थतंत्र को नष्ट करने के ज़िम्मेदार हैं. इनमें हवाला व्यापारी हैं, अधिकारी हैं और कुछ राजनेता भी हैं. मुरादाबाद के हवाला व्यापारी मोईन कुरैशी के यहां छापे पड़ चुके हैं. उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन उसका संबंध भारत के सीबीआई डायरेक्टर रहे रंजीत सिन्हा से रहा. सिन्हा के यहां से जो रजिस्टर बाहर आया, उसमें उसका नाम था. उसका संबंध वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से रहा और इन सारी चीजों को जी बिजनेस हिम्मत के साथ लगातार दिखा रहा है. मेरा सवाल था कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तत्कालीन आईबी डायरेक्टर ने इस तरह अर्थतंत्र को खोखला करने वाला जाल कौन चला रहा है, इसकी जानकारी दी या नहीं दी? जीवीएल नरसिम्हा राव का जवाब था, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार को जानकारी है, सरकार के विभिन्न अंग यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं.

28 जनवरी की शाम देश के लोकप्रिय बिजनेस चैनल जी बिजनेस के ऊपर बिग डिबेट हो रहा था और इस डिबेट का विषय था, मोईन कुरैशी का खुलासा. जी बिजनेस एक फॉलोअप सीरीज चला रहा है. इसमें मोईन कुरैशी को लेकर दो एपिसोड किए गए और दोनों एपिसोड यह बताते हैं कि देश का पूरा अर्थतंत्र उन लोगों के आगे-पीछे घूम रहा है, जिनका अर्थतंत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अर्थतंत्र को नष्ट करने के ज़िम्मेदार हैं. इनमें हवाला व्यापारी हैं, अधिकारी हैं और कुछ राजनेता भी हैं. मुरादाबाद के हवाला व्यापारी मोईन कुरैशी के यहां छापे पड़ चुके हैं. उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन उसका संबंध भारत के सीबीआई डायरेक्टर रहे रंजीत सिन्हा से रहा. सिन्हा के यहां से जो रजिस्टर बाहर आया, उसमें उसका नाम था. उसका संबंध वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से रहा और इन सारी चीजों को जी बिजनेस हिम्मत के साथ लगातार दिखा रहा है.

पिछले एपिसोड में, जो लगभग 20 दिन पहले हुआ, मैंने यह सवाल पूछा और यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव से था कि जितना मैं सरकार के काम करने के तरीके को जानता हूं, अगर कोई आदमी खुफिया विभाग के लोगों से, सीबीआई के लोगों से, वित्त मंत्रालय के लोगों से, राजनीतिक लोगों से सीधा रिश्ता रखता है, तो उसकी जानकारी आईबी के पास होती है और जब इस पैमाने पर देश को खोखला करने वाले क्रियाकलाप हो रहे हों, तो उनके बारे में किसी समय आईबी डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री को जानकारी ज़रूर दी होगी, क्योंकि प्रत्येक रात 10 बजे के आस-पास हर क़ीमत पर आईबी के डायरेक्टर को प्रधानमंत्री के पास जाना होता है और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती हैं.

मेरा सवाल था कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तत्कालीन आईबी डायरेक्टर ने इस तरह अर्थतंत्र को खोखला करने वाला जाल कौन चला रहा है, इसकी जानकारी दी या नहीं दी? जीवीएल नरसिम्हा राव का जवाब था, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार को जानकारी है, सरकार के विभिन्न अंग यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं. मैंने उनकी बात को सत्य मान लिया और तब मैंने उसी बहस में कहा कि यह इतना बड़ा मसला है, जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस देश के जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, जिनमें हथियारों की लॉबी है, जिनमें हवाला लॉबी है, जिनमें अंडरवर्ल्ड है और जिनमें वे राजनेता हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में नहीं, बल्कि खोखला करने में जुटे हुए हैं. इस नेक्सस के ख़िलाफ़ फौरन निगरानी ही नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और उस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा विषय निगरानी करने का कोई और हो नहीं सकता. इस पर जीवीएल नरसिम्हा राव का जवाब था कि हर चीज में हम सुप्रीम कोर्ट को क्यों लाते हैं. हमें तो सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए. हमने जीवीएल नरसिम्हा राव का उस समय विश्वास कर लिया.

28 जनवरी की शाम मोईन कुरैशी को लेकर जी बिजनेस ने तीसरा खुलासा किया. खुलासा करने वाले जी बिजनेस के संपादक अमीष देवगन थे, जिन्होंने पिछले दो खुलासे किए थे. इस तीसरे खुलासे में उन्होंने इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल रहे रोनाल्ड के नोबेल से मोईन कुरैशी का रिश्ता स्थापित किया और यह साबित किया कि जिस समय 9/11 को अमेरिका में ट्विन टॉवर के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उस समय भी यह सज्जन इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल थे. अमीष देवगन के खुलासे में नोबेल ने ई-मेल के ज़रिये दिए गए जवाब में माना कि वह मोईन कुरैशी से उपहार लेते थे और उसे उपहार देते भी थे. सवाल यह है कि मोईन कुरैशी नामक यह सज्जन हिंदुस्तान के ऐसे सर्वाधिक ताकतवर लोगों में हैं, जिनका सीबीआई के डायरेक्टर से भी रिश्ता है, जिनका मंत्रियों से भी रिश्ता है, जिनका वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी रिश्ता है और जिनका इंटरपोल से भी रिश्ता है.

पैनल में कई सारे लोग थे. मैंने इस सारी घटना का विश्लेषण किया. मैंने यह कहा कि यदि मनमोहन सिंह के समय मनमोहन सिंह के पास जानकारी थी, उनके अधिकारियों के पास जानकारी थी और फिर उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, तो क्या यह न माना जाए कि उन सारे लोगों की संलिप्तता देश विरोधी कामों में है? तब आज, जबकि इतने बड़े तीन खुलासे हो चुके हों और उन तीन खुलासों के बाद भी सरकार न जागे और कोई कार्रवाई न करे, तो इसे क्या माना जाए? क्या इसे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा की गई अनदेखी नहीं मानना चाहिए? मेरी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि जीवीएल नरसिम्हा राव को लगा कि मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इसमें शामिल कर रहा हूं. हालांकि, उन्हें उस समय बहुत अच्छा लगा था, जब मैंने मनमोहन सिंह की बात कही थी. लेकिन, उन्होंने बिना विश्लेषण का मर्म समझे मेरी बात को बकवास करार दे दिया. इसके पहले जीवी एल नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल अंजान ने कहा कि सीबीआई इंटरपोल का हिस्सा है और सीबीआई को एक पत्र लिखना चाहिए. सभी लोगों ने, जिनमें जयंत घोषाल, कमाल फारुकी शामिल थे, इसका समर्थन किया था. मैं यह कहना चाहता था कि जीवीएल नरसिम्हा राव अगर टेलीविजन पर आए हैं और अगर इतने महत्वपूर्ण मसले पर आए हैं, तो उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कॉमा-फुलस्टॉप वही कहा था, जो उन्होंने इस बार कहा है. उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई कि सरकार इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी, बल्कि उन्होंने यह कह दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार को यह-यह कार्रवाई करनी चाहिए. इसका मतलब कि मोईन कुरैशी का मसला, जिसका रिश्ता इतने सारे लोगों से है और जो अपराध में पकड़ा जा चुका है, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उसके साथ अगर भारत सरकार के लोगों का रिश्ता रहता है, तो क्या यह इस सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है.

जीवीएल नरसिम्हा राव आपे से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि आप बकवास कर रहे हैं. आप इस बात को वापस लीजिए, नहीं तो मैं चैनल पर नहीं आऊंगा. मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इसमें कौन-सी बकवास की है. जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और उस टीम के सदस्य हैं, जिसके मुखिया देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं. इसका मतलब यह कि सारे सवाल पत्रकार उठाता रहे, दूसरे शब्दों में जी बिजनेस सवाल उठाता रहे और सरकार कोई कार्रवाई न करे. इसे क्या माना जाए? सरकारी कार्रवाई का एक तरीका यह हो सकता है कि वह जी बिजनेस से कहे कि जी बिजनेस उसे सारे तथ्य दे. और, अगर तथ्य ग़लत साबित हुए, तो वह जी बिजनेस के ऊपर कार्रवाई करे या उसके संपादक अमीष देवगन के ऊपर कार्रवाई करे. लेकिन अगर तथ्य सही हुए, तो इस देश को खोखला करने वाले एक बड़े षड्यंत्र की जांच होगी और देश सुधरेगा.

जीवीएल नरसिम्हा राव यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं. इसलिए आप यह बात कह रहे हैं. अब मुझे लगा कि जीवी एल नरसिम्हा राव मुझे आम आदमी पार्टी का सदस्य बता रहे हैं. इसका मतलब है कि वह बेशर्म हैं और बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं और यही मैंने टेलीविजन पर कहा. मैंने कहा कि मैं न बात वापस लूंगा और आप बेशर्मी कर रहे हैं. कहना तो मैं यह चाहता था कि अगर मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं, तो साबित करें. यदि साबित करते हैं, तो मैं पत्रकारिता छोड़ देता हूं, वर्ना वह राजनीति छोड़ दें. किसी पत्रकार को किसी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है.

मैं यह बात इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उस पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि पार्टी के लोग ही अपराधियों के अपराध को अनदेखा करने का अपराध करें. हमारे देश के लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उठता जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण सीबीआई है, जिसके डायरेक्टर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां आई हैं. और, अब जबकि इतने बड़े खुलासे हो रहे हों और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यह कहे कि यह सब तो कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा, तब कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इसका मतलब यह निकलता है कि कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए आप भी कार्रवाई नहीं करेंगे. इसका दूसरा मतलब यह होता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में पूरे अर्थतंत्र को तबाह करने की साजिश की और वहां अपने-अपने लोग चुने, जिन्हें उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, क्या वही काम वे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं कर रहे हैं? यह निष्कर्ष निकालना आसान है.

मैं विनम्रता के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह दायित्व है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास फिर कायम करें. मैं यह नहीं मानता कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं. वे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं. यह उनका दायित्व है कि वे मोईन कुरैशी जैसी घटना को एक व्यक्तिगत घटना न बताएं. जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि मोईन कुरैशी के ऊपर कार्रवाई चल रही है. यह ग़लत नज़रिया है. सही नज़रिया यह है कि मोईन कुरैशी के ऊपर कार्रवाई चल रही थी. लेकिन, मोईन कुरैशी के संबंध जैसे ही सीबीआई डायरेक्टर, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ मंत्रियों, कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के साथ उजागर हुए और अब इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल के साथ उसके संबंध उजागर हुए, उसे देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ बात करके तत्काल गंभीर जांच बैठानी चाहिए और यह जांच तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि यह दीमक है, जो भारतीय अर्थतंत्र में लग चुकी है.

> जीवीएल नरसिम्हा राव को अपनी ग़लती का एहसास हुआ होगा. अगर उन्हें एहसास नहीं हुआ है, तो उन्हें एहसास कर लेना चाहिए कि अगर वह टेलीविजन पर आकर इस तरह की ग़ैर ज़िम्मेदाराना बात करेंगे, तो उन्हें टेलीविजन पर नहीं आना चाहिए. वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक अभिशाप बन जाएंगे. जितनी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सुधारने की कर रहे हैं, उसमें अपनी अज्ञानता से पलीता लगाने का काम जीवीएल नरसिम्हा राव जैसे लोग करेंगे. तथ्य रखना ही हमारा फर्ज है, हमारा पेशा है. किसी को बचाना हमारा पेशा नहीं है. किसी को कवर करना हमारा कर्तव्य नहीं है. हमारा कर्तव्य है कि जहां पर भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ियां हों, घुन लगा हो, दीमक लगी हुई हो, उसे उजागर करना है. इसलिए अब फिर से, प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि कृपा करके अपने व्यस्त समय में से आधा घंटा इस केस के ऊपर भी दीजिए और देखिए कि मोईन कुरैशी जैसे लोगों ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के किन-किन लोगों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा है और उनके साथ मिलकर वह देश में आख़िर कर क्या रहे हैं?

मैं यह विश्वास करता हूं कि जीवीएल नरसिम्हा राव को अपनी ग़लती का एहसास हुआ होगा. अगर उन्हें एहसास नहीं हुआ है, तो उन्हें एहसास कर लेना चाहिए कि अगर वह टेलीविजन पर आकर इस तरह की ग़ैर ज़िम्मेदाराना बात करेंगे, तो उन्हें टेलीविजन पर नहीं आना चाहिए. वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक अभिशाप बन जाएंगे. जितनी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सुधारने की कर रहे हैं, उसमें अपनी अज्ञानता से पलीता लगाने का काम जीवीएल नरसिम्हा राव जैसे लोग करेंगे.

मैं एक तथ्य सामने रख रहा हूं. जीवीएल नरसिम्हा राव से कहना चाहता हूं कि तथ्य रखना ही हमारा फर्ज है, हमारा पेशा है. किसी को बचाना हमारा पेशा नहीं है. किसी को कवर करना हमारा कर्तव्य नहीं है. हमारा कर्तव्य है कि जहां पर भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ियां हों, घुन लगा हो, दीमक लगी हुई हो, उसे उजागर करना है. इसलिए अब फिर से, प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि कृपा करके अपने व्यस्त समय में से आधा घंटा इस केस के ऊपर भी दीजिए और देखिए कि मोईन कुरैशी जैसे लोगों ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के किन-किन लोगों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा है और उनके साथ मिलकर वह देश में आख़िर कर क्या रहे हैं? मोदी जी, सुनने और समझने की कोशिश कीजिए. आप अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते हैं. आशा है, आप इस पर ध्यान देंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

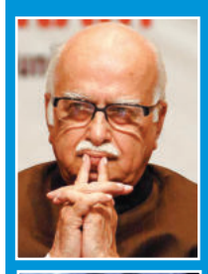

इस वर्ष तीनों श्रेणियों–पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए कुल 104 शख्सियतों का चयन किया गया, जिनमें 15 महिलाएं शामिल हैं. 17 विदेशी नागरिकों को भी पद्म सम्मान मिला.

104 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार

पद्म विभूषण

1. लालकृष्ण आडवाणी, सार्वजनिक मामले, गुजरात.
2. अमिताभ बच्चन, कला, महाराष्ट्र
3. प्रकाश सिंह बादल, सार्वजनिक मामले, पंजाब.
4. डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े, समाजसेवा, कर्नाटक.
5. मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, कला, महाराष्ट्र.
6. जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, अन्य, उत्तर प्रदेश.
7. प्रो. मलुर रामास्वामी श्रीनिवासन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, तमिलनाडु.
8. के. लालकृष्ण वेणुगोपाल, सार्वजनिक मामले, दिल्ली.
9. करीम अल हुसैनी आगा खान (विदेशी), व्यापार एवं उद्योग, फ्रांस/ब्रिटेन.

पद्म भूषण

1. जाहनु बरुआ, कला, असम.
2. डॉ. विजय भाटकर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र.
3. स्वप्न दासगुप्ता, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
4. स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि, अन्य, उत्तर प्रदेश.
5. एन. गोपालस्वामी, सिविल सेवा, तमिलनाडु.
6. डॉ. सुभाष सी. कश्यप, सार्वजनिक मामले, दिल्ली.
7. डॉ. (पंडित) गोकुलोत्सव जी महाराज, कला, मध्य प्रदेश.
8. डॉ. अंबरीश मित्तल, चिकित्सा, दिल्ली.
9. सुधा रघुनाथन, कला, तमिलनाडु.
10 हरीश साल्वे, सार्वजनिक मामले, दिल्ली.
11. डॉ. अशोक सेठ, चिकित्सा, दिल्ली.
12. रजत शर्मा, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
13. सतपाल, खेल, दिल्ली.
14. शिवकुमारा स्वामी, अन्य, कर्नाटक.
15. डॉ. खड्ग सिंह वल्दिया, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कर्नाटक.
16. प्रो मंजुल भार्गव (एनआरआई/पीआईओ), विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, अमेरिका.
17. वामदेव शास्त्री (विदेशी), अन्य, अमेरिका.
18. बिल गेट्स (विदेशी), समाजसेवा, अमेरिका.
19. मिलिंडा गेट्स (विदेशी), समाजसेवा, अमेरिका.
20. साइचिरो मिसुमी (विदेशी), अन्य, जापान.

पद्मश्री

1. डॉ. मंजुला अनागनी, चिकित्सा, तेलंगाना.
2. एस. अरुणान, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कर्नाटक.
3. कन्याकुमारी अवसारला, कला, तमिलनाडु.
4. डॉ. बेटिना शारदा बौमेर, साहित्य और शिक्षा, जम्मू-कश्मीर.
5. नरेश बेदी, कला, दिल्ली.
6. अशोक भगत, समाजसेवा, झारखंड.
7. संजय लीला भंसाली, कला, महाराष्ट्र.
8. डॉ. लक्ष्मी नंदन बोरा, साहित्य और शिक्षा, असम.
9. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी, साहित्य और शिक्षा, मध्य प्रदेश.
10 प्रो. (डॉ.) योगेश कुमार चावला, चिकित्सा, चंडीगढ़.
11. जयाकुमारी चिक्कला, चिकित्सा, दिल्ली.
12. विवेक देबरॉय, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
13. डॉ. सरुंगबम बिमोला कुमारी देवी, चिकित्सा, मणिपुर.
14. डॉ. अशोक गुलाटी, सार्वजनिक मामले, दिल्ली.
15. डॉ. रणदीप गुलेरिया, चिकित्सा, दिल्ली.
16. डॉ. केपी हरिदास, चिकित्सा, केरल.
17. राहुल जैन, कला, दिल्ली.
18. रवींद्र जैन, कला, महाराष्ट्र.
19. डॉ. सुनील जोगी, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
20. प्रसून जोशी, कला, महाराष्ट्र.
21. डॉ. प्रफुल्ल कार, कला, ओडिशा.
22. सबा अंजुम, खेल, छत्तीसगढ़.
23. उषा किरण खान, साहित्य और शिक्षा, बिहार.
24. डॉ. राजेश कोटेचा, चिकित्सा, राजस्थान.
25. प्रो. अलका कृपलानी, चिकित्सा, दिल्ली.
26. डॉ. हर्ष कुमार, चिकित्सा, दिल्ली.
27. नारायण पुरुषोत्तमा माल्या, साहित्य और शिक्षा, केरल.
28. लैम्बर्ट मार्क, साहित्य और शिक्षा, गोवा.
29. डॉ. जनक पलटा मैकगिलिगन, समाजसेवा, मध्य प्रदेश.
30. वीरेंद्र राज मेहता, समाजसेवा, दिल्ली.
31. तारक मेहता, कला, गुजरात.
32. नील हर्बर्ट एन., कला, मेघालय.
33. चेवांग नोर्फेल, अन्य, जम्मू-कश्मीर.
34. टीवी मोहनदास पई, व्यापार और उद्योग, कर्नाटक.
35. डॉ. तेजस पटेल, चिकित्सा, गुजरात.
36. जादव मोलाइ पेयांग, अन्य, असम.
37. बिमला पोद्दार, अन्य, उत्तर प्रदेश.
38. डॉ. एन. प्रभाकर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, दिल्ली.
39. डॉ. प्रहलाद, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र.
40. डॉ. नरेंद्र प्रसाद, चिकित्सा, बिहार.
41. राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
42. मिताली राज, खेल, तेलंगाना.
43. पीवी राजारामन, सिविल सेवा, तमिलनाडु.
44. प्रो. जेएस राजपूत, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश.
45. श्रीकोटा श्रीनिवास राव, कला, आंध्र प्रदेश.
46. प्रो. बिमल रॉय, साहित्य और शिक्षा, पश्चिम बंगाल.
47. शेखर सेन, कला, महाराष्ट्र.
48. गुणवंत शाह, साहित्य और शिक्षा, गुजरात.
49. ब्रह्मदेव शर्मा (भाई जी), साहित्य और शिक्षा, दिल्ली.
50. मनु शर्मा, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश.
51. प्रो. योगराज शर्मा, चिकित्सा, दिल्ली.
52. वसंत शास्त्री, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कर्नाटक.
53. एसके शिवकुमार, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कर्नाटक.
54. पीवी सिंधु, खेल, तेलंगाना.
55. सरदारा सिंह, खेल, हरियाणा.
56. अरुणिमा सिन्हा, खेल, उत्तर प्रदेश.
57. महेश राज सोनी, कला, राजस्थान.
58. डॉ. निखिल टंडन, चिकित्सा, दिल्ली.
59. एचटी रिनपोछे, समाजसेवा, अरुणाचल प्रदेश.
60. डॉ. हरगोविंद लक्ष्मी शंकर त्रिवेदी, चिकित्सा, गुजरात.
61. हुआंग बाओशेंग (विदेशी), अन्य, चीन.
62. प्रो. जैक्स ब्लामॉन्ट (विदेशी), विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, फ्रांस.
63. सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन (मरणोपरांत), अन्य, महाराष्ट्र.
64. जीन क्लॉड कैरियर (विदेशी), साहित्य और शिक्षा, फ्रांस.
65. डॉ. नंदराजन राज शेट्टी (एनआरआई/पीआईओ), व्यापार और उद्योग, अमेरिका.
66. जॉर्ज एल हार्ट (विदेशी), अन्य, अमेरिका.
67. जगद्गुरु अमृता सूर्यानंद महाराज (एनआरआई/पीआईओ), अन्य, पुर्तगाल.
68. मीठा लाल मेहता (मरणोपरांत), समाजसेवा, राजस्थान.
69. तृप्ति मुखर्जी (एनआरआई/पीआईओ), कला, अमेरिका.
70. डॉ. दत्तात्रेययुडु नोरी (एनआरआई/पीआईओ), चिकित्सा, अमेरिका.
71. डॉ. रघुराम पी. (एनआरआई/पीआईओ), चिकित्सा, अमेरिका.
72. डॉ. सौमित्र रावत (एनआरआई/पीआईओ), चिकित्सा, ब्रिटेन.
73. प्रो. एनेट एस. (विदेशी), साहित्य और शिक्षा, जर्मनी.
74. प्राण कुमार शर्मा उर्फ प्राण (मरणोपरांत), कला, दिल्ली.
75. आर. वासुदेवन (मरणोपरांत), सिविल सेवा, तमिलनाडु.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

एल्ड्रिक हेजन एमिसः अमेरिका का देशद्रोही जासूस

अमेरिका के इतिहास में जिसे सबसे शातिर देशद्रोही माना जाता है, उस जासूस का नाम था एल्ड्रिक हेजन एमिस. एमिस पर जासूसी करने की खब्त सवार थी. कहा जा सकता है कि जासूसी करना उसके जीवन का शगल भी था और मकसद भी. जब वह स्मार्ट, चतुर और युवा था तब पढ़ने लिखने का भी शौकीन था. हफ्ते में दो या तीन किताबें पढ़ जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था. नौ वर्ष तक वह रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए भेदिए (मोल) की तरह काम करता रहा. 1985 में एमिस ने अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए के उन 25 जासूसों की लिस्ट नाम पते सहित केजीबी को दे दी जो रूस में सक्रिय थे. केजीबी ने उन सभी 24 व्यक्तियों और एक महिला को हिरासत में ले लिया. इनमें से 10 को व्याशा में सजा दी गई जो वहां की खतरनाक सजाओं में मानी जाती है. दसों जासूसों को घुटनों के बल दीवार की तरफ मुंह करके बैठा दिया गया. लार्ज केलिबर हैंडगन से सभी के सिर में पीछे से गोली मार दी गई ताकि किसी का चेहरा पहचाना न जा सके.

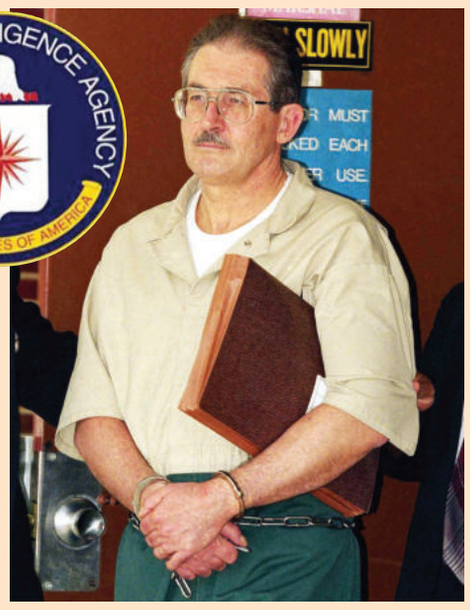

एमिस ने अपने एक खास दोस्त और जासूस की भी जानकारी केजीबी को दी थी. वह सोवियत डिप्लोमेट था. एमिस ने उसकी सीक्रेट बातें एक नहीं बल्कि दो बार बताई थीं. इस तरह एमिस ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कई बार छला था. एमिस ने समय समय पर केजीबी को सीआईए की कई गुप्त योजनाओं की जानकारी भी दी थी. सीआईए के कई ऑफिसर की जान का खतरा बने एमिस को इन जानकारियों के बदले केजीबी से दो मिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी रकम मिली थी. जासूसी के इतिहास में यह अब तक की सबसे अधिक धन राशि थी, जो किसी जासूस को गुप्त भेद देने के एवज में मिली थी. फरवरी 1994 को एमिस को सीआईए ने हिरासत में ले लिया. जांच के बाद एमिस पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर वह भेदियों की कैटेगरी में सबसे ऊपर था. एमिस के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने सीआईए की खूब छीछालेदर की. एमिस को अपनी सालाना तनख्वाह से कहीं अधिक पैसा तो एक बार की इनफॉरमेशन से ही मिल जाया करती थी. आय से अधिक खर्चे के कारण ही वह शक के दायरे में आया. सीआईए ने एमिस पर नजर रखनी शुरू कर दी. आखिरकार उसे पकड़ ही लिया गया. सीआईए ने एमिस को जासूसी के लिए ठोक-बजा कर तैयार किया था लेकिन पैसों के लालच ने एमिस को इतना गिरा दिया कि उसने अपने ही साथियों की मुखबिरी करके उन्हें मरवा डाला और अपने ही देश के भेद गैर मुल्क को बेच दिए. एफबीआई के एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा था कि एमिस ने देश ही नहीं बल्कि लोगों के साथ भी विश्वासघात किया था. उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. एमिस कहता था कि जासूसी उसके खून में है. उसके पिता कार्लटन एमिस अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए काम करते थे. 1950 के दौरान वे वर्मा में सीआईए के जासूस नियुक्त थे. कॉलेजन के प्रोफेसर के रूप में वहां लोकल कल्चर का अध्ययन करते थे. एमिस ने उस वक्त अपने पिता का कोई हुनर नहीं सीखा, लेकिन जब उनका परिवार वाशिंगटन डी.सी. लौट आया.

तब 1957 की गर्मियों में 16 वर्ष के एमिस को उसके पिता कार्लटन ने कहा कि उनकी एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए समर जॉब निकाली हैं जाकर उसे ज्वाइन करे और अपने लिए अतिरिक्त आय का इंतजाम करे. सीआईए की सीक्रेट ट्रेनिंग फैकल्टी में रिक एमिस को समर जॉब के तौर पर जासूसी की मामूली ट्रेनिंग दी गई. रिक एमिस को जासूसी का शौक यहीं से चढ़ा. रिक एमिस की मां हाई स्कूल में टीचर थीं. स्कूल से गोल (बंक) होने के लिए रिक अपनी उस जासूसी कला का इस्तेमाल भी करने लगा जो उसने समर जॉब के दौरान सीखी थी और अपने पिता को देख-देखकर उसे मांझा था. स्कूल में वह रोजाना रिक ट्रेंच कोट पहनता था. उसने अपनी सीक्रेट भाषा और गुप्त रास्ता भी बना लिया था जिसे स्कूल आने जाने के दौरान इस्तेमाल में लाता था. वह स्कूल में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेता था.

वह अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ डेट को भी एक मिशन की तरह इस्तेमाल करता था और इसके लिए भी उसने सीक्रेट कोड बनाए हुए थे. उसके एक कॉलेज साथी के अनुसार एक बार रिक ने उसे बताया था कि कभी भी अपनी सही पहचान किसी को न बताओ, अपनी सही फीलिंग किसी के आगे जाहिर न होने दो. सभी को अपने बारे में भ्रम में जीने दो. ग्रेजुएशन के बाद एमिस ने शिकागो यूनिवर्सिटी में एडमीशन ले लिया. यहां उसका समय ड्रामा क्लबों और नाटकों में भाग लेते हुए बीता. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम और विटमिन डी जरूरी है

चौथी दुनिया ब्यूरो

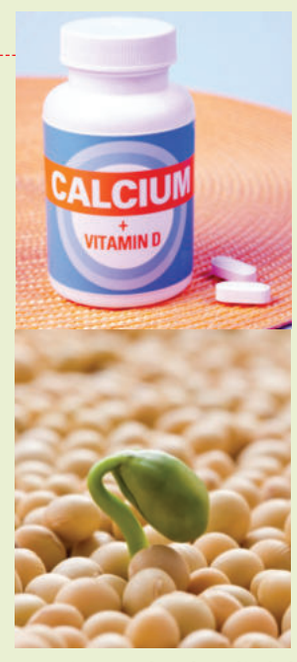

विटमिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एक सर्वे के मुताबिक, हर पांच महिलाओं में से एक में विटमिन-डी की कमी पाई जाती है. सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सोर्स है, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है.

क्या है विटमिन डी: विटमिन-डी एक खास स्टेरॉयड विटामिन है, जो आंतों से कैल्शियम को सोखकर हड्डियों में पहुंचाता है. शरीर में इसका निर्माण हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल और अल्ट्रावॉयलेट किरणों की मदद से होता है. इसके अलावा, शरीर में कोलिकल कैसिरॉल पाया जाता है, जो खाने के साथ मिलकर विटमिन-डी बनाता है. विटमिन-डी पांच प्रकार का होता है-विटमिन-डी1, विटमिन-डी2, विटमिन-डी3, विटमिन-डी4 और विटमिन-डी5. इनमें विटमिन-डी2 और डी-3 बेहद जरूरी हैं.

बीमारियां: अगर आप रोज 15 मिनट धूप में नहीं बैठते, तो विटमिन डी की कमी हो सकती है. पिछली रिसर्च बताती हैं कि विटमिन-डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, मल्टीपल स्केलरोसिस, मेमरी लॉस, हाई ब्लडप्रेशर, बोन पेन, कमजोरी और इंफेक्शन जैसी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं.

सर्दियों में ज्यादा जरूरत होती है: विटामिन डी की जरूरत हमें साल भर होती है लेकिन सर्दियो में जब तपमान कम हो जाता है, तब इसकी जरूरत बढ़ जाती है. इसी तरह महिलाओं को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है. कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है. इसके अलावा दिल, नर्व और मसल्स को ठीक से काम करने के लिए भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है. महिलाओं को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि पीरियड्स और प्रेग्नेंसी के दौरान उनमें कैल्शियम की खपत बढ़ जाती है. साथ ही कैल्शियम प्रेग्नेंसी के दौरान भ्रूण की संरचना का विकास करने के लिए जरूरी होता है. पिछले दिनों रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है उनमें जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कमजोर हड्डियों का होना जैसी शिकायतें आम होती हैं. इतना ही नहीं, भारत में इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस (हड्डियों का कमजोर होकर टूटना/चटखना) के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है. कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं में कंफ्यूजन, साइकोसिस और थकान जैसी सामान्य समस्याएं भी होती हैं.

अधिक कैल्शियम नुकसानदायक है : अक्सर देखने में आता है कि कैल्शियम की कमी के बाद महिलाएं अपना सारा खान-पान कैल्शियम पर ही केंद्रित कर देती हैं. ऐसे में उनका कैल्शियम इनटेक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है. कैल्शियम की अधिक मात्रा से शरीर में पथरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वहीं अगर आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट यूज़ कर रही हैं, तो आपको दिल से संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं. रिसर्च बताते हैं कि जो लोग रोजाना जरूरत से ज्यादा कैल्शियम सेवन करते हैं, उनकी मृत्यु दर कैल्शियम की संतुलित मात्रा लेने वालों से ज्यादा है. हमारे शरीर में कैल्शियम का सही इनटेक तभी हो सकता है जब विटामिन डी की भरपूर मात्रा मौजूद हो. अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो कैल्शियम भी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा.

कैल्शियम युक्त फूड

फल : ब्लैकबैरीज, ब्लूबैरीज, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, किवी

सब्जियां : हरी प्याज, चुकंदर, पालक, मीठे आलू, भिंडी, कसावा, हरी पत्तेदार सब्जियां

अन्य कैल्शियम युक्त पदार्थ : बादाम, चॉकलेट, मूंगफली, काजू, फलियां, मक्का, चावल, सोयाबीन, चोकर, गेहूं, दूध, दही, अंडे, मछली, ड्राईड फिगस, ब्रोकोली, फ्रेंच बीन्स आदि.

कैल्शियम की सही मात्रा

19 से 50 साल तक :

कम से कम : 1000 मिलीग्राम

अधिक से अधिक : 2500 मिलीग्राम

50 साल से ऊपर

कम से कम : 1200 मिलीग्राम हीं विटमिन डी की कमी तो नहीं?

विटमिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एक सर्वे के मुताबिक, हर पांच महिलाओं में से एक में विटमिन-डी की कमी पाई जाती है. सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सोर्स है, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूडान की राजधानी ख़रतूम की जामा मस्जिद के सामने हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन जनाक्रोश को देखते हुए यहां भी पुलिस ने उन्हें फ्रांसीसी दूतावास तक जाने नहीं दिया. मूरीतानिया में नुवाकशूत में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने पत्रिका और फ्रांस के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की. प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी दूतावास जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो उन्होंने फ्रांस के झंडे को आग लाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस प्रदर्शन में उलेमा और इमामों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया.

शार्ली ऐब्दो कॉर्टून प्रकरण

इस्लामी दुनिया में बेचैनी

चेचन्या के राष्ट्रपति रमज़ान क़ादीरोव ने कहा कि यह एक असहनीय कृत्य है और इससे पूरी इस्लामी दुनिया आहत हुई है. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने इस कृत्य को अलोकतांत्रिक बताया. इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों ने एक ओर पत्रकारों की हत्या की निंदा की, वहीं कॉर्टूनों के पुन: प्रकाशन पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस कृत्य के चलते पूरी इस्लामी दुनिया की भावनाएं आहत हुई हैं. शासक वर्ग के अलावा विभिन्न शख्सियतों एवं संगठनों की ओर से भी कॉर्टून छापने पर आपत्ति जताई गई. अल्जीरिया की स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक बयान आया, जिसमें कहा गया है कि अगर फ्रांस ने स्वतंत्रता के नाम पर मोहम्मद साहब का अपमान बंद नहीं किया, तो सभी फ्रांसीसी संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा. इस यूनियन से 24 हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं. दूसरी ओर अल्जीरिया की ट्रेड यूनियन के बुलनवाज़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक फ्रांस इस तरह के कृत्यों पर रोक नहीं लगाता, तब तक फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार जारी रहेगा.

वसीम अहमद

फ्रांस की पत्रिका शार्ली ऐब्दो ने मोहम्मद साहब का आपत्तिजनक कॉर्टून प्रकाशित किया है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पत्रिका के 12 लोगों की हत्या कर दी गई. इसकी निंदा पूरी दुनिया में हुई और सबने कहा कि पत्रिका का तरीक़ा ग़लत था और प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा अपनाना भी बिल्कुल उचित नहीं है. दो भाइयों ने मिलकर पत्रिका के कार्यालय में जो हिंसा की, वह इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. हालांकि, कुछ देशों में पत्रिका के व्यवहार पर प्रदर्शन हुए, लेकिन उनमें आक्रोश नहीं था. लेकिन, जब पत्रिका ने दोबारा कॉर्टून प्रकाशित किए, तो इस्लामी दुनिया के लोग आक्रोशित हो गए और विभिन्न देशों में विरोध प्रदर्शन होने लगे. कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ झड़पें हुईं, जबकि कहीं-कहीं पर फ्रांसीसी संस्थानों को नुक़सान भी पहुंचाया गया. इन झड़पों, फ्रांसीसी संस्थाओं को नुक़सान पहुंचाने और धमकियां देने से एक बात खुलकर सामने आती है कि इस्लामी दुनिया में जहां एक ओर उक्त पत्रिका के पत्रकारों पर जानलेवा हमले की निंदा की जा रही है, वहीं पुन: कॉर्टून प्रकाशित करने और फ्रांसीसी जनता द्वारा उक्त अंक हाथों-हाथ लेने की कड़ी निंदा हो रही है. विश्लेषकों की मानें, तो फ्रांसीसी जनता के इस अमल ने दो संस्कृतियों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है.

उक्त पत्रिका की प्रसार संख्या क़रीब 60 हज़ार है, लेकिन पुन: कॉर्टून प्रकाशित करने के बाद फ्रांस की जनता की पत्रिका में इतनी रुचि बढ़ गई कि उसकी लाखों प्रतियां हाथों-हाथ बिक गईं. जाहिर है, यूरोप की संस्कृति के पक्षधर लोगों को मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उक्त पत्रिका नहीं खरीदनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से लंबी-लंबी लाइनें लगाकर लोगों ने उसे खरीदा, उसने मुसलमानों के बीच नफ़रत बढ़ा दी. नतीतजन, फ्रांस और उक्त पत्रिका के लिए घोर आक्रोश पैदा हुआ. नफ़रत और आक्रोश का इज़हार मुस्लिम सरकारों, संगठनों एवं जनता की ओर से बड़े स्तर पर किया गया. पत्रिका में मोहम्मद साहब के आपत्तिजनक कॉर्टून प्रकाशित होने पर पाकिस्तान की असेंबली में निंदा प्रस्ताव परित किया गया और प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने इसकी कड़ी निंदा की. ईरान के गृह मंत्रालय ने भी एक बयान में फ्रांसीसी पत्रिका की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे इस्लाम धर्म का अपमान एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत क़रार दिया. तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊद ओगलो ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपमान करने का लाइसेंस नहीं देती, पत्रिका ने ऐसा करके मुसलमानों को आक्रोशित किया है. तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यब अर्दगान ने अपने बयान में कहा कि ये कॉर्टून घृणात्मक हैं, हम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसका नोटिस लेना चाहिए, हम ऐसे कृत्य सहन नहीं करेंगे.

चेचेन्या के राष्ट्रपति रमज़ान क़ादीरोव ने कहा कि यह एक असहनीय कृत्य है और इससे पूरी इस्लामी दुनिया आहत हुई है. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने इस कृत्य को अलोकतांत्रिक बताया. इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों ने एक ओर पत्रकारों की हत्या की निंदा की, वहीं कॉर्टूनों के पुन: प्रकाशन पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस कृत्य के चलते पूरी इस्लामी दुनिया की भावनाएं आहत हुई हैं. शासक वर्ग के अलावा विभिन्न शख्सियतों एवं संगठनों की ओर भी कॉर्टून छापने पर आपत्ति जताई गई. अल्जीरिया की स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक बयान आया, जिसमें कहा गया है कि अगर फ्रांस ने स्वतंत्रता के नाम पर मोहम्मद साहब का अपमान बंद नहीं किया, तो सभी फ्रांसीसी संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा. इस यूनियन से 24 हज़ार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं. दूसरी ओर अलजज़ाइर की ट्रेड यूनियन के बुलनवाज़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक फ्रांस इस तरह के कृत्यों पर रोक नहीं लगाता, तब तक फ्रांसीसी

उत्पादों का बहिष्कार जारी रहेगा. ग़ौरतलब है कि अल्जीरिया के बाज़ार में सबसे अधिक फ्रांसीसी उत्पाद ही होते हैं. मोरक्को में भी काफी आक्रोश है. वहां की जनता, सिविल सोसायटी, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य कई वर्गों की ओर से फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की गई है. मोरक्को की जनता की नाराज़गी और सरकार की आपत्ति दूर करने के लिए फ्रांस ने अपने विदेश मंत्री को मोरक्को भेजने की घोषणा की है. पाकिस्तान के फ़ैसलाबाद अंजुमन व्यापारी सिटी की ओर से पत्रिका की कड़ी निंदा की गई. मिस्र के सरकार प्राधिकरण दारूलअता की ओर कहा गया कि पत्रिका के इस कृत्य ने दुनिया भर के मुसलमानों को आहत किया है, जिसका अंजाम बुरा हो सकता है. क़तर में अल्लामा क़रज़ावी के नेतृत्व में मुस्लिम उलेमा एवं विद्धानों की अंतरराष्ट्रीय यूनियन की ओर से कहा गया कि पत्रिका के इस कृत्य से एकता की भावना और सांस्कृतिक संवाद को नुक़सान पहुंचा है. सउदी अरब के मशहूर आलिम दीन शेख़ ग़ामदी का कहना है कि पत्रिका ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं आहत की हैं.

पूरी इस्लामी दुनिया में होने वाले प्रदर्शन बता रहे हैं कि पत्रिका ने मुसलमानों को काफी आक्रोशित किया है. कार्टून के प्रकाशन के बाद नाइजीरिया में 45 चर्चों को नुक़सान पहुंचाया गया. पांच होटलों एवं 36 दुकानें लूट ली गईं. प्रदर्शनों के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 128 लोग घायल हुए, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. इसके अलावा फ्रेंच कल्चरल सेंटर के भवन को आग लगा दी गई. पाकिस्तान के शहर कराची में फ्रांस के दूतावास के सामने प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस के साथ हुई झड़प में पत्रकार आसिफ़ हसन को सीने में गोली लगी, जिन्हें तुरंत जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई गई. इसके अलावा भी कई लोग घायल हुए. पाकिस्तान के ही शहर मुल्तान में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस का झंडा जलाया और पेशावर एवं लाहौर में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मुतीउर्रहमान अहमद ज़ई अहमद के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें फ्रांस से कूटनीतिक संबंध ख़त्म करने की मांग की गई.

रूस की राजधानी मास्को में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी. कुर्दिस्तान के पहीरान शहर में मुस्तफ़ा मोहम्मद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कहा गया कि इस आपत्तिजनक कॉर्टून ने अरबों को नाराज़ कर दिया है. अलकुदस में भी प्रदर्शन हुआ. यह प्रदर्शन नुसरत बनी के नाम से मस्जिद-ए-अक्सा के मैदान में हुआ. जिस समय यह प्रदर्शन हो रहा था, मैदान में इजराइली सेना भी बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ. इसी तरह जॉर्डन की राजधानी ओमान की मशहूर मस्जिद हुसैनी के सामने एक मैदान में हज़ारों लोगों ने एकत्र होकर पत्रिका और फ्रांस की नीति के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व जॉर्डन नेशनल कमीशन नामक संगठन ने किया. प्रदर्शनकारी ट्रंगल सर्किल की ओर से फ्रांसीसी दूतावास में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन सुरक्षाबल के जवानों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके चलते उनके और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई. उक्त पत्रिका के विरोध में एक प्रदर्शन अलजज़ायर में हुआ, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी दूतावास तक जाना चाहते थे, लेकिन उनके तेवर देखकर पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया. नतीजतन पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, पथराव हुआ और पुलिस पर शीशे के टुकड़े फेंके गए. जवाब में पुलिस ने पानी की बौछार की. इस भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी घायल हुए.

इसी तरह सूडान की राजधानी ख़रतूम की जामा मस्जिद के सामने हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन जनाक्रोश को देखते हुए यहां भी पुलिस ने उन्हें फ्रांसीसी दूतावास तक जाने नहीं दिया. मूरीतानिया में नुवाकशूत में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने पत्रिका और फ्रांस के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की. प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी दूतावास जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो उन्होंने फ्रांस के झंडे को आग लाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस प्रदर्शन में उलेमा और इमामों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया. इस्तांबुल में अलहया अलअख्विया लिलसहाबा के नेतृत्व में एक समूह जामा मस्जिद अलफ़ातह के सामने एकत्र हुआ और उसने पत्रिका के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. नारेबाज़ी के दौरान कुछ लोग हमलावर दोनों भाइयों पर नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. रूस के उत्तर-पूर्व में स्थित मुस्लिम बाहुल्य लोकतांत्रिक चेचेन्या की राजधानी गरज़ूनी में लाखों लोगों ने आपत्तिजनक कॉर्टून के प्रकाशन और इस्लाम का अपमान करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में अन्य राज्यों से भी मुसलमान बड़ी संख्या में शामिल हुए. इन चिंताजनक हालात में ईसाइयों के आध्यात्मिक गुरु पोप फ्रांसिस का बयान सराहनीय है. पोप ने फ्रांसीसी पत्रिका में प्रकाशित हुए आपत्तिजनक कॉर्टूनों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए. पोप के अनुसार, किसी भी धर्म का मज़ाक उड़ाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरी मां के ख़िलाफ़ अपशब्द प्रयोग करे, तो उसे मेरा घूंसा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उक्त अपमानजनक कॉर्टूनों के प्रकाशन के ख़िलाफ़ इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी की ओर से अब तक कोई कड़ी प्रतिकिया सामने नहीं आई है. संगठन के महासचिव अैयाद मदनी केवल यह घोषणा करके अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी हो गए हैं कि ओआईसी चार्ली ऐब्दो के ख़िलाफ़ फ्रांसीसी एवं यूरोपीय अदालतों में जाने का इरादा रखती है. हालांकि, दुनिया यह जानती है कि इन अदालतों से मुसलमानों को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है. उत्तरी क़फ़क़ाज़ स्थित पूर्व रूसी देश अंगूशीतिया की राजधानी मगास में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 20 हज़ार से अधिक लोगों ने शिरकत की. अंगूशीतिया के प्रमुख यूनुस बेग यूकोरो ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम देश के नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने की कोशिशों का निरंतर मुक़ाबला करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब चारों जंगल में एक स्थान पर एकत्रित हुए तो वहां उन्हें शेर के शरीर की एक हड्डी पड़ी हुई मिली. एक ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस एक हड्डी से शेर का पूरा अस्थि पंजर बना सकता हूं. उसने ऐसा कर भी दिखाया. तब दूसरे ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूं. फिर उसने यह कर दिया. अब उन लोगों के समक्ष एक शेर पड़ा था, जो प्राणविहीन था. अब तीसरा ब्राह्मण बोला, मैं इसमें अपनी सिद्धि के चमत्कार से प्राण डाल सकता हूं.

साई दिलाएंगे दुखों से छुटकारा

चौथी दुनिया ब्यूरो

जो भी व्यक्ति साई बाबा की शरण में एक बार जाता है वो उनका भक्त बन जाता है और उसे साई कृपा प्राप्त हो जाती है. साई उसकी हर संकट में रक्षा करते हैं और उसे हर दुख और मसीबत से उबारते हैं. इसलिए हम सभी को साई की शरण में जाना चाहिए.

श्री हरि सीताराम, जो काका साहेब दीक्षित के नाम से जाने जाते हैं, का जन्म सन् 1864 में वड़नगर के खंडवा में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा एवं हिंगणघाट में हुई. माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने पहले विल्सन और फिर एलफिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया. सन् 1883 में उन्होंने स्नातक की डिग्री लेकर क़ानूनी सलाहकार की परीक्षा पास की और फिर सरकारी सॉलीसिटर फर्म–मेसर्स लिटिल ऐंड कंपनी में कार्य करने लगे. इसके बाद उन्होंने ख़ुद की एक सॉलीसिटर फर्म भी शुरू कर दी.

सन् 1909 के पहले तक काका साहेब साई बाबा की कीर्ति से वाक़िफ़ नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, वह बाबा के परमभक्त बन गए. एक बार लंदन में रेलगाड़ी पर चढ़ते समय उनके पैर में चोटें आई थीं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तक़लीफ़ थी. इलाज में हर जगह से थक–हारकर काका साहेब ने अपनी परेशानी पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से कही. नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हो, तो मेरे सद्गुरु श्री साई बाबा की शरण में जाओ. उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर कहा कि वैसे भी साई बाबा अपने भक्तों को सात समंदर पार से भी बुला ही लेते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन नहीं होगे, तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे. काका साहेब को ये सारी बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वह शिरडी जाकर बाबा से इस कष्ट से निवारण की प्रार्थना करेंगे.

कुछ दिनों बाद ही काका साहेब दीक्षित किसी काम को लेकर अहमदनगर गए और काम पूरा होते ही शिरडी जाने की तैयारी में लग गए. वहीं दूसरी ओर साई बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे. शिरडी में बाबा का परमभक्त शामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक ख़राब है और उन्हें देखने के लिए वह शीघ्र ही अहमदनगर आएं. बाबा से अनुमति प्राप्त कर शामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था. जाते समय बाबा ने शामा से नाना साहेब पानसे एवं अप्पा साहेब दीक्षित से भेंट करने और उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने के लिए कहा. उन्होंने शामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित एवं मिरीकर को भी दे दी. संध्या समय शामा मिरीकर के घर आए. मिरीकर ने शामा का काका साहेब से परिचय कराया और फिर यह निश्चित हुआ कि काका साहेब उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव रवाना हो जाएंगे. इसके बाद एक विचित्र घटना घटी. मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र से पर्दा हटाकर काका साहेब को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ वे शिरडी जाने वाले हैं, वह ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत के लिए यहां विराजमान हैं. तब अत्यंत द्रवित होकर वह बाबा की वंदना करने लगे. यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था. दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहेब एवं शामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया. 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंच कर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया. जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई, तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा था. उसमें बैठने के लिए तिल मात्र भी स्थान न था. भाग्यवश गार्ड साहब काका साहेब दीक्षित के परिचित निकले और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया. इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे. स्टेशन पर ही शिरडी जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनकी ख़ुशी का ठिकाना न रहा.

> बाबा से अनुमति प्राप्त कर शामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था. जाते समय बाबा ने शामा से नाना साहेब पानसे एवं अप्पा साहेब दीक्षित से भेंट करने और उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने के लिए कहा. उन्होंने शामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित एवं मिरीकर को भी दे दी. संध्या समय शामा मिरीकर के घर आए.

शिरडी पहुंचने के बाद उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा के दर्शन किए. तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था. शामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा था. इसके बाद काका साहेब कई सालों तक बाबा की संगत में रहे. उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा बनवाया, जो उनका बाद के दिनों में प्राय: स्थायी घर हो गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

भारती गंगा विश्वविद्यालय बने

देश में अब भारती गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है. यह जानकर अपार ख़ुशी हुई. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री साध्वी उमा भारती की इच्छा-शक्ति एवं प्रयास से यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो देश के कई नदियों के जोड़ने का काम, स्वच्छता, जल-संसाधन के कार्य के साथ-साथ देश-विदेश के छात्रों को पानी की किस्मों एव पर्यावरण की जानकारी मिलेगी. चौथी दुनिया 05-01-2015 से 11-01-2015 अंक में सद्भावना और प्रेम शिक्षा प्रद कहानी अच्छी लगी और साई बाबा का सदगुरू से शिक्षा लेनी चाहिए. कॉलम में यह पढ़ा कि माता-पिता ही सच्चा गुरु है, खास कर मां से ज्यादा भिक्षा मिलती है . पढ़कर बहुत ख़ुशी हुई.

–विनोद कुमार तिवारी, फारबिसगंज, बिहार.

अन्ना आंदोलन का सच

अब यह स्पष्ट हो गया है कि अन्ना हजारे का तथाकथित आंदोलन देश की राजनीति से कांग्रेस को शुन्य करना था और उसके पीछे भाजपा एवं संघ की सोच थी. हालांकि किरण बेदी ने पहले ही इसकी अनौपचारिक घोषणा कर दी थी कि वे भाजपा में जायेंगी. उनके द्वारा नरेंद्र मोदी का गुणगाण भी तब बेवजह नहीं था. अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ़ सीना ताने खड़े अरविन्द केजरीवाल को अपना मुखिया मानती है या फ़िर नरेंद्र मोदी की कठपुतली किरण बेदी को.

–नवल कुमार, ई-मेल के द्वारा.

कांटे की टक्कर

कवर स्टोरी-दिल्ली विधानसभा चुनाव, भाजपा की अग्निपरीक्षा(26 जनवरी-01-फरवरी 2015) पढ़ा. तथ्यों पर आधारित है. मनीष कुमार ने सही कहा है कि चुनाव कौन जीतेगा, सरकार कौन बनाएगा, इस बारे में वोटों की गिनती के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है और भाजपा ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीवार घोषित कर केजरीवाल को कड़ी चुनौती दी है. यही नहीं भाजपा ने केजरीवाल का मुंह भी बंद कर दिया है और अब केजरीवावल भाजपा पर मुख्यमंत्री पद को लेकर और किरण बेदी पर सीधे अटैक नहीं कर सकते. अब 10 फरवरी को चुनाव परिणाम आने बाद पता चल जाएगा कि कौन दिल्ली की कुर्सी संभालेगा और मुख्यमंत्री बनेगा.

–अखिलेश सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

आजीवन सुखी रहें

हे प्रभु मैंने तुझे नहीं देखा फिर भी मेरा विश्वास है कि तू कहीं न कहीं जरूर है, क्योंकि मेरी सांस चल रही है. पंझी उड़ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं चांद अपने समय पर आ रहा है. यह सब भगवान के होने के ही सबूत हैं. मैं तुझसे प्राथना करता हूं कि तू हमारे देश में रहने वालों को परेशानियों से मुक्त कर उन्हें बुरे कर्मों से बचा अच्छी तरह राह दिखा मानव समाज के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं उनकी आंखे खोलों. आप विश्व के लोगों को सत्य की राह पर चलने की हिम्मत दे अपने कर्तव्य से कोई भी मनुष्य मुंह न मोड़े.

–राकेश कुमार, नवादा, बिहार.

युवाओं को रोजगार चाहिए

आलेख-दिल्ली विधानसभा चुनाव असमंजस में युवा मुस्लिम मतदाता(26 जनवरी-01-फरवरी 2015) पढ़ा. बहुत अच्छा आलेख है. वसीम अहमद ने सही कहा है कि मुस्लिम युवा मतदाता असमंजस में हैं. मुस्लिम यवाओं ने चुनाव के आखिरी समय तक तय नहीं कर पाया की वो अपना मत किसे दें. क्योंकि मुस्लिम युवा भी बाकी युवाओं की तरह मोदी को पसंद करता है. इसी का नतीजा रहा कि मोदी को लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई. युवाओं के मन में धर्म-जाति का कोई असर नहीं उसे विकास, रोजगार और अन्य सुविधाएं चाहिए जो हर युवा की जरूरत है. धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रादयिकता से कोई मतलब नहीं उसे केवल विकास चाहिए. इसलिए मुस्लिम युवाओं के मन में एक डर भी है, जो आज तक मुस्लिम मतदाताओं के मन में भाजपा को लेकर रही है. इसलिए वह विकास भी चाहता, कांग्रेस को भी मत नहीं देना चाहता और केजरीवाल को लेकर उसके मन में है कि एक बार फिर वह दिल्ली गद्दी छोड़कर भाग न जाएं. इसलिए वह आखिरी समय तक यह तय नहीं कर पाया कि उसे मत किसे देना है.

–नईम अहमद, ओखला, दिल्ली.

अमीरों का नहीं गरीबों का हो विकास

चौथी दुनिया एक जानकारीपरक समाचार-पत्र है. इसमें प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद नई-नई जानकारियां हासिल होती हैं. संतोष भारतीय द्वारा लिखा गया जब तोप मुकाबिल हो पढ़कर काफी अच्छा लगता है. (26 जनवरी-01-फरवरी 2015) के अंक में प्रकाशित संपादकीय आशा करें, आगामी बजट जनता का हो पढ़ा. संतोष भारतीय ने बहुत अच्छा विचार प्रकट किया है कि हम न किसी की नीयत पर संदेह जता रहे हैं और न किसी के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं. यह बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो वादा किया था उसे आधार पर देश को विकास के रास्ते ले जाना चाहते हैं, उनको अपने कदमों से यह बता होगा कि उनके विकास मतलब केवल 20 प्रतिशत लोगों का विकास नहीं हैं. प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक युवा हैं, तो प्रधानमंत्री को सभी युवाओं को रोजगार देने के तरफ कदम बढ़ाने चाहिए और देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकना चाहिए.

–रविन्द्र कुमार, बक्सर, बिहार.

कहानी

ब्राह्मण मित्र

बहुत पुरानी बात है. चार विद्वान ब्राह्मण मित्र थे. एक दिन चारों ने संपूर्ण देश का भ्रमण कर हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का निश्चय किया. चारों ब्राह्मणों ने चार दिशाएं पकड़ीं और अलग-अलग स्थानों पर रहकर अनेक प्रकार की विद्याएं सीखीं. पांच वर्ष बाद चारों अपने गृहनगर लौटे और एक जंगल में मिलने की बात तय की. चूंकि चारों परस्पर एक-दूसरे को अपनी गूढ़ विद्याओं व सिद्धियों को बताना चाहते थे, अत: इसके लिए जंगल से उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता था.

जब चारों जंगल में एक स्थान पर एकत्रित हुए तो वहां उन्हें शेर के शरीर की एक हड्डी पड़ी हुई मिली. एक ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस एक हड्डी से शेर का पूरा अस्थि पंजर बना सकता हूं. उसने ऐसा कर भी दिखाया. तब दूसरे ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूं. फिर उसने यह कर दिया. अब उन लोगों के समक्ष एक शेर पड़ा था, जो प्राणविहीन था.

अब तीसरा ब्राह्मण बोला, मैं इसमें अपनी सिद्धि के चमत्कार से प्राण डाल सकता हूं. चौथे ब्राह्मण ने उसे यह कहते हुए रोका, यह मूर्खता होगी. हमें तुम पर विश्वास है, किंतु यह करके न दिखाओ. किंतु तीसरे ब्राह्मण का तर्क था कि ऐसी सिद्धि का क्या लाभ जिसे क्रियान्वित न किया जाए. उसका हठ देखकर चौथा ब्राह्मण तत्काल पास के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया. तीसरे ब्राह्मण के मंत्र पढ़ते ही शेर जीवित हो गया. प्राणों के संचार से शेर को आहार की आवश्यकता महसूस हुई और उसने सामने मौजूद तीनों ब्राह्मणों को मारकर खा लिया. चौथे ब्राह्मण ने समझदारी से अपने प्राण बचा लिए. ■

शिक्षा–किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा संकट में पड़ सकते हैं.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

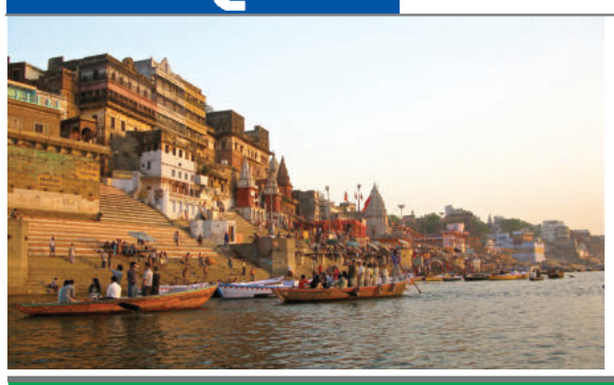

> शिवरात्रि पर देखना, भीड़ देखनी हो तो..., कहकर मोटा आगे बढ़ गया. दोनों राजेंद्र प्रसाद घाट की सीढ़ियां उतरने लगे. घाट पर भीड़ थी और श्रद्धालु गंगा में नहाकर अपने पाप कम करने की कोशिश में थे. दोनों सीढ़ियां उतर कर सिंधिया घाट की तरफ़ जाने लगे.बोट पर चलेंगे, बोट पर चलेंगे सर? मल्लाहों के झुंड से एक लड़का उन दोनों के पीछे लग गया. मोटे ने पीछे पलट कर देखा. लड़के से उसकी नज़रें मिलीं.

अकथ कहानी मोहब्बत की

अनंत विजय

संस्मरण हिंदी में अपेक्षाकृत नई विधा है, जिसका आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है. इस विधा का असली विकास छायावादी युग में हुआ. इस काल में सरस्वती, सुधा, माधुरी, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं में कई उल्लेखनीय संस्मरण प्रकाशित हुए. आगे चलकर छायावादोत्तर काल में तो यह विधा पूरी तरह से एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हुई. संस्मरण साहित्य की सबसे अनमोल निधि वे पत्र-पत्रिकाएं हैं, जिनमें संस्मरणात्मक लेख नियमित रूप से प्रकाशित हुए या होते रहे. न सिर्फ़ हिंदी के लेखकों ने बेहतरीन संस्मरण लिखकर इस विधा को स्थापित किया, बल्कि कुछ विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी में अच्छे संस्मरण लिखे. प्रसिद्ध रूसी विद्वान ये पे चेलीशेव का संस्मरण-निराला: जीवन और संघर्ष के मूर्तिमान आज भी हिंदी पाठकों की स्मृति में जीवंत है.

संस्मरणों में आम तौर पर लेखकीय ईमानदारी की ज़रूरत होती है, जो न केवल लेखक की विश्वसीनयता को बढ़ाती है, बल्कि लेख को भी एक ऊंचाई प्रदान करती है. संस्मरण लेखन में हाल के दिनों में जिस स्तरहीनता का परिचय मिला, वह चिंता का विषय है. हाल के दिनों में हुआ यह कि संस्मरण लेखन को लेखकों ने व्यक्तिगत झगड़े निपटाने का औजार बनाकर लेखक विशेष के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, जिससे फौरी तौर पर तो लेखक चर्चा में आ गया, लेकिन चंद महीनों बाद उसका और लेख का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा. उर्दू के मशहूर नगमानिगार कैफी आजमी साहब की बेगम और अपने जमाने की मशहूर अदाकारा शौकत कैफी ने अपनी आपबीती-यादों के रहगुजर लिखी, जो संस्मरण के अलावा शौकत और कैफी की एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी है.

यादों की रहगुजर लगभग डेढ़ सौ पन्नों में लिखा गया वह अफसाना है, जिसे अगर कोई पाठक एक बार पढ़ना शुरू कर देगा, तो फिर बीच में नहीं छोड़ सकेगा. शौकत कैफी की पैदाइश 1928 की है. शौकत हैदराबाद के एक ऐसे मुस्लिम परिवार में पैदा हुईं, जिसका माहौल उस दौर के आम मध्यवर्गीय मुसलमान परिवार जैसा ही था. यह वह दौर भी था, जब लड़कों की पैदाइश पर लड्डू बांटे जाते थे, तो लड़की की विलादत को अल्लाह की मर्जी मान लिया जाता था. लेकिन, शौकत इस मामले में जरा भाग्यशाली थीं, क्योंकि उनके पिता अपने परिवार के विचारों के उलट तरक्की पसंद इंसान थे. वह लड़कियों को लड़कों के बराबर मानते थे और लड़कियों की तालीम के हक़ में थे. बावजूद अपने परिवार के सख्त विरोध के उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की तालीम का इंतज़ाम किया. नतीजा यह हुआ कि शौकत का बचपन बेहतर और तरक्की पसंद लोगों की सोहबत में बीता.

आज़ादी के चंद महीने पहले की बात है, जब फरवरी में हैदराबाद में तरक्की पसंद लोगों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी आदि ने शिरकत

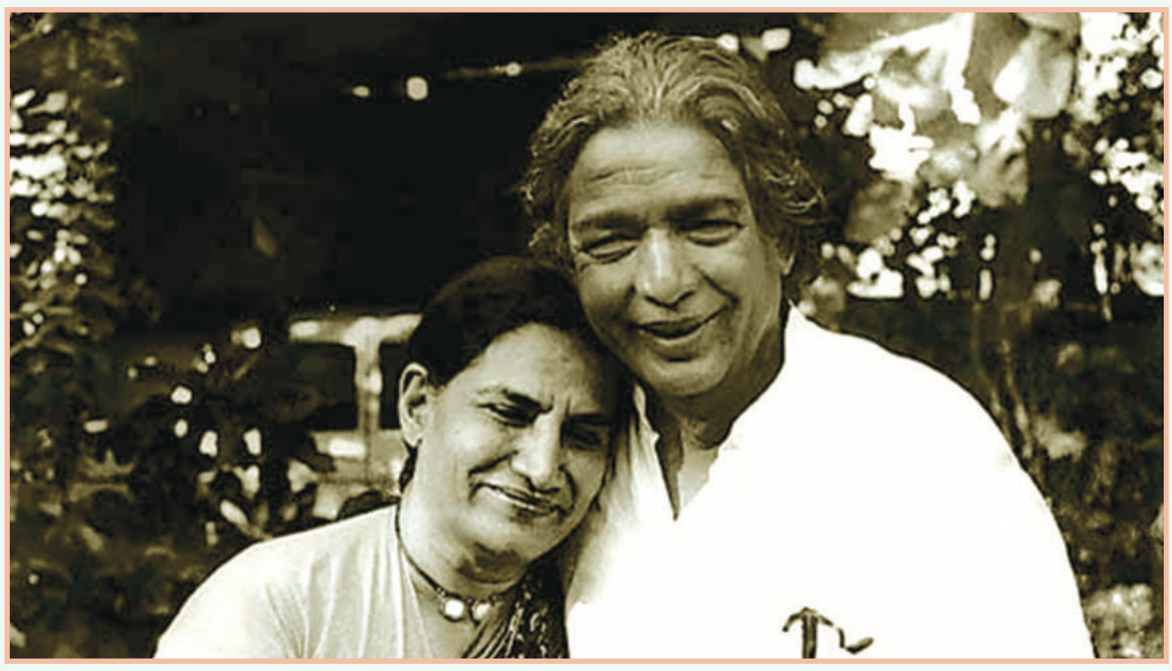

की थी. उसी दिन रात में एक मुशायरे में शौकत खानम और कैफी ने एक-दूसरे की आंखों में अपना भविष्य देख लिया. यह भी एक बेहद दिलचस्प वाकया है. हुआ यह कि जैसे ही मुशायरा ख़त्म हुआ, तो लोगों का हुजूम कैफी, मजरूह और सरदार जाफरी की तरफ़ लपका. शौकत ने एक उड़ती नज़र कैफी पर डाली और सरदार जाफरी से ऑटोग्राफ लेने चली गईं. इतनी भीड़ में भी कैफी ने अपनी इस उपेक्षा को भांप लिया और जब शौकत ने कैफी की तरफ़ ऑटोग्राफ के लिए कॉपी बढ़ाई, तो शायर ने अपनी उपेक्षा कॉपी पर उतार दी:-

वही अब्रे-जाला चमकनुमा वही, ख़ाके-बुलबुले-सुर्ख़-रू जरा राज बन के महन में आओ, दिले घंटा तुन तो बिजली कड़के धुन तो फबन झपट के लगन में आओ इस शे'र से नाराज़ होकर जब शौकत ने कैफी से इसकी वजह जाननी चाही, तो कैफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने भी तो पहले जाफरी साहब से ऑटोग्राफ लिया. इसके बाद तो शौकत खानम कैफी की पुरकशिश शख्सियत पर सिहरजदा हो गईं. फिर तो मुहब्बत और आशिकी का सिलसिला चल निकला और लंबी-लंबी खतो-किताबत भी शुरू हो गई. कैफी मुंबई में रहते थे, तो शौकत अपने पिता के साथ औरंगाबाद में. शौकत के हाल-ए-दिल का पता उनके पिता को चल चुका था और शौकत ने भी कैफी से शादी करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी. पिता ने बेटी से कहा कि मुंबई चलकर देख लेते हैं, फिर कोई फ़ैसला लेते हैं.

पिता-पुत्री दोनों चल पड़े मुंबई. वहीं घटनाचक्र कुछ इस कदर चला कि कैफी की हालत का पता लगाने गए पिता ने बेटी की मर्जी को देखते हुए दोनों का निकाह करा दिया. शादी हुई सज्जाद जहीद के घर और उनकी बेगम रजिया ने शौकत की मां की भूमिका निभाई. बाराती बने जोश मलीहाबादी, मजाज, कृष्ण चंदर, साहिर लुधियानवी, इस्मत चुगताई और सरदार जाफरी जैसे तरक्की पसंद लोग. इसके बाद शौकत और कैफी की नई ज़िंदगी शुरू होती है कम्यून में. लेकिन, यहां एक बात रेखांकित करने लायक है कि उस दौर में भी शौकत के अब्बाजान इतने तरक्की पसंद ख्यालात के थे कि उन्होंने बेटी के प्यार के लिए पूरे परिवार की नाराज़गी मोल लेते हुए उसका निकाह करा दिया और अकेले घर लौट आए. जब शादी हुई थी, तो उस वक्त कैफी कम्यून में रहते थे और त्रैमासिक नया अदब के संपादक थे. शौकत ने कम्यून के कमरे को घर का रूप देना शुरू किया. यह पूरा किस्सा बेहद दिलचस्प है. कैफी की संगत और कम्यून के माहौल ने शौकत को इप्टा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भीष्म साहनी के ड्रामे में काम किया, जिसे खूब सराहना मिली. सब कुछ ठीकठाक चल रहा था. घर में बेटे के रूप में एक चिराग भी रौशन हो चुका था कि अचानक साल भर का बच्चा टीबी का शिकार होकर काल के गाल में समा गया. इस विपदा से शौकत पूरी तरह से टूट गईं. अपने इस पहाड़ जैसे दुःख से उबरने की कोशिश में जब गमजदा शौकत को पता चला कि वह फिर से मां बनने जा रही हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. शौकत ने अपनी खुशी कम्यून में साझा की. जब शौकत की पार्टी (तब तक शौकत वामपंथी पार्टी की सदस्यता ले चुकी थीं?) को इसका पता लगा, तो उसने गर्भ गिरा देने का फरमान जारी कर दिया. यह वामपंथ का बेहद ही अमानवीय चेहरा है, जो इस पार्टी के लोकप्रिय न होने का एक बड़ा कारण है. पार्टी के इस अमानवीय फरमान के ख़िलाफ़ शौकत जब अड़ गईं, तो इस मसले पर पार्टी की बैठक बुलाई गई. तर्क-कुतर्क और तमाम बहसों के बाद शौकत की जिद के आगे पार्टी को झुकना पड़ा. शौकत कैफी को बच्चा पैदा करने की अनुमति मिली. कम्युनिस्ट पार्टी के इस अमानवीय चेहरे से गाहे-बगाहे उसके सदस्य ही पर्दा उठाते रहते हैं.

इस आपबीती के बाद जो दास्तान है, वह है कैफी और शौकत के संघर्ष की कहानी. कैफी के लगातार हौसला आफजाई के बाद शौकत नाटकों में और सक्रिय हो गईं और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं. एक अदाकारा के रूप में शौकत और शायर के रूप में कैफी की शोहरत बढ़ने लगी. शौकत को नाटकों के अलावा फिल्मों में काम मिला, तो कैफी ने भी कई बेहतरीन नगमे लिखे. शोहरत और उससे आए पैसे को कैफी और शौकत एन्जॉय कर रहे थे कि एक दिन इस हंसते-खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई और कैफी साहब बुरी तरह बीमार हो गए. शौकत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर इसे भी मित्रों के सहयोग से झेला. इसके अलावा कैफी के उत्तर प्रदेश के अपने गांव मिजवां के लिए किए गए कामों और अपने गांव-इलाके की बेहतरी के लिए कैफी की बेचैनी का भी विस्तार से विवरण है. साथ ही शौकत के पृथ्वी थिएटर के दिनों के भी दिलचस्प और रोचक किस्से हैं. कुल मिलाकर यह एक अद्भुत प्रेम कहानी है. अफसाना है दो दिलों का, जो तमाम दिक्कतों और संघर्षों के बावजूद एक-दूसरे पर दिलो-जान से फिदा हैं.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

लोकल

विमल चंद्र पांडेय
ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित

वे दोनों जब गोदौलिया चौराहे पहुंचे, तो सूरज निकलने में कुछ मिनटों का समय शेष था. सड़क के किनारे बैरीकेडिंग लगी थी और उसके भीतर लोटा लिए श्रद्धालुओं की जो लाइन थी, वह कई बार, कई जगहों पर मुड़कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और उन पर जल चढ़ाने के लिए व्याकुल थी.

कितना किलोमीटर होगा? मोटे लड़के ने पिछली सीट से उचक कर कतार का सिरा देखने की कोशिश करते हुए पूछा.

नापे हैं क्या हम? चश्मे वाले ने झल्लाहट में जवाब दिया.

भीड़ इतनी थी कि पैदल लोग भी चलने की बजाय सरक रहे थे. उन दोनों ने अपनी मोटर साइकिल घाट वाली सड़क की ओर बढ़ाई, जहां पुलिस का अस्थायी चेक पोस्ट बना था और कई वर्दी वाले खड़े देश की बढ़ती जा रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त कर रहे थे.

मोटर साइकिल की हेडलाइट कवर पर प्रेस लिखा था. पीछे बैठे मोटे लड़के ने गले में एक हैंडीकैम लटका रखा था और उसके हाथ में एक पन्नी थी, जिसमें कुछ अपाहिज़ हो चुके ईश्वर थे, जिन्हें गंगा में प्रवाहित करना था. मोटर साइकिल आगे बढ़ी, तो खाकी वर्दी वालों ने डंडा खड़काया.

आगे नहीं जाएगी गाड़ी.

प्रेस हैं, मोटर साइकिल चला रहे चश्मे वाले लड़के ने कहा. कहने में टोन थी कि वह प्रेस से है या फिर खुद प्रेस है.

प्रेस हो, मिक्सर हो, चाहे गीजर, आज गाड़ी आगे नहीं जाएगी, खाकी वर्दी ने बेतुकी तुक जोड़ते हुए आदेश फरमाया.

चश्मे वाले लड़के ने थोड़ी देर पुलिस वाले को घूरने के बाद मोटर साइकिल मारवाड़ी अस्पताल की तरफ़ मोड़ दी. खाकी वर्दी वाला निर्लिप्त भाव से देख रहा था. लड़के ने मोटर साइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी. फिर नाराज़गी भरे भाव से पुलिस वाले से बोला, अगर गाड़ी चोरी हुआ, तो आपका जिम्मेदारी होगा.

पुलिस वाला उदासीन भाव से बोला, आज क्या, कभी भी चोरी हुई, तो मेरी ही ज़िम्मेदारी होगी.

दोनों लड़के पैदल ही राजेंद्र प्रसाद घाट की ओर चलने लगे.

उसको फोन करो, कितनी देर में आ रहा है. पार्टी आज देगा या कल? मोटे ने उम्र में बड़े होने का फ़ायदा उठाना चाहा.

बनारस छोड़ के कोई बंबई जाएगा नौकरी करने, तो पार्टी तो उसका बाप भी देगा, चश्मे वाले ने महानगर की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला वक्तव्य दिया और फोन मिलाने लगा.

मोटा लड़का उसी चैनल में कैमरामैन था, जिसमें अब वह चश्मे वाला लड़का समाचार वाचक, पत्रकार और वीडियो एडिटर की बहुआयामी भूमिकाएं निभा रहा था. वह अभी हाल ही में शहर के एक विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करके आया था और तकनीकी रूप से अपेक्षाकृत जानकार था. इस चैनल में आते ही उसने अपने लिए अच्छा नाम और सम्मान, दोनों अर्जित कर लिया था. मोटे लड़के को सिर्फ़ कैमरा चलाना आता था और उसका अनुभव उस लड़के से कम से कम पांच साल अधिक था, लेकिन अब विडंबना यह थी कि उसे उस लड़के की जानकारियों के आगे एक तरह से उसके अघोषित सहायक की भूमिका निभानी पड़ रही थी. चैनल के मालिक ने उसे कई बार चश्मे वाले लड़के के सामने डांटा था और कहा था कि उसे अपने इस जूनियर सहकर्मी से कुछ सीखना चाहिए. दोनों साथ काम करते थे और शहर में यहां-वहां घूमकर ख़बरें इकट्ठी करते थे. उनके अन्य साथी, जो सेटेलाइट चैनलों के संवाददाता थे, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते थे. वे दोनों शहर के ही नाम पर चल रहे एक स्थानीय चैनल के पत्रकार थे. आज माघी पूर्णिमा यानी गंगा स्नान कर सभी पापों से एक झटके में छुटकारा पाने का धार्मिक ऑफर था और लोगों में काफी उत्साह था. चश्मे वाले ने मोटे लड़के को इशारा किया कि वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी अत्यधिक लंबी लाइन की एक फुटेज रिकॉर्ड कर ले और फिर अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा.

उसमें का है? हर सोमवार लाइन लगती है एतने लंबी, मोटे ने उसकी बात को भाव नहीं दिया.

हर सोमवार की बात अलग है. यहीं से स्टोरी उठाएंगे, तो सही रहेगा. माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का तांता... चश्मे वाले लड़के ने चैनलों के अख़बारों से आतंकित होने की पुष्टि करते हुए कहा, मगर मोटे ने उसे भाव नहीं दिया.

शिवरात्रि पर देखना, भीड़ देखनी हो तो..., कहकर मोटा आगे बढ़ गया. दोनों राजेंद्र प्रसाद घाट की सीढ़ियां उतरने लगे. घाट पर भीड़ थी और श्रद्धालु गंगा में नहाकर अपने पाप कम करने की कोशिश में थे. दोनों सीढ़ियां उतर कर सिंधिया घाट की तरफ़ जाने लगे.बोट पर चलेंगे, बोट पर चलेंगे सर? मल्लाहों के झुंड से एक लड़का उन दोनों के पीछे लग गया. मोटे ने पीछे पलट कर देखा. लड़के से उसकी नज़रें मिलीं.

बोट माने? उसने लड़के से पूछा.

नाव, लड़के ने इत्मीनान से उत्तर दिया.

तऽ पूरा हिंदी बोल, नाव पर चलेंगे? या तऽ फिर पूरा अंग्रेजी बोल..., इतना कहकर मोटे ने चश्मे वाले लड़के की ओर देखा. बाकी बात उसने पूरी की, विल यू कम ऑन माई बोट सर? मल्लाह लड़का समझ गया कि दोनों लोकल हैं. वह उछलता हुआ दूसरी तरफ़ निकल गया.

वे दोनों भीड़ में जगह बनाते हुए आगे बढ़े, तो एक सपेरा अपनी पिटारी खोलकर सांप दिखा रहा था. मोटा वहां से गुज़रा, तो सपेरे ने पिटारी उसके आगे बढ़ाते हुए उसका अभिवादन किया, जिसका अर्थ था कि उसकी पिटारी में कुछ पैसे डाल दिए जाएं.

महादेव...

असली हौ? मोटे ने पूछा. सवाल ने सपेरे को दुःखी कर दिया और वह सांप को पिटारी से निकाल कर मोटे की ओर बढ़ाने लगा.

कटवा के बतइबा का? मोटे ने मुस्कराते हुए कहा और आगे बढ़ गया. चश्मे वाले ने उसे आवाज़ दी.

सांप को नचवा के रिकॉर्डिंग कर लिया जाए क्या? उसने सलाह मांगी. मोटे को अच्छा लगा कि उसने सलाह मांगी है, आदेश नहीं दिया. उसने एक पल को सोचा, फिर प्रस्ताव को नकार दिया, सांप वाले तो बहुत मिल जाएंगे, एम्मे कोई बड़ी बात थोड़े है.

दोनों फिर चलने लगे. चश्मे वाला काफी देर से बार-बार फोन लगा रहा था और दूसरी तरफ़ से उसका फोन नहीं उठाया जा रहा था.

हद्द है..., वह फिर झल्लाया.

अरे जाने दो, सो रही होगी, मोटे ने कहा.

नहीं यार, उसके मामा के यहां सब सुबेरहीं उठ जाते हैं. उठ गई होगी. उसने फिर से नंबर लगाया. इस बार फोन उठा लिया गया. मोटा थोड़ा आगे हो गया लेकिन उसके कान फोन की बातों पर ही लगे थे.

आधा घंटा से परसान हैं. तो? रोमिंग में होगी, तो फोने नहीं उठाओगी? कोई मर जाए और तुम बिल बचाती रहो. अरे यार, गजब बात करती हो. अच्छा गुस्साओ मत, हम आए हैं स्नान पर स्टोरी बनाने. ठीक है, हम करा देंगे रिचार्ज. हमको एक घंटे बाद करो मिसकाल, ठीक है? भूलना मत.

फोन काटने के बाद वह मोटे के पास पहुंचा. मोटे ने चाल धीमी कर दी थी. ई रोमिंग का बहुत लफड़ा है. चश्मे वाले ने निराश आवाज़ में कहा.

वो कहां पहुंचा, पूछो, मोटे ने अचानक पलट कर कहा, तो चश्मे वाला लड़का फोन मिलाने लगा.

पहुंच जाएगा पांच मिनट में, सुलभ शौचालय के पास है अभी, चश्मे वाले ने फोन काटकर कहा.

निपट कर नहीं आया था का घरे से? मोटे ने कहा और सामने से आ रही दो विदेशी युवतियों को देखने लगा. उसकी नज़र युवती के स्तनों पर थी.

लटक गया है कम उमर में ही, उसने चिंताग्रस्त होकर चश्मे वाले से कहा.

चश्मे वाले ने भी मुआयना किया, इतनी कम उमर भी नहीं है. हमारे यहां तो तीसे साल में...

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

लावा का 3जी स्मार्टफोन आइरिस 350एम

भारतीय मोबाइल कंपनी लावा ने एक नया सस्ता स्मार्टफोन आइरिस 350 एम बाजार में उतारा है. यह 1.2 जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर से लैस है और बेहद हल्का है. यह डुअल सिम फोन है और 3जी को सपोर्ट करता है. इसका स्क्रीन 3.5 इंच का है और इसका रेजोल्यूशन 480 गुणा 320 पिक्सल है. इस फोन में 256 एमबी का रैम है. इस फोन का कैमरा 2 एमपी का है. इसमें अन्य फीचर–3जी, जीपीएस, ब्लूटुथ, वाई–फाई है. इसकी बैटरी 14 एमएएच की है जो 5 घंटे का वीडियो टाइम देती है. इसकी कीमत 3,500 रुपये है. ■

एलजी का 4जी आइसक्रीम स्मार्ट लॉन्च

एलजी ने अपना नया फ्लिप फोन आइसक्रीम स्मार्ट पेश कर दिया है. एंड्रॉयड आधारित यह मोबाइल 1.2 जीएचजेड क्वॉड कोर प्रोसेसर से लैस है. इसमें 8एमपी कैमरा है और वीजीए फ्रंट कैमरा है. यह 4जी फोन है और इसका स्क्रीन 3.5 इंच का है, जो 320 गुणा 480 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसका स्पीकर 1वॉट का है. इसमें 1.2 जीएचजेड क्वॉड कोर का प्रोसेसर है. साथ ही इसमें 1जीबी रैम जिसे 8 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है. यह फोन एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसमें अन्य फीचर–4जी, वाई–फाई, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस, डीएमबी है.

इसकी बैटरी 1700 एमएएच की है. ■

विंडोज-10 की कुछ खास बातें

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुचर्चित विंडोज 10 आपरेटिंग सिस्ट में को पिछले महनी लॉन्च कर दिया है. कंपनी पूरी तरह से इस सभी फीचर को सबके सामने रखा है. विंडोज 10 में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपको विंडोज एक्सपी की भी याद दिलाएंगी और विंडोज 8.1 जैसा या उससे भी बेहतर ग्राफिक इंटरफेस का अनुभव देंगे. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि विंडोज 10 उनका अब तक का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज 10 के फीचर्स पर एक नजर डालें तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मोबाइल और कंप्यूटर दोनों तरह की एप्लीकेशन आराम से इस्तेमाल की जा सकती है. आईए नजर डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट के खास फीचर्स पर.....

1. स्टार्ट मेन्यू का नया अवतार

विंडोज 10 में आपको एक बार फिर स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार इसका लुक कुछ नया होगा. खास बात ये भी है कि स्टार्ट मेन्यू कंप्यूटर के साथ ही मोबाइल में भी नजर आएगा. स्टार्ट मेन्यू अपने पुराने रूप में तो होगा ही इसमें विंडोज 8 की तरह टाइल्स के रूप में शॉर्टकट भी होंगे, जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं.

2. स्मार्टफोन की स्क्रीन पर डेस्कटॉप का मजा

विंडोज 10 मोबाइल पर भी डेस्कटॉप का मजा देगा. विंडोज 10 के साथ आप अपने स्मार्टफोन में डेस्कटॉप जैसा काम कर सकते हैं. यही नहीं इससे डेस्कटॉप और फोन के बीच सिंक भी आसान होगा. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की स्काइप सेवा विंडोज 10 में मैसेजिंग ऐप के रूप में दी गई है. अब तक विंडोज स्मार्टफोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इसमें इंस्टाग्राम और जीमेल जैसे ऐप सही से नहीं चलते थे, लेकिन विंडोज 10 के साथ अब आपका स्मार्टफोन सिर्फ फोन न रहकर विंडोज डिवाइस हो जाएगा और इस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी.

3. डेस्कटॉप पर भी कोरटाना

माइक्रोसॉफ्ट के पर्सनल डिजिटल एसिस्टेंट कोरटाना का इस्तेमाल विंडोज स्मार्टफोन यूजर्स पहले से ही कर रहे हैं, अब यह विंडोज 10 के साथ डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध होगा. स्टार्ट बटन के साथ ही टास्कबार पर अब कोरटाना भी यूजर्स को दिखेगा. यह विंडोज 10 के लिए नैचुरल लैंग्वेज इंटरफेस की तरह काम करेगा. यह आपके सवालों का जवाब देगा. यही नहीं यह आपके लोकल डॉक्यूमेंट को तो खंगालेगा ही साथ ही वनड्राइव में भी आपके सवाल का जवाब ढूंढकर आपके सामने लाएगा. कोरटाना नए मैप ऐप से भी जुड़ा होगा, जो आपको याद दिलाएगा कि आपकी कार कहां खड़ी है. यही नहीं आपकी पसंद के अनुसार कोरटाना आपको फ्लाइट्स, स्टॉक्स, स्पोर्ट्स और अन्य नोटिफिकेशन देता रहेगा.

4. स्पारटन ब्राउजर

हम सब ने सालों तक इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया है. लेकिन बाद के दिनों में मोजिला, क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउजर के आने के कारण यह पिछड़ता चला गया. यही नहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर ने इस बीच खूब आलोचनाओं का भी सामना किया. लेकिन विंडोज 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक नया ब्राउजर स्पारटन लेकर आया है. स्पारटन ब्राउजर इससे पहले के इंटरनेट एक्सप्लोर से साफ-सुथरा और नए फीचर्स से लोडेड है, कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट की अन्य सेवाएं पहले से ही इंटीग्रेटिड हैं. इनके अलावा भी इस ब्राउजर में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो संभवत: मौजूदा किसी भी ब्राउजर में आपको नहीं मिलेंगी.

5. कम्प्यूटर को बन सकते हैं एक्सबॉक्स

विंडोज 10 मोबाइल पर भी डेस्कटॉप का मजा देगा. विंडोज 10 के साथ आप अपने स्मार्टफोन में डेस्कटॉप जैसा काम कर सकते हैं. यही नहीं इससे डेस्कटॉप और फोन के बीच सिंक भी आसान होगा. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की स्काइप सेवा विंडोज 10 में मैसेजिंग ऐप के रूप में दी गई है.

माइक्रोसॉफ्ट के पास कम्प्यूटर गेम्स की अच्छी खासी वैरायटी है. इसके अलावा गेमिंग कंसोल (एक्सबॉक्स) की मार्केट में भी कंपनी अच्छे-अच्छों को टक्कर देती है. अब विंडोज 10 के साथ कंपनी ने एक्सबॉक्स ऐप की घोषणा कर दी है. इस ऐप में एक्सबॉक्स वन के मैसेजे, फ्रेंड लिस्ट और एक्टीविटी फीड मिलेंगे. इस ऐप की मदद से आप एक्सबॉक्स लाइव पर लोगों से चैट कर सकते हैं, कंसोल के अचीवमेंट्स देख सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से वीडियो देख और वीडियो क्लिप बना भी सकते हैं.

6. फोन पर भी पावरप्वाइंट प्रजेंटेशन होगा

विंडोज 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट की कोशिश है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन एक साथ अच्छे से काम करें. इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने युनिफाइड ऑफिस पेश किया है. अब मोबाइल और टैबलेट पर भी ऑफिस उसी तरह से चलेगा जिस तरह से यह डेस्कटॉप या लैपटॉप पर चलता है. विंडोज 10 के साथ हर प्लेटफॉर्म पर ऑफिस में एक जैसे फीचर्स और फॉर्मेटिंग ऑप्शन्स देखने को मिलेंगे. यही नहीं मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के बीच रीसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट को भी सिंक किया जा सकता है. खास बात यह भी है कि विंडोज 10 के साथ आप अपने मोबाइल से ही वायरलैस प्रिंट भी ले सकेंगे.

7. विंडोज 10 में वनड्राइव की अहम भूमिका

विंडोज 10 में वनड्राइव की बहुत बड़ी भूमिका होगी. माइक्रोसॉफ्ट की इस क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल विंडोज 10 के साथ काफी ज्यादा बढ़ेगा. विंडोज 10 के लॉन्च प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने वनड्राइव को हर जगह दिखाने का प्रयास किया. यह क्लाउड सर्विस अलग-अलग डिवाइसों के बीच में डॉक्यूमेंट सिंक करने में भी इसकी खास भूमिका होगी. फोटो और म्यूजिक के मामले में भी वनड्राइव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. यह विंडोज 10 पर ऑपरेट होने वाली दो डिवाइसों के बीच म्यूजिक सिंक करने में अहम किरदार निभाएगा.

8. नए रूप में मेल क्लाइंट आउटलुक

माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिवर्सल आउटलुक ऐप में पूरा वर्ड इंजन बना दिया है. इसमें मैसेज डिलीट करने या फ्लैग करने के लिए आईओएस जैसा स्वाइपिंग फीचर होगा. आउटलुक का कम्प्यूटर वर्जन मौजूदा मेल क्लाइंट से बहुत ज्यादा साफ-सुथरा होगा. यह आपको रिमाइंडर, एक्सचेंज एक्टिवल सिंक, पीपल हब जैसी सुविधाएं देगा.

आईसीसी का लाइव क्रिकेट ऐप

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल(आईसीसी) ने रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मिलकर आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट ऐप 2015 लॉन्च किया है. ये ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों ही ऐप स्टोर्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट 14 फरवरी 2015 से शुरू होने वाला है. इस इवेंट की सभी डिटेल्स आईसीसी के आधिकारिक ऐप से मिल जाएंगी. इस ऐप में कई यूनिक फीचर्स दिए गए हैं जिससे यूजर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का मजा ले सकते हैं.

फीचर्स–

आईसीसी लाइव मैच सेंटर जिसमें बॉल टू बॉल स्कोर और कमेंट्री शामिल है. मैच की एक्सक्लूसिव वीडियो हाइलाइट्स

अपनी टीम को सपोर्ट करने का चांस

स्कोर नोटिफिकेशन

टूर्नामेंट स्टैट्स

ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

मैच रिपोर्ट्स

क्रिकेट वर्ल्ड कप लेजेंड्स के बारे में जानकारी इन सभी फीचर्स के साथ कुछ और फीचर्स भी शामिल हैं. इस ऐप का साइज 21एमबी का है. ■

सैमसंग सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी जे1

कोरियाई कंपनी सैमसंग ने अपना नया सस्ता स्मार्टफोन जे1 लॉन्च किया है. इस फोन की स्क्रीन 4.3 इंच की है और यह 1.2 जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर से लैस है. यह ऐंड्रॉयड फोन है और डुअल सिम सुविधा के साथ है. इसका रियर कैमरा 5एमपी का है जबकि फ्रंट में 2एमपी कैमरा है. इसका स्क्रीन 800 गुणा 480 पिक्सल का रेजोल्यूलशन देता है. इसमें 1.2 जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर है. इसमें 512 एमबी का रैम है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 4जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह ऐंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसमें अन्य सुविधा एफएम रेडियो, 3जी, वाई-फाई 802.11, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस उपलब्ध है. इस फोन की बैटरी 1850 एमएएच की है, जो अल्ट्रा पॉवर सेविंग मोड के साथ आती है. ■

मारुति स्विफ्ट की नई मॉडल

मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट का नया संस्करण पेश किया है. यह लिमिटेड एडिशन है और इसे स्विफ्ट विंडसॉन्ग का नाम दिया गया है. इस कार को सिर्फ स्विफ्ट वीएक्सआई और वीडीआई ट्रिम मॉडल में ही लाया गया है. इसमें बॉडी ग्राफिक्स, फ्रंट और रियर मडफ्लैप और रियर स्पॉयलर जैसे बाहरी बदलाव किए गए है. बॉडी ग्राफिक्स के कारण यह कार बेहद आकर्षक हो गई है. इस कार को अंदर से आकर्षक बनाने के लिए खास किस्म के सीट कवर और स्टियरिंग व्हील कवर, दरवाजों के चमकदार चौखट और खूबसूरत लाइटिंग भी की गई है. इसमें संगीत के शौकीनों के लिए सोनी टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम भी है. इसके अलावा इसमें सीडी. डीवीडी, ब्लूटुथ, यूएसबी वगैरह की सुविधा भी है. इसमें रिवर्स पार्किंग के लिए कैमरा भी है. यह 1.2 लीटर के 12 इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन से चलेगी. कंपनी ने इसकी कीमत वीएक्सआई मॉडल के लिए 5.14 लाख रुपये और वीडीआई के लिए 6.1 लाख रुपये रखी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पाकिस्तानी गेंदबाज आमिर की वापसी

एसीएसयू प्रमुख रोनी फ्लैगानान ने कहा कि वह प्रतिबंध की इस मियाद के दौरान आमिर के बर्ताव और एसीएसयू के साथ उनके सहयोग से प्रभावित और संतुष्ट हैं. इसी वजह से उनका प्रतिबंध समय से पहले समाप्त किया जा रहा है. 22 साल के गेंदबाज आमिर के साथ पाकिस्तान के कई अन्य खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा था, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालिक कप्तान सलमान बट्ट भी शामिल थे.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने प्रतिबंध का सामना कर रहे पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाद मोहम्मद आमिर को राहत देने का निर्णय लिया है. साल 2010 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में लिप्त पाये जाने के बाद उन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था. अब वह घरेलू क्रिकेट खेल सकेंगे.

आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधी एवं सुरक्षा इकाई(एसीएसयू) ने दुबई में हुई बोर्ड मीटिंग के दौरान उनके प्रतिबंध में कटौती करते हुए, आमिर को क्रिकेट में लौटने की अनुमति दे दी है. हालांकि, आमिर का प्रतिबंध इसी साल 2 सितंबर को समाप्त हो रहा है. एसीएसयू प्रमुख रोनी फ्लैगानान ने कहा कि वह प्रतिबंध की इस मियाद के दौरान आमिर के बर्ताव और एसीएसयू के साथ उनके सहयोग से प्रभावित और संतुष्ट हैं. इसी वजह से उनका प्रतिबंध समय से पहले समाप्त किया जा रहा है. 22 साल के गेंदबाज आमिर के साथ पाकिस्तान के कई अन्य खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा था, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालिक कप्तान सलमान बट्ट भी शामिल थे. बट्ट पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था. आईसीसी कम उम्र होने की वजह से आमिर के प्रति नर्म रुख अख्तियार किया था और अंततः प्रतिबंध समाप्त होने के पहले उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलने की अनुमति दे दी, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मजबूती से वापसी के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर सकें.■

भारत में अगले साल होगा टी-20 विश्वकप

International Cricket Council

भारत साल 2016 में होने वाले टी-20 विश्वकप की मेजबानी करेगा. इसके अलावा साल 2023 के आईसीसी वन-डे विश्वकप की मेजबानी भी भारत को सौंपी गई है. टी-20 विश्वकप का आयोजन अगल साल मार्च-अप्रैल के दौरान होगा. साल 2019 के वन-डे विश्वकप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा इसका आयोजन 30 मई से 19 जुलाई के बीच होगा. टी-20 विश्वकप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन 6 से 26 जुलाई के बीच स्कॉटलैंड में होगा. आईसीसी अंडर-19 विश्वकप का आयोजन इस साल बांग्लादेश में होगा. साल 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1 से 19 जुलाई के बीच आयोजित की जायेगी.■

ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख

खेल मंत्रालय ने स्कीम ऑफ स्पेशल अवार्डस में संशोधन करते हुए ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि में इज़ाफा किया है. अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 30 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे. पहले इसके लिए पहले क्रमश: 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपये दिए जाते थे. इसी तरह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर यह राशि 20,10 और 10 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30,20 और 10 लाख रुपये कर दिया गया है. जहां तक विश्वकप, एशिया कप और विश्व चैंपियनशिप की बात है तो खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि इस पर निर्भर करेगी कि ये आयोजन चार साल में एक बार होते हैं या इनका आयोजन साल में एक बार या दो साल में एक बार होता है. पैरालंपिक, पैरा एशियाई खेलों और पैरा कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बराबर ही पुरस्कार राशि दी जाएगी. ■

संगकारा का नया विश्व रिकॉर्ड

श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज़ कुमार संगकारा ने एकदिवसीय क्रिकेट में नया विश्व रिकार्ड बनाय है. संगकारा ने एकदिवसीय मैचों में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के 472 शिकार के रिकॉर्ड को तोड़कर 474 शिकार करने का रिकॉर्ड बनाया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सात मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 2 कैच लपककर संगकारा ने यह रिकॉर्ड बनाया. सबसे ज्यादा कैच लेने वालों की सूची में दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर 424 शिकार के साथ तीसरे , टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 314 शिकार के साथ चौथे स्थान पर हैं. सीरीज के दौरान ही संगकारा श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले एकदिवसीय बल्लेबाज भी बने. अब उनके 13434 रन है, उन्होंने सनत जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ा. सबसे ज्यादा एकदिवसीय रन बनाने वालों की सूची में सचिन तेंदुलकर 18,424 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

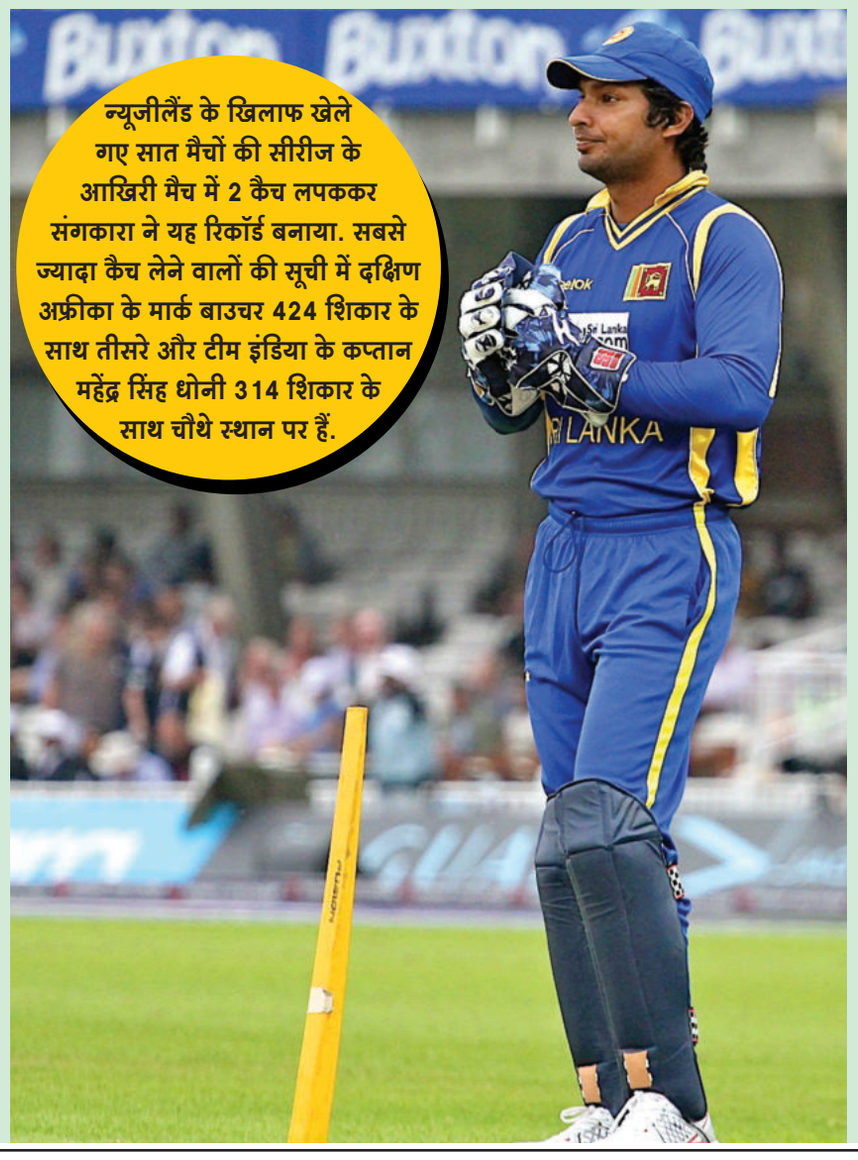

समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के गणतांत्रिक
मूल्यों के साथ विकास पथ पर बढ़ता प्रदेश।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएं

गणतांत्रिक मूल्यों के साथ
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2015

धनुष के मुरीद हुए अमिताभ

षमिताभ में अभिनेता धनुष के साथ काम करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन उनके मुरीद हो गये हैं. धनुष ने षमिताभ में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, लेकिन अमिताभ उन्हें अभी से बड़ा स्टार मानने लगे हैं. ऐसा लगता है कि धनुष का फिल्मी करियर उज्जवल है. अमिताभ को अपनी एक ही फिल्म से अपना मुरीद बना देना इतना आसान नहीं है. निश्चित तौर पर धनुष में बेहतरीन अभिनय तथा स्टार बनने की काबलियत है जिसे अमिताभ ने पहली नज़र में ही पहचान लिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिग बी ने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं. मैंने उनकी दक्षिण भारतीय फिल्में देखी हैं. मैंने रांझणा भी देखी है. वह एक बहुत कुशल अभिनेता और बड़े स्टार हैं. दूसरी तरफ धनुष भी अमिताभ से अत्यंत प्रभावित हैं. उन्होंने अमिताभ की फिल्मों के रीमेक में काम करने के सवाल पर कहा कि मैं उनकी फिल्में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे सफल बनाने का माद्दा नहीं रखता. मेरे में उनकी फिल्में करने जितनी काबिलियत नहीं है. जहां तक उनकी फिल्मों का सवाल है, मुझे शोले और दीवार बहुत पसंद है. षमिताभ में धनुष के किरदार पर बात करते हुए अमिताभ ने कहा कि इस किरदार के लिए धनुष का चुनाव अद्भुत है. षमिताभ में धनुष के किरदार के लिए पहले शाहरुख़ खान को प्रस्ताव दिया गया था. अमिताभ ने कहा कि अब, जब मैंने अपनी फिल्म को करीब-करीब देख लिया है. तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि धनुष को चुनना सबसे सही फैसला था. षमिताभ को आर. बाल्की ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म षमिताभ में अमिताभ ने धनुष को अपनी आवाज़ दी है. ■

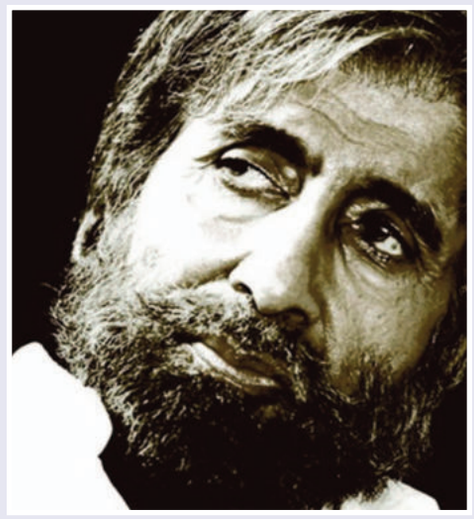

हैप्पी न्यू ईयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हकदार नहीं : शाहरुख़

करियर के शुरुआती दिनों का ज़िक्रकरते हुए शाहरुख ने कहा कि, मुझे अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी पुरस्कार मिल चुके हैं लिहाजा मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है. मुझे पुरस्कार मिले या न मिले, लेकिन मैं आज भी पुरस्कार समारोह का हिस्सा बने रहना चाहता हूं, क्योंकि फिल्मी करियर की शुरुआत में इन्हीं पुरस्कारों ने मुझे आत्मविश्वास दिया था.

बॉलीवुड के किंग ख़ान शाहरुख़ ख़ान का कहना है कि वह फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के हक़दार नहीं हैं. शाहरुख ने पिछले साल इस फिल्म में काम किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तरीके से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म एक कॉमेडी-ड्रामा थी. शाहरुख का मानना है कि इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तो दूर-दूर तक नामांकित नहीं किया जाना चाहिए. शाहरुख को हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया. इस पर उन्होंने कहा कि, पिछले साल कई अभिनेताओं ने अच्छा काम किया है और खुद को साबित किया है. हैप्पी न्यू ईयर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, लेकिन बतौर अभिनेता मैंने फिल्म में कोई खास कमाल नहीं किया है. करियर के शुरुआती दिनों का ज़िक्र करते हुए शाहरुख़ ने कहा कि, मुझे अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी पुरस्कार मिले हैं लिहाजा मेरे लिए यह महत्वपूर्ण हैं. मुझे पुरस्कार मिले या न मिले, लेकिन मैं आज भी पुरस्कार समारोह का हिस्सा बने रहना चाहता हूं, क्योंकि फिल्मी करियर की शुरुआत में इन्हीं पुरस्कारों ने मुझे आत्मविश्वास दिया था. ■

जैकलीन बनेगी संगीता बिजलानी

श्रीलंकाई बाला जैकलीन फर्नांडीज बॉलीवुड में सफलता की राह पर चल पड़ी हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन के जीवन पर बन रही बायोपिक में उनकी दूसरी पत्नी का किरदार जैकलीन निभायेंगी. जबकि उनकी पहली पत्नी नौरीन के किरदार में प्राची देसाई नज़र आयेंगी. फिल्म में इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में होंगे. पहले कयास लगाए जा रहे थे संगीता बिजलानी का किरदार करीना कपूर अदा करेंगी. लेकिन डेट्स की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया. फिल्म का निर्देशन एंथनी डिसूजा करेंगे. बॉलीवुड में खिलाड़ियों की जिंदगी पर बॉयोपिक बनने का नया चलन शुरू हुआ है. दर्शक इस तरह की फिल्मों को पसंद भी कर रहे हैं. मिल्खा सिंह, मैरीकॉम और महेंद्र सिंह धोनी के बाद किसी खिलाड़ी के जीवन पर बनने वाली यह चौथी फिल्म होगी. ऐसे भी संगीता बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं, ऐसे में उनका किरदार निभाना जैकलीन के लिए थोड़ा आसान होगा. ■

श्रद्धा ने बांधे कंगना की तारीफों के पुल

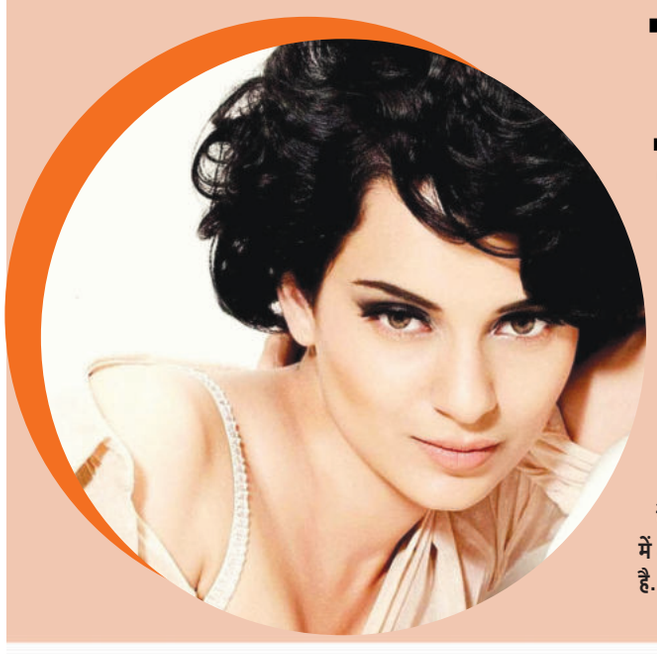

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने पिछले साल आई फिल्म क्वीन में कंगना रनौत के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है. श्रद्धा ने ट्वीट किया कि, मैं बेहद खुश हू, मैं यह कह सकती थी कि मुझे क्वीन में कंगना बेहद पसंद आईं? आखिरकार आपको सबसे बड़ा पुरस्कार प्रशंसकों से ही मिल सकता है. इसके साथ ही श्रद्धा ने ट्विटर पर कंगना और अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. विकास बहल द्वारा निर्देशित फिल्म क्वीन में कंगना ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो अपनी शादी टूटने के बाद अकेले ही हनीमून पर निकल जाती है. उनके इस किरदार ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया था. कंगना अपने अभिनय के बल पल पर पहले भी लोगों को मोह चुकी हैं. फिल्म फैशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. कंगना ने बॉलीवुड में अपनी मेहनत के बल पर यह मुक़ाम हासिल किया है. समय के साथ उनके अभिनय में निखार आता जा रहा है. श्रद्धा के रूप में उनके मुरीदों की सूची में एक नाम और जुड़ गया है. ■

कुणाल की हुई सोहा

सोहा अली खान और कुणाल खेमू हाल ही में शादी के बंधन में बंध गये. गौरतलब है कि यह दोनों लंबे समय से साथ हैं, इनकी शादी को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रही है. पिछले साल के आखिर में दोनों ने पेरिस में सगाई की थी. यह शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में परिवार के लोगों के बीच हुई. क्रीम और ऑरेंज कलर के दुल्हन के लिबास में सोहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं. वहीं कुनाल क्रीम कलर के कुर्ते और कलरफुल साफे में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे. शादी के मौके पर छोटे नवाब सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर, सोहा की छोटी बहन सबा, मां शर्मिला टैगोर मौजूद थीं. शादी में सैफ का बेटा अब्राहम भी शरीक हुआ. लेकिन शादी में सैफ की पूर्व पत्नी अमृता सिंह और बेटी सारा कहीं नज़र नहीं आईं. ■

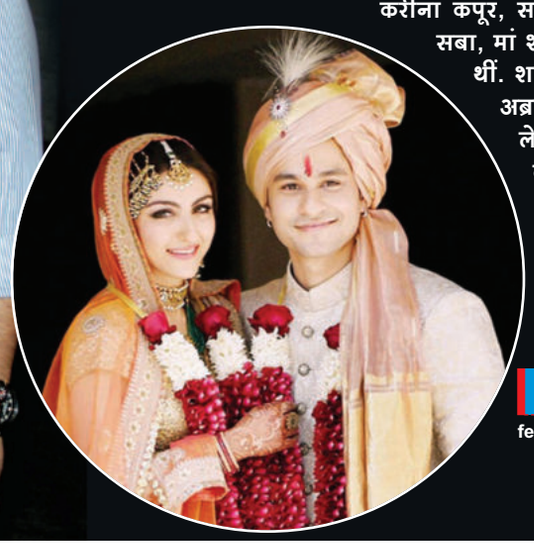

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

09 फरवरी–15 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

जदयू में टूट से पासवान और कुशवाहा को नुक़सान

भाजपा चाहती है कि जो भी मंत्री या विधायक जदयू से आएं, वे भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ें, न कि अलग गुट के तौर पर तालमेल करके. यदि बागी गुट ने भाजपा की इस शर्त को मान लिया तो भाजपा के सहयोगी दलों यानि कि लोजपा और रालोसपा की सीटों में भारी कटौती हो सकती है. समय आने पर भाजपा अपने सहयोगी दलों से यह साफ कर देगी कि उन्हीं सीटों की मांग कीजिए जिन पर जीत की पूरी संभावना हो, अन्यथा केवल संख्या बढ़ाने के लिए सीटें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है.

सरोज सिंह

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे की कवायद तेज हो जाएगी. हालांकि भाजपा चाहती है कि फिलहाल इस तरह की कवायद से दूर रहा जाए और संसद के बजट सत्र के बाद इस मसले पर आधिकारिक तौर पर प्रारंभिक बातचीत की जाए, लेकिन भाजपा के सहयोगी दलों की सोच कुछ और ही है. रालोसपा और लोजपा दोनों सहयोगी दलों के नेता चाहते हैं कि, जितनी जल्दी हो सीटों के बंटवारे पर फैसला कर लिया जाए. बिना लाग-लपेट के कहा जाए तो भाजपा के दोनों सहयोगी दल, सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ सशंकित हैं. सार्वजनिक तौर पर इन दलों के नेता भले ही यह कह रहे हों कि उचित समय पर सम्मानजनक समझौता हो जायेगा और इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है. लेकिन अंदरखाने जबरदस्त बेचैनी है. खासकर महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन के मामले को जिस तरह निपटाया, उससे कहीं न कहीं सहयोगी दलों को लग रहा है कि कहीं भाजपा उन्हें बीच मझधार में न छोड़ दे.

झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश भाजपा के तेवर और भी कड़े हो गए हैं. इस पर अमित शाह ने पटना आकर जो मंत्र पार्टी नेताओं को दिया है उससे साफ है कि भाजपा जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. खासकर मिशन-185 का जो लक्ष्य अमित शाह ने तय किया है उसकी रणनीति बनाने में सहयोगी दलों की हक मारा जा सकता है. पहले सभी यह मान कर चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, उसी आधार पर विधानसभा चुनावों में भी सीटों का तालमेल होगा. आमतौर पर एक लोकसभा सीट पर छह विधानसभा सीटों का हिसाब बनता है. इस लिहाज से यह माना जा रहा था कि लोजपा को 42-50 सीटें, रालोसपा को 18-25 सीटें दी जा सकती हैं. हालांकि सहयोगी दलों की मांग बहुत ज्यादा है. लोजपा ने 80 सीटों पर अपना होमवर्क शुरू किया है, वहीं रालोसपा ने 40 सीटों का लक्ष्य रखा है. यह बात रालोसपा और लोजपा के नेता भी जानते हैं कि इतनी सीटों पर भाजपा के साथ तालमेल नहीं बनेगा, लेकिन दबाव बनाने की रणनीति के तहत फिलहाल पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेताओं से इस तरह की बात कहलवाई जा रही है. लेकिन भाजपा के मन में कुछ और ही है. जानकार सूत्रों के अनुसार भाजपा ने तालमेल के खेल के लिए जो नियम बनाए हैं, उसमें दबाव की कोई जगह नहीं है. बुलंद हौसले से लबरेज भाजपा चाहती है कि सहयोगी दलों के साथ ताल-मेल बनाकर ही चुनावी अखाड़े में उतरा जाये, लेकिन वह अपने ऊपर दबाव के किसी भी एजेंडे को लागू नहीं करेगी. भाजपा अपने सहयोगी दलों को यह बात साफ-साफ बतायेगी कि, उनका लक्ष्य चुनाव जीतना है इसलिए सीटों के आंकड़ों में न फंसा जाए.

झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश भाजपा के तेवर और भी कड़े हो गए हैं. इस पर अमित शाह ने पटना आकर जो मंत्र पार्टी नेताओं को दिया है उससे साफ है कि भाजपा जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. खासकर मिशन-185 का जो लक्ष्य अमित शाह ने तय किया है उसकी रणनीति बनाने में सहयोगी दलों की हक मारा जा सकता है. पहले सभी यह मान कर चल जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ उसी के आधार पर विधानसभा चुनावों में भी सीटों का तालमेल होगा.

लोकसभा चुनाव में बात कुछ और थी, अब हालात बिल्कुल अलग हैं. केंद्र में अकेले के दम पर पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद भाजपा ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई. उन्हें पूरा सम्मान दिया गया. अब इन दोनों दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि विधानसभा चुनाव में वे भाजपा का दिल से सहयोग करें. भाजपा ने अपना आंतरिक सर्वे कराया है उसके अनुसार ज्यादातर सीटों पर लोजपा और रालोसपा के पास चुनाव लड़ने के लिए गंभीर उम्मीदवार ही नहीं हैं. अमित शाह ने बिहार की सभी 243 सीटों का फीडबैक पार्टी नेताओं से लिया है. भाजपा मानती है कि प्रत्येक सीट पर बेहद कड़ा मुक़ाबला होगा. एक-एक सीट महत्वपूर्ण है इसलिए किसी भी सीट पर वाकओवर देने जैसी स्थिति नहीं आने दी जायेगी. इसलिए समय आने पर भाजपा अपने सहयोगी दलों से यह बात स्पष्ट कर देगी कि केवल उन्हीं सीटों की मांग कीजिए जिन पर जीत की पूरी संभावना हो, अन्यथा केवल संख्या बढ़ाने के लिए सीटें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है. चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए हर हाल में चुनावी रणनीति कुछ ऐसी बनेगी जिससे कि चूक की गुंजाइश कम से कम रहे.

जदयू में उठ रहे बागी तेवरों ने भी लोजपा और रालोसपा की दिक्कतें बढ़ा दी हैं. नीतीश कुमार से नाराज जदयू के कई मंत्री और विधायक भाजपा के संपर्क में हैं. यह बात अब किसी से छिपी भी नहीं है. सूबे के जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें दिन-ब-दिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जिस तरह दूरी बढ़ती जा रही है. ऐसे में इस बात की संभावना है कि जदयू का एक बड़ा धड़ा चुनाव से ठीक पहले जदयू से अलग हो सकता है. यह गुट इस फिराक में है कि भाजपा के साथ तालमेल कर चुनावी अखाड़े में उतरा जाए. लेकिन भाजपा के सूत्र बताते हैं कि भाजपा तालमेल से ज्यादा विलय के विकल्प पर जोर देगी. भाजपा चाहती है कि जो भी मंत्री या विधायक जदयू से आएं, वे भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ें, न कि अलग गुट के तौर पर तालमेल करके. यदि बागी गुट भाजपा की इस शर्त को मान लेता है तो भाजपा के सहयोगी दलों यानि कि लोजपा और रालोसपा की सीटों में भारी कटौती हो सकती है.

भाजपा चाहती है कि जीतने की ताकत रखने वाले जो भी मंत्री और विधायक जदयू को छोड़कर उनका साथ लेना चाहते हैं वे पार्टी में शामिल हो जायें और कमल के निशान के साथ चुनावी अखाड़े में कूदें, ताकि मिशन-185 को हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए. यदि ऐसा हुआ तो रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मनमुताबिक सीटें मिलने में दिक्कत आ सकती है. भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि जीतन राम मांझी का साथ उन्हें मिल गया तो 22 फीसदी दलित और महा-दलित वोटों का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है. ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए लोजपा और रालोसपा का टिकटों का कोटा कम करना मजबूरी हो जायेगी. इसलिए भाजपा अभी सीटों के तालमेल के चैप्टर को बंद ही रखना चाहती है, और सूबे के रोज बदलते राजनीतिक समीकरणों और हालात को देखकर चुनाव से ठीक पहले इस चैप्टर को खोलना चाहती है. सहयोगी दलों को भी इसका अहसास है इसलिए वे चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए. लोजपा प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस तो बार-बार यह कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सीटों का तालमेल कर लिया जाए ताकि कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुट सकें. लोजपा ने अभी से ही 80 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है. ये वे 80 सीटें हैं जिन्हें लोजपा ने अपने हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए अनुकूल माना है. अब इन 80 सीटों में से भाजपा कितनी सीटों पर राजी होती है यह तो वक्त ही बताएगा.

दूसरी तरफ रालोसपा ने पूरे बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है. उपेंद्र कुशवाहा जिलावार पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं. रालोसपा को उम्मीद है कि एनडीए एक बेहतर तालमेल के साथ चुनावी अखाड़े में उतरेगा. पार्टी को उम्मीद है कि लोकसभा में मिली सीटों को सीटों के बटवारे का आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जमीन पर पार्टी की बढ़ी हुई ताकत का सहयोगी दल सम्मान करेंगे. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान कहते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और लोकसभा चुनाव के समय जो तेवर था उसी तेवर के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव में भी अखाड़े में उतरेंगे. सीटों के तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आयेगी. हमारे बड़े नेता बेहद परिपक्व हैं और बिहार की जमीनी राजनीतिक हक़ीकत को सभी समझते हैं. रालोसपा ने जिलास्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का अभियान छेड़ रखा है. सदस्यता अभियान को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. इसलिए हमें उम्मीद है कि सीटों के बंटवारे में रालोसपा की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

वार्षिक विक्रेता सम्मेलन आयोजित

देश की अग्रणी सीमेंट कंपनी जेपी सीमेंट ने पटना के एस के मेमोरियल हॉल में बिहार के 1000 से अधिक विक्रेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया तथा प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक जिले के तीन सर्वाधिक विक्रेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया तथा सितंबर माह की प्रोत्साहन स्कीम के तहत बिहार के 650 स्टॉकिस्टों को तनिष्क ज्वैलरी, मोटर साईकिल, स्कूटी, एलईडी टीवी, लैपटॉप, टैब, हैंडीकैम,फ्रिज, वाशिंग मशीन, कैमरा, घड़ी आदि का वितरण किया गया. इस अवसर पर कंपनी के श्री एस के पी गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विपणन) ने कहा कि जेपी सीमेंट इस देश के उपभोक्ताओं को निरंतर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध श्री पीपी सिंह, उपाध्यक्ष (विपणन) ने उपस्थित विक्रेताओं को बताया इस अवसर पर बिहार से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने-वाले मैसर्स गीता ट्रेडर्स, मैसर्स राय ट्रेडर्स बेतिया, मैसर्स सिंह खाद भंडार, रामगढ कैमूर, रणवीर सीमेंट स्टोर, साहपुर दानापुर इन सभी स्टॉकिस्टों को विशेष रुप से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर कंपनी के श्री केएन महरोत्रा (सेल्स मैनेजर) ने उपस्थित विक्रेताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया.

–निक्की

पंडित पुण्य देव शर्मा पुण्यतिथि समारोह

विक्रम के गांधी आश्रम में पंडित पुण्य देव शर्मा पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय, विक्रम विधायक अनिल कुमार, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह, मगध विकास मोर्चा के अध्यक्ष अंजनी कुमार राजू, लोजपा के प्रदेश महासचिव उपेन्द्र यादव, रोहित शर्मा, वाल्मीकि शर्मा, प्रभात बटालियन सहित कई लोग उपस्थित थे. इस समारोह की शुरुआत डॉ शीला शर्मा के स्वागत भाषण से हुई. कार्यक्रम की अध्यक्षता समर बाबू ने की तथा इसका संचालन शंशाक शेखर मिश्रा द्वारा किया गया.

अध्यादेश के खिलाफ धरना

सीतामढ़ी जिला मुख्यालय स्थित डॉ अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर जदयू किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रो अमर सिंह ने की. मौके पर शिव पूजन सहाय, किरण गुप्ता, बबलू मंडल, सुरेंद्र पटेल, मो जुनैद, राहुल कुमार सिंह, तनवीर अहमद, विश्वनाथ साह, लोहा सिंह, विजय ठाकुर, रामबाबू साह, मनोज कुमार, देवेंद्र झा, शत्रुघ्न कुशवाहा समेत अन्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

– विकास कुमार

जननायक की जयंती मनायी

सीतामढ़ी के डुमरा स्थित शंकर चौक पर जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के तत्वावधान में जननायक की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये. केंद्र के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चुम्मन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जननायक को भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की. कार्यक्रम में जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद, जदयू नेता भरत प्रसाद, रामबली सिंह, रामजी मंडल, मो जब्बार अंसारी, रघुनाथ सिंह, जदयू सेवा दल अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सुरेश यादव व सत्येंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.

–ब्रजेश कुमार

भ्रष्टाचार मुक्त शासन का प्रयास

जिला मुख्यालय डुमरा स्थित परेड मैदान में 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डीएम डॉ प्रतिमा ने राष्ट्रध्वज फहराया. मौके पर एसपी हरि प्रसाथ समेत जिले के आलाधिकारी व आम जनता मौजूद थी. समारोह को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सीतामढ़ी मां जानकी की पावन जन्म स्थली है. सीतामढ़ी जिला प्रशासन आम आवाम को भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ ही सरकार प्रायोजित विकास योजनाओं का लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है. समारोह के दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों के दस्ते के अलावा स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट के दौरान राष्ट्रध्वज को सलामी दी. इस दौरान अलग-अलग विभागों द्वारा आकर्षक झांकी भी निकाली गयी.■

–वाल्मीकि

बक्सर

राजनीतिक दांव पेंच में उलझा मलई बैराज

प्रो जयमंगल पांडेय

बक्सर में लगभग तीस वर्षों से राजनीति का अखाड़ा बना मलई बैराज इस बार सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक दांव-पेंच का शिकार हो गया है. बैराज निर्माण के विरोध में एक तरफ रोहतास के किसान लाठी डंडा लेकर तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ बक्सर जिले के किसान बैराज निर्माण कराने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त हैं. लगभग छह महीने से निर्माण कार्य बंद होने के बाद भी जनप्रतिनिधि तथा आला अधिकारी खामोश हैं.

बक्सर के नावानगर अंचल में निर्माणाधीन महत्वकांक्षी मलई बैराज सिंचाई परियोजना का दुर्भाग्य यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-1952 में स्वीकृत होने के बाद भी आज तक उस पर लगा ग्रहण समाप्त नहीं हुआ है. वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विन्देश्वरी दुबे ने बैराज का निर्माण कार्य शुरू कराया था. लेकिन रोहतास जिले के दावत अंचल के किसानों ने खेत डूब जाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया. इसके बाद बैराज निर्माण पर ग्रहण लग गया. इसे लेकर वर्षों तक राजनीति होती रही और हर चुनाव में बैराज निर्माण चुनावी मुद्दा भी बनता रहा.

डुमरांव के जेडीयू विधायक डॉ. दाउद अली की पहल पर 23 मई, 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोबारा शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कराया. लेकिन रोहतास के किसानों ने पुराना राग अलापते हुए निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों तथ मजदूरों के साथ दो बार मारपीट कर उन्हें भगा दिया. लेकिन इंजीनियरों की मांग के बाद भी वहां पुलिस बल तैनात नहीं किया गया. लिहाजा इंजीनियरों ने कार्य को रोक दिया. लगभग 66 करोड़ की इस योजना पर अब तक छह करोड़ रुपये खर्च हो गए है. सिंचाई विभाग के यहां तैनात इंजीनियर और कर्मचारी निठल्ले वेतन ले रहे हैं. दिलचस्प बात तो यह है कि बैराज निर्माण के लिए 1987 में ही 35 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर उसका मुआवजा दे दिया था. लेकिन रोहतास के किसान उसी समय से जमीन पर कब्ज़ा कर खेती कर रहे हैं और संभवत: इसी लोभ में विरोध को हवा भी दे रहे हैं. परियोजना के सहायक अभियंता धीरेंद्र सिंह बताते हैं कि इस योजना को लेकर फसल डूब जाने की महज अफवाह उड़ाई गई है. पुलिस कैंप स्थापित करने के लिए सरकार के पास लिखा गया है. पुलिस की तैनाती के बाद ही कार्य शुरू होगा. चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर जीतने वाले डुमरांव के जेडीयू विधायक डॉ दाउद अली तो इसके लिए इंजीनियरों को ही दोषी मानते हैं. वह कहते हैं कि इंजीनियर विरोध करने वालों के नाम क्यों नहीं बताते हैं. वहीं बैराज निर्माण के जागो किसान संगठन से जुड़े मुखिया विनोद कुमार ओझा कहते हैं कि दोनों तरफ से जेडीयू के ही विधायक हैं और वे लोग रूकावट में बाधा दूर करने के बदले राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं. सत्तारूढ़ दल के विधायकों की आपसी राजनीति से किसानों में आक्रोश है और विकास के प्रति प्रदेश सरकार की मंशा भी उजागर हो गई है. दिलचस्प बात तो यह है कि रोहतास के किसान बैराज निर्माण का विरोध कर रहे हैं.

बक्सर के नावानगर अंचल में निर्माणाधीन महत्वकांक्षी मलई बैराज सिंचाई परियोजना का दुर्भाग्य यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में स्वीकृत होने के बाद भी आज तक उस पर लगा ग्रहण समाप्त नहीं हुआ.

समीपवर्ती इलाके के विधायक जेडीयू के हैं और राज्य सरकार में दो मंत्री पद पर भी हैं. सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह बक्सर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं. जो यहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा कर आदेश भी देते हैं. यहां के किसानों का सीधा सवाल है कि नीतीश कुमार की महत्वकांक्षी योजना में आ रही बाधा पर प्रभारी मंत्री खामोश क्यों है. बक्सर जिले के छह प्रखंड़ों में पंद्रह हजार एकड़ खेतों की सिंचाई करने वाली योजना कोई मायने नहीं रखती है या इससे भी कोई बड़ी योजना हो सकती है? ऐसे में तमाम अहम प्रश्नों पर प्रभारी मंत्री तथा डुमरांव जेडीयू विधायक दाउद अली की चुप्पी पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. वर्षों से खेतों की सिंचाई के लिए परेशान किसान सोन मलई किसान संघ तथा जागो किसान नायक संगठन बनाकर धरना प्रदर्शन कर मंत्रियों का पुतला फूंक रहे हैं और किसानों के बीच घूम-घूम कर सरकारी साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं. अब आशंका इस बात की है कि दो ढाई साल पूर्व बने प्राक्कलन और लागत खर्च बढ़ने के कारण निर्माण एजेंसी काम कराने से इंकार करती है तो निर्माण पर स्थायी ब्रेक लग जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

सफलता का परचम लहरा रहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ी

महिलायें हर क्षेत्र में लगातार सफलता नये आयाम गढ़ रही हैं. परंपराओं केबंधनों के टूटने के साथ महिलायें सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रही हैं. राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक महिलायें अपनी नई पहचान बनाने में लगी हैं. जो उसके लिए परिवार से समाज तक सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता दिख रहा है. आलम यह है कि कल तक बेटी को घर की दहलीज पार करने से मना करने वाले भी अब बेटियों को सम्मान पाने की राह दिखाने लगे हैं. नतीजा यह है कि महिलाओं का बढ़ता आत्मबल उसे अबला की जगह सबला साबित कर रहा है. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण सीतामढ़ी जिले के हेलेंस स्कूल व एनएस डीएवी पब्लिक स्कूल की आधा दर्जन छात्रायें हैं, जिनका चयन राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टीम में भागीदारी को लेकर किया गया है...

सीतामढ़ी

वाल्मीकि कुमार

कला, संगीत, साहित्य व नृत्य सहित अनेक कलाओं को लेकर सूबे में चर्चित रहे सीतामढ़ी जिले को एक बार फिर नई उपलब्धि ने इतराने का मौका दे दिया है. यह मौका न किसी राजनीतिक हस्ती और न ही किसी धन-बल शाली व्यक्ति ने दिया है. इस बार जिले को यह मौका जिले की आधा दर्जन बेटियों ने दिया है. जो स्कूली शिक्षा के साथ-साथ खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. ऐसे तो खेलों में अब तक जिले की कई बेटियों ने सफलता हासिल की है परंतु हाल ही में क्रिकेट के मैदान पर तेज रफ्तार गेंदों का सामना करने का जोखिम हेलेंस स्कूल डुमरा की छात्रा अस्मिता मेहरौर, अंकिता कुमारी, अपूर्वा निधि एवं एनएस डीएवी स्कूल की छात्रा भामिनी भाव्या, नितिका विभु व भाव्या प्रियदर्शनी उठाया है. कहा गया है कि साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती है. जिले की इन बेटियों ने इसे सच कर दिखाया है. 66 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीतामढ़ी की डीएम डॉ प्रतिमा ने उक्त छात्राओं को उनकी सफलता पर प्रशस्ति पत्र व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया है.

अंकिता कुमारी | अपूर्वा निधि | अस्मिता मेहरौर | भामिनी भाव्या | भाव्या प्रियदर्शिनी | निकिता विभू
चंदा सिंहा | संजय सिंह | श्याम किशोर प्रसाद | अनंत सहाय

जिला क्रिकेट संघ के सचिव श्याम किशोर प्रसाद की मानें तो साल 2012 में सीतामढ़ी में महिला क्रिकेट टीम का नींव रखी गई थी. तब इस खेल के विकास को लेकर कई योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता महसूस की गई. जिले में महिला क्रिकेट के विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए. स्थानीय स्तर पर प्रतिभावान छात्राओं का चयन कर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई. नतीजतन, महज दो साल के अथक प्रयास के बाद ही जिले की छह छात्राओं ने राज्य स्तर पर महिला क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की. उनमें से अंकिता कुमारी एक ऐसी प्रतिभा साबित हुई हैं जिन्हें बिहार के उदीयमान खिलाड़ी के रूप में बिहार क्रिकेट संघ के मानद सचिव अजय नारायण शर्मा ने पुरस्कृत किया है. बताया जाता है कि बिहार महिला क्रिकेट टीम के गठन को लेकर सूबे भर के कुल 38 छात्राओं का चयन किया गया है. जिसमें 6 छात्रायें सीतामढ़ी जिले की हैं. अब राज्य स्तर पर एक माह का कोचिंग कैंप आयोजित किया जाएगा. जिसमें सफल छात्राओं का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन किया जायेगा.

प्राचार्य का कहना है कि प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के खेल प्रतिभा का विकास को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है. हेलेंस स्कूल डुमरा के चेयरमैन संजय सिंह का कहना है कि स्कूल की चयनित तीनों छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही नेट, बैट, बॉल व अन्य संसाधन छात्राओं को उपलब्ध कराये गए हैं. इस स्कूल की प्राचार्य चंदा सिन्हा कहती हैं कि जिले में महिला खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. लेकिन इसके विकास को लेकर महिलाओं में विशेष जागरूकता की आवश्यकता है. जिले की छात्राएं शिक्षा के साथ-साथ खेल जगत में भी अपनी पहचान बना रही हैं. जो जिला के साथ-साथ प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत हैं.

एनएस डीएवी डुमरा की छात्रा भामिनी भव्या किसान अशोक कुमार सिंह की पुत्री हैं. ये अब तक इंटर स्कूल, जिला स्तरीय क्रिकेट व जिला स्तरीय बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हैंड बॉल आदि खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं. नितिका विभू, विभू रंजन कुमार की पुत्री हैं वह भी इंटर स्कूल, जिला स्तरीय क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन में भी उप-विजेता रह चुकी हैं. जबकि पीएचईडी विभाग में सरकारी कर्मी धीरज कुमार की पुत्री भाव्या प्रियदर्शिनी इंटर स्कूल व जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं. वहीं दुसरी ओर हेलेंस स्कूल डुमरा की छात्रा अपूर्वा निधि व्यवसायी अंजनी शर्मा तो अंकिता कुमारी, दीपक कुमार की पुत्री हैं. दोनों अब तक इंटर स्कूल के अलावा जिला स्तरीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं. जबकि डॉ अभय कुमार की पुत्री अस्मिता मेहरौर इंटर स्कूल, जिला स्तरीय क्रिकेट के साथ ही बैडमिंटन में उपविजेता रह चुकी हैं. जिले में महिला खेल प्रतिभाओं के विकास को लेकर दोनों ही स्कूल प्रबंधन हर संभव प्रयास करने की करते हैं. निखिल श्यामा डीएवी डुमरा के प्राचार्य अनंत सहाय की मानें तो स्कूल में खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की गई है. क्रिकेट के साथ फुटबॉल में भी ध्यान दिया जा रहा है. प्राचार्य का कहना है कि प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभा के विकास को लेकर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. हेलेंस स्कूल डुमरा के चेयरमैन संजय सिंह का कहना है कि स्कूल की चयनित तीनों छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही नेट, बैट, बॉल व अन्य संसाधन छात्राओं को उपलब्ध कराये गए हैं. इस स्कूल की प्राचार्य चंदा सिन्हा कहती हैं कि जिले में महिला खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. लेकिन इसके विकास को लेकर महिलाओं में विशेष जागरूकता की आवश्यकता है. जिले की छात्राएं शिक्षा के साथ-साथ खेल जगत में भी अपनी पहचान बना रही हैं. जो जिला के साथ-साथ प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत हैं. अब देखना है कि राज्य स्तरीय टीम में सीतामढ़ी जिला की महिला खेल प्रतिभायें किस स्तर तक पहुंचने में कामयाब होती हैं. यदि इन खेल प्रतिभाओं को मुकाम मिलता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जिला क्रिकेट संघ व संबंधित स्कूल प्रबंधन बधाई के पात्र होंगे. यदि किसी वजह से इन महिला खिलाड़ियों को दोबारा प्रयास करना पड़े तो इसके लिए संघ के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन को भी जिले की महिला क्रिकेट टीम को मजबूती देनी होगी. इसके लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि व आम लोगों को समान भागीदारी के लिए तैयार रहना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला!

इन्तेजारूल हक़

पूर्वी चंपारण जिले का शिक्षा विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है. यहां खुलेआम विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों की सरकारी राशि की बंदरबाट की जा रही है. यहां भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घोटाले के प्रमाणित होने के बावजूद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है. इसका ज्वलंत नमूना जिले के घोड़ासहन, मधुबन, चकिया, बंजरिया, ढ़ाका आदि प्रखंड क्षेत्रों में देखा जा सकता है. विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को जूडो-कराटे का प्रशिक्षण देने के लिए आवंटित राशि का हो या छात्रवृत्ति की राशि का या फिर पोशाक व मध्यान्ह भोजन योजना का या फिर विद्यालयों में छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लगाये गये कंप्यूटर का सभी की स्थिति एक जैसी है. खुलेआम सरकारी राशि की बंदरबाट की जा रही है. आम जनता द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जब चौथी दुनिया ने इस संबंध में तहक़ीकात शुरू की और संबधित अधिकारियों के कार्यालयों से आवश्यक कागजात हासिल किए. तब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. सबसे पहली यह बात सामने आई कि आरोपों पर जांच तो होती है, गड़बड़ घोटाला होने की बात भी साबित भी होता है, लेकिन जांच रिपोर्ट को विभाग के ही कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ इस तरह दबा दिया जाता है या दबा दिया गया है कि जैसे कि समुद्र में कंकड़ फेंका गया हो.

हम शुरूआत घोड़ासहन प्रखण्ड से करते हैं. घोड़ासहन प्रखण्ड क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को जुडो-कराटे का आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए एक लाख रुपये की स्वीकृति मिली और 31 मार्च 2013 को प्रखण्ड संसाधन केंद्र घोड़ासहन ने उक्त राशि को प्राप्त कर लिया. लेकिन घोड़ासहन के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी योगेन्द्र नाथ शर्मा ने इस आवासीय प्रशिक्षण को गैर-आवासीय कर दिया और फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर राशि की बंदरबांट कर दी. जूडो-कराटे प्रशिक्षण के निरीक्षण के लिए पटना से आई टीम ने अपने जांच प्रतिवेदन में प्रशिक्षण नहीं चलाने का जिक्र किया है और मध्यान्ह भोजन योजना में बड़े पैमाने पर राशि का गबन करने की बात कही है. राज्य परियोजना कार्यालय पटना के एसआरजी सरिता कुमारी ने अपने पत्रांक-09 दिनांक 03.01.2014 के तहत अनुश्रवण प्रतिवेदन में मध्यान्ह भोजन योजना में हो रही गड़बड़ी व प्रशिक्षण में हुई राशि की बंदरबांट का खुलासा किया है. दूसरी तरफ वित्तीय संचालन में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करने का खुलासा मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभारी पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में किया है. वहीं बीते दिनों बालापुर गांव में संचालित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा किया गया हंगामा व सड़क जाम भी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सहित विभाग के अन्य आलाधिकारियों की काली करतूत का परिणाम है. जानकार बताते हैं कि अगर छात्रों को मध्यान्ह भोजन योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिलता तो वे हंगामा क्यों करते? इसी तरह का मामला मधुबन का है, जहां मध्यान्ह भोजन योजना से लेकर प्राय: सभी योजनाओं की राशि की बंदरबाट करने का मामला सुर्खियों में रहता है. इसके लिए समय-समय पर छात्र हंगामा करते रहते रहे हैं. दो वर्ष पूर्व जब मधुबन प्रखण्ड के माधोपुर कुशवाहा टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यक योगेन्द्र राम निराला पर जब असैनिक कार्य, छात्रवृति, पोशाक एवं मध्यान्ह भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बदले उसका तबादला दूसरे विद्यालय में कर दिया गया और बेहद नाटकीय ढ़ंग से उनके कार्यकाल की संचिका को दबा दिया गया.

सदर मुख्यालय में स्थापित बंजरिया का हाल तो और भी निराला है. जानकार बताते हैं कि यहां दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां मध्यान्ह भोजन कभी नहीं बनता है, विभागीय अधिकारी पूरी तरह से मैनेज हैं. असैनिक कार्यों में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई और राशि की बंदरबाट की गई. इसी तरह जानकार बड़े पैमाने पर घोटाले होने की बात बताते हैं और कहते हैं कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी यह मामला स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सदस्यों व विधायकों द्वारा बड़े जोड़-शोर से उठाया जाता है. बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है. यहां यह भी बताते चलें कि वर्ष 2004-05 में जिले के मध्य विद्यालयों को तीन-तीन कंप्यूटर उपलब्ध कराये गए थे ताकि छात्र कंप्यूटर शिक्षा हासिल कर सकें. किंतु इस कंप्यूटर पर भ्रष्टाचार का साया इस कदर हावी रहा कि एक तरफ दर्जन भर विद्यालयों में कंप्यूटर लगने के साथ ही खराब हो गए और किसी काम के लायक नहीं बचे. दुसरी तरफ कई विद्यालयों के प्राचार्यों ने इसे अपनी निजि संपत्ति बना लिया. कुछ विद्यालयों में लगे कंप्यूटरों की चोरी होने की सूचनायें मिलती रही हैं, अब यहां सवाल यह उठता है कि किस कंपनी के कंप्यूटर की खरीददारी हुई थी कि अधिकांश लगने के साथ ही खराब हो गए? इसकी जांच अभी लंबित है और लोगों की नज़र जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव पर टिकी हुई है. कुल मिलाकर शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है और यहां संचालित योजनाओं की यदि निष्पक्ष जांच होती है तो अनेक चौंकाने वाले मामले तो सामने आयेंगे ही, साथ ही कई अधिकारियों की काली करतूत भी उजागर हो सकेगी. इस विषय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रामनन्दन प्रसाद ने कुछ भी बताने से परहेज किया.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

मुख्यमंत्री ने दिखायी सुशासन की आस

मंगलानंद

झारखंड के नये मुख्यमंत्री रघुबर दास आमलोगों की समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील हो चुके हैं. लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए उन्होंने जनता दरबार लगाना भी शुरू कर दिया है ताकि आमलोगों को उनकी समस्याऐं ज्यादा परेशान न करें. मुख्यमंत्री के पहले जनता दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. साल 2000 में झारखंड प्रदेश की स्थापना होने के 15 साल बाद पहली बार सुशासन का चेहरा प्रदेश के लोगों के सामने आया है. मुख्यमंत्री की सूबे के नौकरशाहों के साथ पहली समीक्षा बैठक में ही उनके बदले हुए तेवर से सभी अधिकारियों को सकते में डाल दिया है. लोग इसे सुशासन की शुरूआत मान रहे हैं. मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि वे अगले तीन से चार दिनों के भीतर प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल पदाधिकारी नामित करें जो आम लोगों से विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त करें और उन आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें. इससे आम लोगों को दाखिल-खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने, चापानल की मरम्मत, शौचालय का निर्माण जैसे छोटे-छोटे कामों के लिए ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी लोग प्रखंड में एक ही स्थान पर आवेदन दें सकें. प्रखंड प्रशासन विभिन्न विभागों से सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराये. इसके साथ ही की गई कार्रवाई की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता को समय से मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मात्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों में भी प्रत्येक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है ताकि कार्य पारदर्शी हों एवं बिचौलियों की कोई भूमिका ना रहे. स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन तथा लोगों को समय से सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ई-गवर्नेंस पर फोकस करें. इसके लिए मानसिकता में बदलाव को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि गांव-शहर के गरीब लोगों को सशक्त बनाने में ही लोकतंत्र की मजबूती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरवी और दलाली बंद हो. कोई भी अधिकारी अपनी पैरवी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए न करे. अधिकारियों को रांची, धनबाद और जमेशदपुर से कुछ ज्यादा ही मोह हो गया है, यह गलत है. लोहा और कोयले की तस्करी पर अधिकारी पूर्ण रूप से रोक नहीं लगायेंगे, तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में राज्य के सभी आलाधिकारी मौजूद थे.■

feedback@chauthiduniya.com

बगहा विकास मंच का हुआ गठन

बगहा को पुलिस जिला से राजस्व जिला बनाने के लिए सभी दलों के लोगों ने मिलकर बगहा विकास मंच का गठन किया है. बगहा को राजस्व जिला बिहार सरकार द्वारा अब तक नहीं बनाने की वादा खिलाफी को लेकर फरवरी में अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष बगहा विकास मंच के लोग धरना देंगे और आंदोलन करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री के वाल्मीकिनगर आने पर बगहा विकास मंच के लोग प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे. मिली खबर के मुताबिक बगहा को पुलिस जिला से राजस्व जिला बनाने के लिए जदयू की जिला बैठक में सभी लोग इस बात से सहमत हुए कि बगहा को राजस्व जिला हर हाल में बनना चाहिए. मंच की तरफ से फरवरी माह में अनुमण्डल परिसर में अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष धरना और मुख्यमंत्री के कैबिनेट मीटिंग के समय प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री का घेराव किया जायेगा, बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में प्रो. बबुआ सिंह, भीष्म सहनी, सतीश कुमार बर्मा, संजय पाण्डेय, मनोज सिंह कामरान अजीज, विजय कुमार पाण्डेय,भूप यादव,आलमगीर रब्बानी, अरमानी खां, मुन्ना राज, तुफानी चौधरी आदि लोग शामिल थे. बैठक की अध्यक्षता कैलाश नाथ तिवारी तथा संचालन राकेश सिंह ने किया. ■

–अरविन्द नाथ तिवारी

एक नज़र

पार्टी कार्यालय में फहराया तिरंगा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी जिले में उत्साह व उल्लास का माहौल बना रहा. सरकारी से लेकर गैर सरकारी कार्यालयों समेत अन्य स्थानों पर लोगों ने देश का शान तिरंगे को फहरा कर सलामी दी. सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला ने राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी दी. मौके पर पूर्व सांसद मो. अनवारूल हक़, उपाध्यक्ष सीताराम झा, सत्येंद्र तिवारी, प्रो. बच्चा मिश्र, मो. असद, परवेज आलम अंसारी, अंजारूल हक तौहिद, मंजू कुमारी व शिव शंकर शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे.

विधायक को मांग पत्र सौंपा

भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ किसान सत्याग्रह के अंतर्गत सीतामढ़ी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मो. शम्स शहनवाज़ के नेतृत्व में सैकडों कार्यकर्ताओं ने नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू का घेराव किया. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने संबंधी मांग पत्र उन्हें सौंपा. कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम झा, महासचिव वीरेंद्र कुशवाहा, अफजल राणा, वैदेही शरण यादव, रफीक आलम, रेयाज अंसारी, मो शाकिर, मो शमी आलम, नेमतुल्लाह, मकसूद आलम, लालबाबू व राम छबीला राय सहित अन्य उपस्थित थे.

–ब्रजेष

बेहतर कार्य के लिए मिला पुरस्कार

66 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी व जदयू नेता राजेश चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले 125 लोगों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. सम्मानित होने वालों में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र प्रसाद सिंह, समाजसेवी प्रो वीरेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक सहायक गोविंद कुमार, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष विजय कुमार पासवान, मुखिया मुकेश शाही, देवरंजन राम, राम शत्रुघ्न राय, ईरा देवी, पंसस भूपेंद्र प्रसाद नारायण सिंह, राम जीवन राय, शंभू प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद चौधरी, राधा रमण मेहता व विजय कुमार सिंह समेत अन्य शामिल हैं. कार्यक्रम में प्रमुख संगीता देवी, बीडीओ नीरज आनंद, सीओ समीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता कुमारी सत्यनंदन, अविनाश कुमार, बीईओ जयजयराम राय, बालेश्वर चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवीन्द्र चौधरी, एएनएम विभा कुमारी व थानाध्यक्ष गोरख राम समेत अन्य उपस्थित थे.

– विभा सिन्हा

राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना

पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और मतदान के प्रति लोगों को अनेक जानकारियां दी गयीं. शहर के लूठहां महावीर मध्य विद्यालय में पंचम जिला स्तरीय मतदाता दिवस मनाया गया. मतदाताओं को शपथ दिलाया कि हम, भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार व सीडीओ गंगा सागर सिंह बीए-लओ प्रेमशंकर पंडित, राजकिशोर राम, गजेन्द्र राम सहित दर्जनों मतदाता व गणमान्य लोग उपस्थित थे.

लोजपा नेता का स्वागत हुआ

बिहार लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अनिल चौधरी व लोजपा प्रदेश महासचिव बाल मुकुंद सिंह का केसरिया के लाला छपरा स्थित गगन होटल में पिपरा विधान सभा के लोजपा नेता डॉ बीके राय के नेतृत्व में फूल माला पहना कर स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने व लोजपा की नीतियों व सिद्धांतों से आम जनता तक पहुंचाने का आहवान किया. मौके पर लोजपा जिला अध्यक्ष धरनीधर मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष नसीमुहो जोहा उर्फ नन्हे, निपू सिंह, मुकेश कुमार सिंह, जिला सचिव संजय यादव, प्रखंड अध्यक्ष मो. मुस्ताक समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे.

श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया

पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज स्थित सुविख्यात श्री सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया. लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने-अपने हाथ में पावन जल का पात्र लिये ऊँ नम: शिवाय मंत्र का जाप करते रहे और घंटों दिव्य पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी की प्रतिक्षा में कतार में खड़े रहे. हालांकि शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो इस बाबत प्रशासन काफी मुस्तैद था. इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया था, जहां दंडाधिकारी के रूप में सीओ कृष्ण मोहन पाठक, मोहन पाठक, सीडीपीओ शंकर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक अजय कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष आरके भानू, थानाध्यक्ष राजेश कुमार, थानाध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार, सअनि संजय कुमार, आदि तैनात किये गये थे. दूसरी तरफ एसडीओ एसएस पाण्डेय व डीएसपी नुरूल हक़ भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे. पूर्व सैनिक संघ के कांति शरण शर्मा, लाल प्रसाद मिश्र, जितेन्द्र पाण्डेय, कैलाश सिंह आदि भक्तों की सेवा में जुटे रहे.

स्व. ठाकुर की जयंती मनाई

पूर्वी चम्पारण जिले में बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पूर्वक मनायी गयी और उन्हें तहेदिल से याद किया गया. इस दौरान शहर के नगर थाना चौक पर स्थापित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर अति-पिछड़ा वर्ग संघ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश किशोर ठाकुर की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर के आदर्शों पर चलने की जरूरत है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो नसीम अहमद, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह, राय सुनरदेव शर्मा, अमरेन्द्र कुमार सिंह, दशरथ ठाकुर, सूर्य नारायण ठाकुर, अधिवक्ता जयराम सिंह, मोहिबल हक, मो साजिद राजा, डॉ विनोद शर्मा, तारकेश्वर प्रसाद, लालबाबू सिंह, अब्दुल हमीद कैप्टन आदि मौजूद थे.

– इन्तेजारूल हक

> कुलपति ने राज्य सरकार को खेद जताते हुए पत्र लिखा है कि मगध विश्वविद्यालय आईआईएम की शाखा खोलने के लिए भूखंड देने में असमर्थ है. विश्वविद्यालय की जमीन पर आईआईएम खोलने के लिए जमीन हस्तानांतरित करने का अधिकार राज्यपाल सह कुलाधिपति के पास है. इसके लिए सीनेट व सिंडिकेट की सहमति लेना भी जरूरी है. सीनेट के अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं. जमीन हस्तानांतरण का अधिकार भी उन्हीं के पास है.

आईआईएम की स्थापना को लेकर राजनीति

सुनील सौरभ

भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम) के बोधगया में खुलने को लेकर राजनीति शुरु हो गयी है. प्रबंधन शिक्षा देने वाली देश की इस महत्वपूर्ण संस्था के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में खोलने के लिए राज्य सरकार ने पहले कुलपति से सहमति ले ली थी. इसके लिए मगध विश्वविद्यालय परिसर मे डेढ़ सौ एकड़ भूमि भी चिन्हित कर ली गयी थी. इसी आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 06 जनवरी, 2015 को दिल्ली में हुई शिक्षा मंत्रियों की बैठक में बोधगया में आईआईएम खोलने संबंधी आदेश जारी कर दिया. इससे पहले आईआईएम, इंदौर ने राजधानी पटना में ही इस संस्था को खोलने पर ही मेंटर बनने की शर्त रखी थी. लेकिन पटना में डेढ़ सौ एकड़ भूमि मिलना बेहद कठिन काम था. इसी वजह से गया को इसका लाभ मिला. गया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तथा यह रेल यातायात के माध्यम से पूरे देश से भी जुड़ा है. यह भी आईआईएम की बोधगया मे स्थापना की एक महत्वपूर्ण वजह है.

अब मगध विश्वविद्यालय प्रशासन तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ आईआईएम के लिए ज़मीन देने से इंकार कर रहा है. कुलपति डॉ प्रो. मोहम्मद इश्तियाक ने कर्मचारी संघ के विरोध पर यू-टर्न लेते हुए कहा है कि इस मामले में सरकार के आदेश का पालन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस पर विश्वविद्यालय के सभी संघों से विचार विमर्श किया जायेगा. जबकि शुरुआत में राज्य के शिक्षा विभाग ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की सहमति के बाद केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय परिसर में आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी. राज्य शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने मगध विश्वविधालय परिसर स्थित भूमि का निरीक्षण भी किया था. इसके बाद विश्वविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया. विरोध के बाद कुलपति ने राज्य सरकार को खेद जताते हुए पत्र लिखा है कि मगध विश्वविद्यालय आईआईएम की शाखा खोलने के लिए भूखंड देने में असमर्थ है. विश्वविद्यालय की जमीन पर आईआईएम खोलने के लिए जमीन हस्तानांतरित करने का अधिकार राज्यपाल सह कुलाधिपति के पास है. इसके लिए सीनेट व सिंडिकेट की सहमति लेना भी जरूरी है. सीनेट के अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं. जमीन हस्तानांतरण का अधिकार भी उन्हीं के पास है. सीनेट, सिंडिकेट व कुलाधिपति की इजाजत के बाद ही विश्वविद्यालय की जमीन हस्तानांतरित की जा सकती है. लेकिन 24 जनवरी, 2015 को जब शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय टीम प्रधान सचिव आरके महाजन के नेतृत्व में मगध विश्वविद्यालय के मुख्यालय पहुंची, तो कुलपति ने विरोध कर रहे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ से कहा कि हमसे सरकार जो कहेगी, हमें वही करना होगा. हम उनके प्रतिनिधि हैं. सूबे के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने स्पष्ट कहा है कि आईआईएम बोधगया नौ सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है. इसमें फेरबदल संभव नहीं है. यह सरकार का निर्णय है जो हर हाल में पूरा होना है. विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी चाहें तो इसके बदले में अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सकते हैं. सरकार उनकी मागों पर गौर करेगी.

हालांकि, मगध विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने भी पूर्व में राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि भविष्य में मगध विश्वविद्यालय कैंपस का विस्तार करने तथा अन्य विभागों की स्थापना की योजनाओं की वजह से आईआईएम के लिए वर्तमान ज़मीन मुहैया नहीं करा सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि आज मगध विश्वविद्यालय का पदाधिकारी या कर्मचारी संघ आईआईएम जैसी महत्वपूर्ण संस्था केगया में खुलने का विरोध कर रहे हैं, इसकी स्थापना के लिए ज़मीन नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे विश्वविद्यालय की सैकड़ों एकड़ भूमि को अतिक्रमण से बचाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं. मगध विश्वविद्यालय परिसर के पश्चिम में स्थित सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी है, इसका अतिक्रमण किया जा रहा है. जहां-तहां इस भूमि के बीच से सड़क बना दी गयी है. वहीं जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित लोधवे में बुधौली मंहथ से दान मे मिली डेढ़ सौ एकड़ से अधिक भूमि पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है. यहां सवाल है कि इसे देखने वाला कौन है? इन बातों को छोड़िये, मगध विश्वविद्यालय के पास 371 एकड़ भूमि है, कुछ स्थानों पर सजिश के तहत चाहरदीवारी नहीं होने दिया जा रहा है. नतीजतन पूरा मगध विश्वविद्यालय परिसर पशुओं की चारागाह बना हुआ है. प्रतिदिन सैकड़ों गाय- भैंस विश्वविद्यालय परिसर में चरते हुए देखे जा सकते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए कोई शिक्षक या कर्मचारी संघ आगे नहीं आता. इन सारे मामलों मे विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारियों- कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जाती है. इस मसले पर पूर्व विधायक डॉ विनोद कुमार यादवेंदु ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से निश्चित रुप से मगध विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्थिति व संस्कृति प्रभावित होगी. कार्य संस्कृति में भी सुधार आयेगा. साथ ही मगध क्षेत्र के युवाओं में भी आईआईएम में अध्ययन के लिए आकर्षण बढ़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नकारात्मक सोच के लोग इस संस्थान के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के खिलाफ हैं.

अब जबकि आईआईएम-गया की स्थापना के लिए मेंटर बनाये गये. आईआईएम इंदौर से अधिकारियों की एक टीम संस्थान के अस्थायी आवास तथा शिक्षण कार्य के लिए निर्मित स्थान के चयन हेतु गया पहुंचने वाली है, तो लोगों के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है. आईआईएम निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अवधेश कुमार सिंह, संयोजक विजय कुमार मिट्टू सहित दर्जनों लोगों ने कहा है कि यह समिति की ओर तीन महीने से किए जा रहे आंदोलन का प्रतिफल है. जबकि राजद के पूर्व विधायक डॉ विनोद कुमार यादवेंदु ने कहा है कि बोधगया में आईआईएम का खुलना मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल के प्रयास का प्रतिफल है. भाजपा के विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ने कहा है कि अपना धरोहर गया शहर के वैनर तले लंबे समय से आईआईएम को गया लाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था. आंदोलन के दौरान ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया गया था. जिससे कि आईआईएम को बोधगया में खोलने की अनुमति मिली. गया नगर के विधायक डॉ प्रेम कुमार ने विजय जुलुस निकालकर कहा कि केंद्र की सात महीने की भाजपा सरकार ने देश का महत्वपूर्ण प्रबंधन संस्थान गया में खोलकर क्षेत्रवासियों का सम्मान किया है. तमाम राजनीति व विवाद के बाद भी बिहार सरकार ने तय किया है कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आईआईएम, गया में पढ़ाई शुरु हो जायेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

सवालों के घेरे में कवि सम्मेलन

इंतेजारूल हक़

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मोतिहारी के नगर भवन में आयोजित कवि सम्मेलन पूरी तरह सवालों के घेरे में है. आम जनता के बीच देश भक्ति का जज्बा पैदा करने, समाज में अमन-चैन स्थापित करने तथा भारतीय सभ्यता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस कवि सम्मेलन से एक तरफ जिलावासी पूरी तरह से अंजान रहे, वहीं दूसरी तरफ चंद शायरों व कवियों के बीच यह कार्यक्रम सिमट कर रह गया. सम्मेलन में श्रोता भी नहीं पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान नगर भवन की कुर्सियां खाली रहीं. इसका मुख्य कारण लोगों तक इस आयोजन की जानकारी नहीं पहुंचना है. इसके साथ ही शहर के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था. जानकार बताते हैं कि इस कवि सम्मेलन के नाम पर केवल सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई. इसमें किसी भी नामचीन शायर व कवियों को आमंत्रित नहीं किया गया था. इसके अलावा कवि सम्मेलन में शिरकत कर अपनी रचनाएं पढ़ने वाले कवियों व शायरों को मुनासिब प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई. इस वजह से तरह-तरह की चर्चायें हो रही हैं.चंपारण के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ कि किसी कवि सम्मेलन को सुनने श्रोता नहीं पहुंचे. अपनी रचनाओं को पढ़ने वाले शायर व कवि ही श्रोताओं की भूमिका में नज़र आये. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे नगर भवन प्रांगण में शायर, कवि व श्रोताओं को मिलाकर तकरीबन 25 से 30 लोग ही उपस्थित थे. जबकि इतिहास गवाह है कि यहां जब भी कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन आयोजित हुआ तो श्रोताओं का ऐसा हुजूम उमड़ता है कि उन्हें संभाल पाना स्थानीय प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है. कहा जाता है कि शायर व कवि के लिए श्रोता ही खुराक होते हैं . श्रोताओं की संख्या जितनी अधिक होती है शायर व कवि उतनी बेहतरी और ओज से अपनी रचनायें पढ़ते हैं. लेकिन जिस कवि सम्मेलन से श्रोता ही गायब रहें तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है?

आखिर इस आयोजन में शहर के सम्मानित लोगों को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे प्रशासनिक पदाधिकारियों की क्या मंशा थी? क्या उनका सीधा- सीधा मकसद कवि सम्मेलन के नाम पर खानापूर्ति करना और पैसे की बंदरबाट करना था या कुछ और? इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे पर भी कई तरह की चर्चायें हो रही हैं और प्रशासन की कार्यशैली पर अनेक तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक कवि ने यह भी बताया कि सभी शायरों व कवियों को मात्र पांच-पाचं सौ रुपये व अंगवस्त्र दिया गया. इस वजह से यह कवि सम्मेलन पूरी तरह से सवालों के घेरे में है. जानकार बताते हैं कि इस मामले में जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया. सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता व सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार से इस संबंध में पूछ जाने पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया. उन्होनें यह जरूर स्वीकार किया कि श्रोता इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे. इन तमाम चर्चाओं व सवालों के बीच सबकी नजरें जिलाधिकारी पर टिकी हुई हैं. डीएम इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं यह तो समय ही बताएगा. डीएम को गुमराह करने का प्रयास अभी भी जारी है.■

माधवपुर में ग्राम विकास शिविर आयोजित

गोगरी अनुमंडल के परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन विधायक आर एन सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव, डीएम राजीव रौशन एवं डीडीसी एबी अंसारी ने संयुक्त रूप से किया. सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी डॉ पी झा ने दी. वहीं कृषि विभाग से श्रवण कुमार ने किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. जबकि विधायक व डीएम ने अपने अपने हाथों से छात्र-छात्राओं को छात्रवृति की राशि दी. वहीं शिविर को संबोधित करते हुए आरएन सिंह ने कहा कि आज हमारे प्रयास से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है. अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का निर्माण जोर-शोर से हो रहा है. चार वर्ष में यह पुल बन कर तैयार हो जायेगा. उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र से बिजली की समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं. वहीं जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहती हूं. इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पिंकू देवी के प्रतिनिधि अखिल कुमार राय उर्फ मंटू राय, बीडीओ डॉ कुंदन, सीओ शैलेन्द्र कुमार, बीईओ अखिलेश कुमार यादव, बीएओ श्रवण कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.■

– गीता कुमार

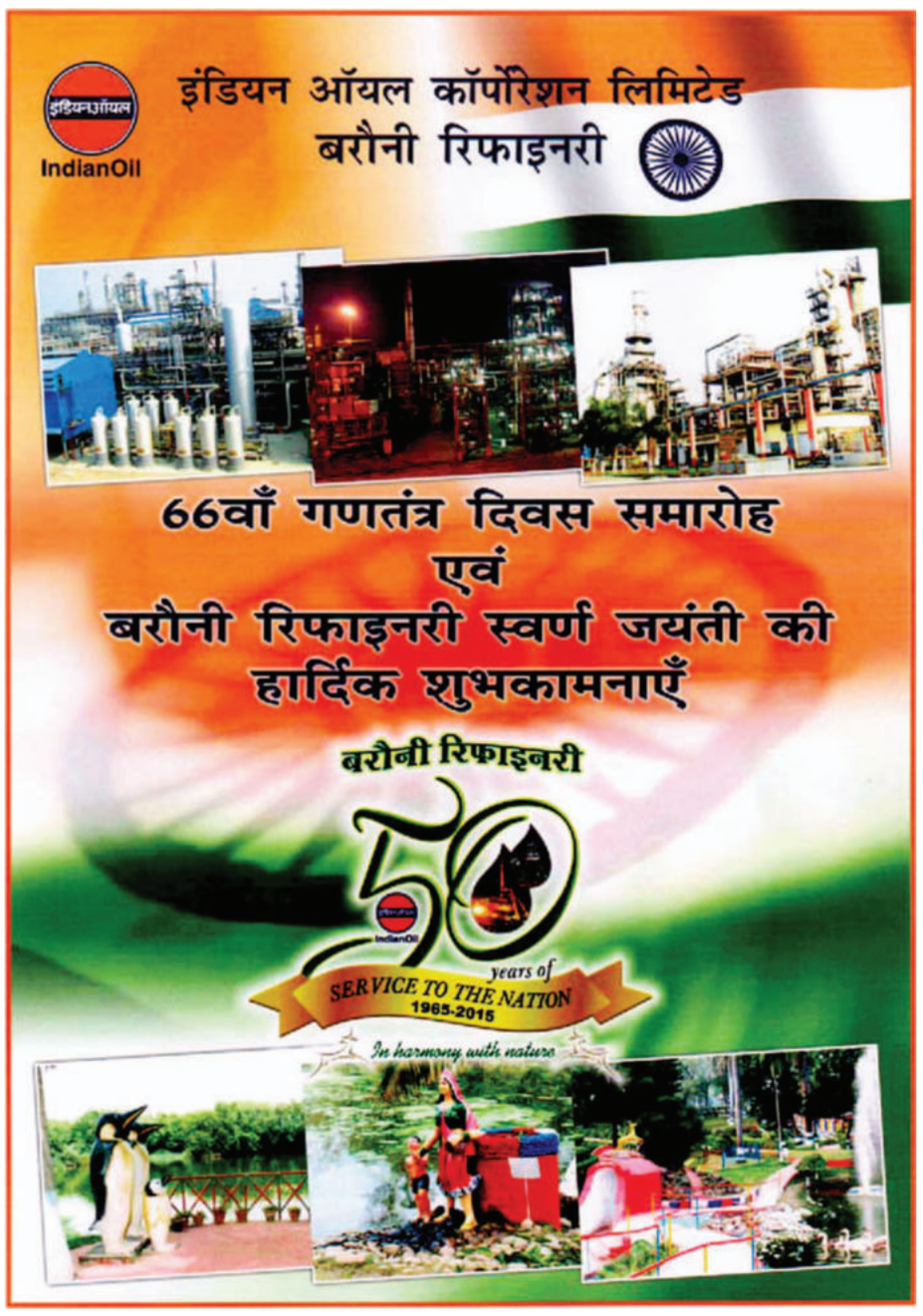

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

09 फरवरी–15 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

प्रभात रंजन दीन

क़ानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ीं

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चहल–पहल भरी सड़क पर शाम का है. वृंदावन कॉलोनी निवासी निखिलेंद्र कुमार गुप्ता (35) उर्फ अमित वकील के साथ–साथ राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भी थे. निखिलेंद्र लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार आरके गुप्ता के पुत्र थे. लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव इसे आपसी रंजिश का मामला बता कर ऐसे गंभीर अपराध को आसान बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह नहीं समझते कि आपसी रंजिश में अपराधी अगर कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं तो यह वाकई शर्मनाक है. घर से चंद कदमों की दूरी पर वकील की मां ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को बम से उड़ते हुए देखा और उन्हें एसएसपी का ऐसा बेजा बयान भी सुनना पड़ा.

वकील निखिलेंद्र गुप्ता की हत्या के विरोध में वकीलों ने जमकर बवाल किया. वकीलों ने लखनऊ पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उकसाए जाने पर हंगामा भी किया, तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई. लखनऊ के मुख्य बाजार हजरतगंज के साथ ही आसपास के सारे बाजार बंद रहे. लखनऊ बार एसोसिएशन ने एसएसपी यशस्वी यादव के हटने तक वकीलों की हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया. सभी वकील हड़ताल पर चले गए और सिविल कोर्ट तथा फैमिली कोर्ट सहित सभी अदालत परिसर में तालाबंदी हो गई. नाराज वकील एसएसपी यशस्वी यादव को हटाने की मांग पर अड़े हैं.

वकील को बम से मारे जाने की घटना के एक ही दिन पहले राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में बसपा विधायक विजय कुमार और उसकी शिक्षा अधिकारी पत्नी मृदुला आनंद ने एक युवा इंजीनियर शिखर श्रीवास्तव की बर्बर हत्या कर दी. इंजीनियर को पहले चाकुओं से गोदा गया, फिर गोली मारी गई और बाद में गाड़ी से कुचला गया. इंजीनियर भी बहराइच के कांग्रेस नेता व जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेशचंद्र श्रीवास्तव का बेटा था. हत्या के पीछे मृदुला आनंद द्वारा इंजीनियर से घूस लेने के साथ–साथ रंजिश के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कारण पुलिस को कार्रवाई से कहां रोकते हैं? हत्या के मामले में अभियुक्त विधायक और उसकी पत्नी समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था के सड़ते जाने की वजहों का खुलासा करते हैं. हत्यारोपी विधायक विजय कुमार गोरखपुर जिले के बांसगांव से बसपा विधायक हैं और इंजीनियर की हत्या की घटना के बाद भी राजधानी में खुलेआम देखे जाते हैं.

अलीगढ़ में बसपा नेता की इसी तरह हुई सनसनीखेज हत्या ने भी कानून व्यवस्था के सवाल को गहरा किया है. अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार रहे धर्मेंद्र चौधरी महावीर गंज में एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे. उनकी गाड़ी जैसे ही बारहद्वारी चौराहे पर पहुंची वहां पहले से मौजूद दो हमलावरों ने मारे गए अपराधी सरगना बृजेश माही के साथी भी मथुरा जेल में ही बंद थे. 17 जनवरी को अपराहन जेल में अचानक गोलियों के धमाके गूंजने लगे. अफरा–तफरी मच गई. अधिकारी वहां पहुंचे तबतक अक्षय सोलंकी मारा जा चुका था. टोटा और राजकुमार शर्मा घायल पड़े थे. हद तो तब हो गई जब इलाज के लिए आगरा ले जाए जा रहे राजेश टोटा पर रात को 11 बजे भारी पुलिसबल की मौजूदगी में हमला बोल दिया गया. बदमाशों ने एंबुलेंस का दरवाजा खुलवाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. टोटा की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस गारद वहां से भाग निकली. एक सिपाही और एक मेडिकल असिस्टेंट घायल हो गए. टोटा के परिवार वालों का आरोप है कि मथुरा जेल से लेकर मथुरा की सड़क तक हुआ हमला पुलिस की मिलीभगत से हुआ है. जेल में हथियार पहुंचने और ऐसे फिल्मी तरीके से लोगों को निबटाए जाने से जेल और पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में तो है ही. यहां तक कि डीएम राजेश कुमार ने भी कहा कि बिना मिलीभगत के हथियार जेल के अंदर नहीं पहुंच सकते. बहरहाल, इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के छींटे तो उड़ा ही दिए.

राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम इलाके में बलिंगटन चौराहे के पास एटीएम वैन से दिनदहाड़े एक करोड़ 35 लाख रुपए लूटे जाने की घटना ने भी लोगों को हिला कर रख दिया है. पुलिस ऐसी घटनाओं से कोई सीख भी नहीं लेती या पुलिस की मिलीभगत से ही ऐसी घटनाएं होती हैं. इस घटना के कुछ ही घंटे बाद लखनऊ के नजदीक उन्नाव में एचसीबीएल बैंक का एटीएम लूटने की कोशिश में एक सुरक्षाकर्मी गोलियों से जख्मी हुआ. कानपुर में तो 20 दिन में एटीएम लूटने की पांच घटनाएं दर्ज हुईं. कुछ अर्सा पहले ही लखनऊ के अलीगंज में भी एटीएम लूट की वारदात हुई थी. उसमें निजी सिक्युरिटी एजेंसी के वाहन से 47 लाख रुपये लूट लिए गए थे. आधिकारिक आंकड़े ही देखें तो आप पाएंगे कि प्रदेशभर में लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार की घटनाओं की भरमार हो गई है. अपराध की अधिकतर घटनाओं में पुलिस की मिलीभगत रहती है और कई वारदात तो खुद पुलिस के लोग ही करते हैं. यह किसी नेता का बयान नहीं, बल्कि आधिकारिक तथ्य है.

> **सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के अलावा अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान तक प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. कुछ ही दिन पहले आजम खान ने कहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति उनसे संभल नहीं पा रही है. मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बावजूद कानून–व्यवस्था ठीक नहीं चल पा रही है.**

लेकिन पत्रकार चुप्पी साधे रहे

वरिष्ठ पत्रकार आरके गुप्ता के पुत्र वकील निखिलेंद्र गुप्ता की हत्या के विरोध में वकील समुदाय एकजुट होकर सड़क पर उतर आया. लेकिन पत्रकार समुदाय की खाल पर कोई असर नहीं पड़ा. पत्रकार आरके गुप्ता के समर्थन में पत्रकारों का कोई संगठन या नेता सामने नहीं आया और न सरकार से इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की. पत्रकारों के इस रुख पर वकील समुदाय से जुड़े लोग खुलेआम खिल्लियां उड़ा रहे हैं.

इटावा में सबसे ज्यादा अपराध

पुलिस और प्रशासन की यह आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि कानपुर के पूरे जोन में इटावा में सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं. इटावा सपा प्रमुख मुलायम, मुख्यमंत्री अखिलेश, कैबिनेट मंत्री शिवपाल, राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रामगोपाल, सांसद धर्मेंद्र, सांसद तेज प्रताप का गृह जनपद है.

पानी मांगा तो पुलिस ने पिलाया पेशाब

महोबा में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर बुरी तरह पीटा, यातनाएं दीं और उसने पानी मांगा तो पेशाब पिला दिया. महोबा के बंधान वार्ड निवासी दीपेंद्र गुप्ता उर्फ विक्की के साथ पुलिस ने ऐसी अमानवीय हरकत की. दीपेंद्र ने अपनी मां रंजना गुप्ता के साथ पुलिस अधीक्षक रामकिशोर को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी देवेंद्र यादव, कांस्टेबल दीपक कुमार और गजेंद्र सिंह ने उसके साथ चौकी से अंदर ऐसी हरकतें कीं. पुलिस ने दीपेंद्र के शरीर के नाजुक हिस्सों पर पेट्रोल भी डाला. दीपेंद्र को दी गई यातनाओं की डॉक्टरी परीक्षण में आधिकारिक पुष्टि हो गई है. ■

बम हमले में मारे गए वकील निखलेन्द्र के पिता आर के गुप्ता के साथ वकील प्रदर्शन करते हुए

आपराधिक खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती

- लखनऊ में वकील व पत्रकार-पुत्र की बम मार कर हत्या.
- लखनऊ में बसपा नेता और उसकी शिक्षा अधिकारी पत्नी ने युवक की बर्बर हत्या की.
- मथुरा जेल से लेकर सड़क तक खूनी हिंसा, कई मरे, पुलिस भागी.
- बरेली में चलती ट्रेन से युवती को फेंका.
- इटावा में अपहृत बच्चे की लाश मिली, गुस्साए लोगों का हंगामा.
- मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या.
- ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में खुला गैंगवार, कई जख्मी.
- गाजियाबाद में महिला ने आईजी पर लगाया रेप का आरोप.
- इटावा में केके डिग्री कॉलेज से छात्रा का दिनदहाड़े अपहरण.
- अलीगढ़ में बसपा नेता की सरेआम गोली मार कर हत्या.
- लखनऊ में एटीएम कैश वैन से दिनदहाड़े डेढ़ करोड़ की लूट.
- बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करते लोगों पर लाठी चार्ज.

वकील निखिलेन्द्र गुप्ता

इंजीनियर शिखर

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

अवैध शराब का कहर

जो बच गए उनकी आंखें जा रही हैं

बुद्ध प्रकाश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इससे सटे उन्नाव जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब तक 50 से ऊपर पहुंच गई है. मलिहाबाद में जहरीली शराब का प्रभाव अभी भी जारी है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं, और आधा दर्जन से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है. वे अब इस दुनिया को देख नहीं पाएंगे. लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर और बलरामपुर अस्पतालों में अभी भी पीड़ित मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

दूसरी ओर प्रदेश में व्यापक छापेमारी से ड्रमों अल्कोहल, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, शराब बनाने के उपकरण, विषाक्त मिथाइल अल्कोहल, शराब भरे टैंकर, नकली शराब की फैक्ट्रियों एवं ग्रामीण अंचलों में धधकती भट्ठियों से बड़े पैमाने पर अवैध शराब का बरामद होना, आबकारी और पुलिस की सक्रियता पर कई नए गंभीर सवाल उठा रहा है. इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश के अंदर शराब माफियाओं ने शराब के इस गोरखधंधे में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली हैं कि उनका उखड़ना इतना आसान काम नहीं होगा. देश और प्रदेश में ऐसे कौन शराब माफिया है, जिनके संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है. जिनके आगे खाकी वर्दी भी बौनी नजर आती है. वास्तव में यह हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसने समाज को एक बार फिर से अंदर तक दहला दिया है. देश में जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तब कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करके और मरने वालों के परिजनों को कुछ मुआवजा देकर कर्तव्य की इतिश्री कर दी जाती है. लेकिन विडम्बना है कि कोई ऐसा कारगर कानून नहीं बनाया जाता, जिससे इन मौत के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा सके.

जहरीली शराब का यह तांडव प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इस प्रकार की पिछली दर्जनों घटनाओं में हजारों बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे हादसों में 90 के दशक में भदोही में 27, अक्टूबर 2001 में नोएडा के 18, फरवरी 2010 में वाराणसी के 13, मार्च 2010 में गाजियाबाद और बुलंदशहर के 30, अक्टूबर 2013 में आजमगढ़ के 37, नवम्बर 2014 में भदोही के 10 लोगों की जान इसी जहरीली शराब ने ले ली. जहरीली शराब की चपेट में राजधानी से सटे सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी सहित पश्चिमी और पूर्वांचल उत्तरप्रदेश के कई जिले हैं. देश के कई अन्य राज्यों में भी जहरीली शराब का कारोबार और उससे होने वाली मौतों का इतिहास रहा है. गतवर्ष पहले पश्चिम बंगाल में जहरीली शराब पीने से लगभग 200 लोगों की मौतें हुई थीं. इसी राज्य में 2008 में 40 और 2009 में 28 लोग जहर रूपी शराब की चपेट में बेमौत मारे गए थे. 2008 में कर्नाटक में 180 लोगों की मौत हुई थी. इसी तरह बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल और गुजरात में भी सैकड़ों लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुके हैं. जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए असली जिम्मेदार कौन लोग हैं? किनकी कारगुजारियों के कारण इन निरीह लोगों को बेमौत मारा जा रहा है? क्या भविष्य में मौत के इन ठेकेदारों पर कठोर कानून बनाकर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं या फिर देश की ये सरकारें मौत के इन सौदागरों को यूं ही आंखें बंद कर देखने का उपक्रम करती रहेंगी?

वर्तमान समय में कच्ची शराब यानी मौत के इस काले कारोबार का गोरखधंधा कुटीर उद्योग के रूप में फैल चुका है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर आसानी से कच्ची दारू, ड्रग्स व स्मैक जैसे महंगे नशीले पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं. यह स्थान शराबियों, स्मैकियों व अपराधियों की शरण स्थली बनते जा रहे हैं. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्ठियां कुकुरमुत्ते की तरह उग आई हैं. सामूहिक रूप से इसका उपयोग भी हो रहा है. परिणामस्वरूप आए दिन खूनी वारदातें होती रहती हैं. सरकार ने जिन लोगों पर इस कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी दे रखी है, वे लोग इसके मुनाफे से अपना हिस्सा लेकर चुप ही रहते हैं. प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही कच्ची शराब के उत्पादन व देशी और अंग्रेजी शराब की तस्करी से न सिर्फ राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि बेगुनाह लोगों की बड़ी संख्या में जाने भी जा रही हैं.

प्रदेश सरकार ने आबकारी और पुलिस विभाग के दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. क्या अब अवैध शराब के बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कस पाएगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि इस प्रकार की त्वरित कार्रवाइयां पहले भी की जा चुकी है, लेकिन जब तक अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी कार्रवाइयां निष्फल ही साबित होती रहेंगी. वास्तविकता यह है कि देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध भट्ठियां हजारों लीटर जहर उगल रही है. स्थानीय शासन प्रशासन और आबकारी विभाग इससे भली-भांति वाकिफ होने के बावजूद भी इसे रोकने की पहल नहीं कर रहा है. ऐसा शायद इसलिए है कि इन लोगों पर राजनीतिक दबाव भी होता है, यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अवैध शराब के कारोबारी माफिया राजनीति से जुड़े होते हैं, या उन्हें किसी न किसी रूप में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है. मौत की दवा बनती कच्ची शराब की इन भट्ठियों की ओर प्रशासन का ध्यान तभी जाता है, जब मलिहाबाद जैसा कोई बड़ा हादसा होता है. ऐसे हादसों के शिकार निरीह गरीब श्रमिक निम्न वर्ग ही होता है. ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी अमीर या बड़े वर्ग के व्यक्ति की मौत जहरीली शराब से हुई हो. इस जहर ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है. निश्चय ही यह जहरीला नशा समाज में कैंसर की तरह अपने पैर जमा चुका है. इसको नेस्तनाबूद करने के लिए सामाजिक जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए सख्त कानून की भी आवश्यकता है. वास्तव में यह समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है. अवैध शराब के कारोबारी तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों तक अपना जाल फैलाए हुए हैं. देश में शराब माफियाओं ने सफेदपोश, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के दम पर नशे के जहर का ये कारोबार बेखौफ होकर चलाते रहते हैं. मौत का यह कारोबार केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बक अन्य प्रदेशों में भी खूब फल-फूल रहा है. यह कटुसत्य भी है कि ऐसा अवैध कारोबार खाकीवर्दी, सफेदपोश और आबकारी विभाग के सहयोग और संरक्षण के बिना चल ही नहीं सकता.

कानूनविद् विशेषज्ञ कहते हैं कि अवैध शराब के कारोबारियों का आर्थिक लाभ के लिए शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाकर बनाना व उसकी बिक्री करना समाज के लिए एक संगठित गिरोहबद्ध अपराध है. लिहाजा इन पर गिरोहबंद अधिनियम के अंतगर्त गैंगेस्टर, एन एस ए व गुण्डा एक्ट तथा आई पीसी की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस 272 आईपीसी के तहत भी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है. लेकिन पुलिस अवैध शराब कारोबारियों पर इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं करती है. देश की राज्य सरकारों को सचेत रहना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पाएं. इसके लिए स्थाई रणनीति बनाकर अवैध शराब कारोबारियों और इनको संरक्षण देने वालों के विरुद्ध गैंग्स्टर जैसी कठोर धाराओं के साथ कार्रवाई करनी होगी. यदि इस घटना से भी सबक नहीं लिया गया और पिछली घटनाओं की तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हो सकती हैं, जो मानवता के लिए कलंक साबित होंगी. ■

उधर जांच जारी तो इधर खनन...

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के गोरखधंधे पर चौथी दुनिया का प्रहार लगातार जारी है. खबरों के प्रकाशन के क्रम में यह उजागर हो चुका है कि किस तरह सत्ता केंद्र से लेकर सत्ता-सामर्थ्य के निचले पायदान तक बैठे लोग इस धंधे के जरिए चांदी काट रहे हैं. इस श्रृंखला में मंत्री से लेकर नेता, माफिया, नौकरशाह, पत्रकार, दलाल सब शामिल हैं. ऐसे पुष्ट तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट की यह कड़ी

शिव दास प्रजापति

उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक व प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न सोनभद्र अवैध खनन का केंद्र बन गया है. कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जमकर संसाधनों की लूट की जा रही है. आधिकारिक दस्तावेज अवैध खनन का धंधा करने वालों के नाम बताते हैं लेकिन इन पर हाथ डालने से शासन और प्रशासन कन्नी काटता है, क्योंकि इसके लाभ में वे भी शामिल हैं. पिछले अंक में अवैध खनन करने वाले कुछ बड़े नाम प्रकाशित किए गए. इनके अलावा भी ऐसे कई खनन पट्टाधारक हैं जिन्होंने अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया और अब भी कर रहे हैं. 15 सितंबर 2014 समेत अन्य कई तिथियों की जांच में क्षेत्रीय लेखपाल समेत तहसील प्रशासन ने इन्हें अवैध खनन करते हुए पाया और अपनी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सौंपी. ऐसे अवैध खनन पट्टाधारकों में निम्नलिखित शामिल हैं-

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7402-क, 7403 और 7404 (कुल रकबा 2.45 एकड़) में खनन पट्टा राम नरेश पुत्र स्व. हरिराम अग्रहरी निवासी ओबरा के नाम दिनांक 24 अगस्त 2017 के लिए स्वीकृत है. इनके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से सटे पश्चिम में अवैध खनन किया जा रहा है और पट्टाधारक द्वारा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गये हैं.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7405 (कुल रकबा-3.15 एकड़) पर खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी संजय कुमार सिंह पुत्र अलगू सिंह और संजीव कुमार सिंह पुत्र राम लखन के नाम दिनांक 27 नवम्बर 2016 तक के लिए स्वीकृत है. उनके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से दक्षिण में अवैध खनन किया जा रहा है तथा मौके पर सीमा स्तंभ भी नहीं पाया गया.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7536-घ (रकबा 1.50 एकड़) में ओबरा नगर पंचायत के सामने वीआईपी रोड स्थित मकान संख्या-ए-2 निवासी अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री अवध नारायण सिंह के नाम दिनांक 29 मार्च 2017 तक खनन पट्टा स्वीकृत है. उनके द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से पूरब में अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-3567, हाल नंबर 7536-ग (कुल रकबा 1.87 एकड़) में चोपन निवासी गणेश प्रताप सिंह पुत्र राम नाथ सिंह के नाम से 14 अप्रैल 2016 तक के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है. पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से उत्तर अवैध खनन किया गया है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. दक्षिण तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7536-ग (कुल रकबा 1.85 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली मारकुंडी गांव निवासी कादिर अली पुत्र तुफेन अहमद, केशव प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र देवराज विश्वकर्मा और रंगनाथ पुत्र भोलानाथ के नाम दिनांक 15 अप्रैल 2016 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ हटा लिए गए हैं. दक्षिण की तरफ खड़ी पहाड़ी है जो खतरनाक स्थिति में है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7569-क (रकबा 2.25 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी गांव निवासी पवन कुमार सिंह आदि के स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स पावग स्टोन क्रेसिंग कंपनी के नाम दिनांक 27 नवंबर, 2016 तक के लिए स्वीकृत है. उनके स्वीकृत क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-7564-क, 7566, 7566-ख और 7568 (कुल रकबा 1.55 एकड़) में खनन पट्टा ओबरा के गजराजनगर निवासी पंकज सिंह पुत्र चंद्रशेखर सिंह के नाम 22 मार्च 2016 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन प्रतीत होता है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव स्थित आराजी संख्या-7617-ख (रकबा 1.5 एकड़) में खनन पट्टा मेसर्स उमा सेवा समिति के नाम दिनांक 20 फरवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है. समिति की सचिव श्रीमती किरन राय पत्नी प्रदीप नारायण और सदस्य सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र परमात्मा सिंह, निवासीगण- बिल्ली-मारकुंडी, द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे उत्तर-पूरब की तरफ अवैध खनन करने का प्रयास किया गया है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिए गए हैं.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-5390-ख, 5391, 5394, 5395 और 5396 (कुल रकबा 2.51 एकड़) में खनन पट्टा मेसर्स दीपाली सेवा समिति के सचिव विनोद कुमार के नाम 29 अप्रैल 2014 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के पूरब अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4478-छ (कुल रकबा 1.22 एकड़) में खनन पट्टा बिल्ली-मारकुंडी स्थित मेसर्स सार्थक सेवा समिति के सचिव के रूप में रॉबर्ट्सगंज निवासी विप्लव जालान पुत्र रवि जालान के नाम 22 दिसंबर, 2016 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण अवैध खनन किया गया है और सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है.

बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-6229-ख (कुल रकबा 1.00 एकड़) में खनन पट्टा ओबरा स्थित मेसर्स सत्यसेवा समिति के अध्यक्ष एसपी सिंह पुत्र राम सूरत सिंह, सचिव श्रीमती रश्मि सिंह पत्नी आशीष सिंह और सदस्य इसहाक पुत्र इदरीश के नाम दिनांक 19 फरवरी 2017 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है. (एसपी सिंह पत्रकार हैं)

बिल्ली-मारकुंडी के आराजी संख्या-6229-ख (कुल रकबा 5.00 एकड़) में खनन पट्टा मनोज कुमार सूद पुत्र सुरेन्द्र कुमार सूद आदि के नाम दिनांक 23 मई, 2024 तक के लिए स्वीकृत है. इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिया गया है.

श्रीमती निर्मला अग्रवाल और श्रीमती चंचला केशरी की संयुक्त स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4478 के कुल 0.62 एकड़ में खनन पट्टा आवंटित है जिसकी मियाद 28 नवंबर 2016 तक है. तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में अवैध खनन में इसके शामिल होने की बात कही गई है. रिपोर्ट में लिखा है कि इनके स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर अवैध खनन किया जा रहा है तथा सीमा स्तंभ भी हटा लिये गए हैं.

डोलो स्टोन पत्थर की खतरनाक खदान में तीन मजदूरों की मौत के बाद भी अवैध खनन का गोरखधंधा चलता रहा लेकिन जिला प्रशासन के नुमाइंदे अवैध खनन रोकने में नाकाम रहे. यह खुद जिला प्रशासन के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ है. वर्ष 2013 से सितंबर, 2014 तक उसकी सभी रिपोर्टों में चोपन निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह पुत्र प्रेम नारायण सिंह के नाम से आबंटित खनन पट्टों की भूमि पर अवैध खनन पाया गया है.

तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-7613 के 1.25 एकड़ क्षेत्रफल में चोपन निवासी धर्मेन्द्र कुमार सिंह के नाम से 28 जून 2019 तक के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है. उनके द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से पश्चिम में अवैध खनन किया जा रहा है और सीमा स्तंभ भी हटा लिए गए हैं. धर्मेन्द्र की अन्य खदान में तहसील प्रशासन ने अवैध खनन पाया है. लेकिन जिला प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा. क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, अगोरी, नायब तहसीलदार, रॉबर्ट्सगंज, तहसीलदार रॉबर्ट्सगंज, क्षेत्राधिकारी, ओबरा और उप-जिलाधिकारी, रॉबर्ट्सगंज ने जिलाधिकारी को दी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चोपन निवासी धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व. प्रेम नारायण सिंह के स्वामित्व वाली मेसर्स सौरभ क्रेशर्स के नाम से आवंटित खनन पट्टे पर खतरनाक ढंग से पत्थर खनन किया जा रहा है, जहां दुर्घटना की संभावना बनी हुई है. कई बार हादसे हो चुके हैं. इसके बावजूद जिला प्रशासन अवैध खनन के धंधे को रोक नहीं सका.

बार-बार भेजी रिपोर्ट लेकिन नहीं रुका अवैध खनन

रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन बिल्ली-मारकुंडी स्थित एक खदान के संचालक द्वारा बार-बार अवैध खनन कराने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को देता रहा लेकिन उसकी खदान और आस-पास में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग सका. यह जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ है. मेसर्स शीला इंटर प्राइजेज के नाम से बिल्ली-मारकुंडी गांव की आराजी संख्या-5593-क के 1.70 एकड़ रकबे में खनन पट्टा आवंटित है. तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में लिखा है कि पट्टाधारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है. लेकिन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगाया गया.

अभी तक पूरी नहीं हुई मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट

पौने तीन साल पहले 27 फरवरी, 2012 को बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में शारदा मंदिर के पीछे पत्थर की एक खदान में टीला धंसने से 10 मजदूरों की मौत हो गई थी. मरने वालों का आंकड़ा सरकारी है. स्थानीय लोग यह संख्या अधिक बताते हैं. बहरहाल, उस हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और न मरने वाले मजदूरों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा ही मिला है. सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन वह अपनी जांच रिपोर्ट कब तक जिला प्रशासन को सौंपेंगे, यह उन्हें मालूम नहीं.

खनन मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच तेज

उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त की जांच ने तेजी पकड़ ली है. जांच में खनन सिंडिकेट के बारे में भी लोकायुक्त को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं. इस मामले को लोकायुक्त की अदालत में गति देने वाली समाजसेवी नूतन ठाकुर ने 28 जनवरी को लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा के समक्ष अवैध खनन के सिंडिकेट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत कीं. सिंडिकेट के प्रमुख लोगों में उन्होंने हमीरपुर के रमेश मिश्रा, जालौन के विजय गुप्ता और सहारनपुर के बसपा विधायक मोहम्मद इकबाल के नाम बताए. उक्त जिलों में खनन में की जा रही भारी अनियमितता के बारे में भी लोकायुक्त को कई तथ्य बताए गए.

नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री के खास लोगों में विकास वर्मा से जुड़े पावनी डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और वैष्णो इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. इसी प्रकार पिंटू सिंह की लक्जरी गाड़ियों के साथ उनके विकास खंड, गोमतीनगर और पाइनवुड सिम्पलेक्स विला में हाल में खरीदे प्लॉट की भी जानकारी दी गई. खनन मंत्री के खास सरकारी लोगों में सोनभद्र में सर्वेयर रामनाथ यादव और जालौन में खनन अधिकारी राजकुमार संगम के बारे में कई तथ्य लोकायुक्त को बताए गए. नूतन ठाकुर ने इस परिवाद के बाद उन्हें और उनके पति को मिल रही धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की. उधर, खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दूसरी बार डॉ. नूतन ठाकुर को कानूनी नोटिस भेजी है और उनकी शिकायतों को अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए 15 दिनों के अन्दर प्रस्तरवार जवाब देने या फौजदारी मुकदमा करने की बात कही है. पिछली नोटिस के जवाब में नूतन ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने लोकहित में परिवाद दिया है. जांच प्रभावित होने की बात कहते हुए उन्होंने श्री प्रजापति को विस्तार से सभी तथ्य बताने से इनकार कर दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

हरीश ने भाजपा के दिग्गजों की बोलती बन्द

राजकुमार शर्मा

विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हुई मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आड़े हाथों लिया. उन्होंने आंकड़े पेश कर भाजपा शासनकाल व वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलनात्मक तस्वीर पेश कर भाजपा के दिग्गजों की बोलती बन्द कर दी. उन्होंने तालठोक कर कहा कि भाजपा नेताओं को आईना दिखाने के लिए यह काफी है. लोकतंत्र में विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप में भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ करना चाहिए और हमेशा लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए. मुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए उनके आरोपों को निराधार बताते हुए अपने एक वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है. जहां तक विकास की बात है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में मैंने 44 घोषणाएं की हैं जिन पर कार्य गतिमान है. नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में करीब 50 घोषणाएं की गई हैं. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के क्षेत्र में भी पेयजल योजना व सड़को के निर्माण को मंजूरी दी गई है, करीब 12 घोषणाएं अब तक की गई हैं. जहां तक विवेकाधीन कोष का सवाल है, भाजपा शासनकाल में वर्ष 2007 से 2012 तक कुल स्वीकृत धनराशि में से केवल सात प्रतिशत विपक्ष के विधायक(कांग्रेस व बसपा) को दिया गया था. इसमें व्यक्तिगत आवेदन भी शामिल है. जबकि कांग्रेस सरकार के अब तक के तीन वर्ष के कार्यकाल में विवेकाधीन कोष में अबतक स्वी.त धनराशि में से 18 प्रतिशत विपक्ष, 50 प्रतिशत व्यक्तिगत आवेदन और 32 प्रतिशत कांग्रेस नेताओं के निवेदन के आधार पर दिया गया है. जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कोई भी सरकार हो कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए. भाजपा नेताओं को अपने शासनकाल को भी याद करना चाहिए. वर्ष 2009 में कालाढूंगी में थाने को फूंकने का कांड, 2011 में शांतिकुंज में भगदड़ में हुई मौतें, कुंभ मेले में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौतें इन सब घटनाओं को वह किस रूप में देखते हैं. उन्होंने कहा यह पूरी तरह से सरकारी तंत्र की विफलता थी, जबकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार में एक भी ऐसा मामला नहीं है. वर्ष 2007 में मसूरी में कमला देवी व रतन लाल की हत्या, वर्ष 2008 में उदासीन अखाड़ा के रत्नाकर मुनी की हत्या, वर्ष 2009 में रामनगर में शादी से उठायी गई महिला की हत्या, वर्ष 2010 में हल्द्वानी के राधिका ज्वैलर्स के पुत्र का अपहरण व हत्या, जसपुर में दो अज्ञात व्यक्तियों की हत्या, काशीपुर में वर्ष 2010 में केपी कालेज की छात्रा की हत्या, काशीपुर में चीनी मिल के निकट कुलदीप कुमार की हत्या जो की भाजपा शासनकाल में हुई और इनका खुलासा आज तक नहीं हो सका है. कांग्रेस शासनकाल में हरिद्वार के फेरूपुर में बालिका की हत्या हुई जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. जबकि रुड़की बम विस्फोट मामले में केंद्र की एनआईए जांच कर रही है. इसे जल्द इसका खुलासा करना चाहिए. वर्तमान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अबतक जितने भी हत्याएं हुई हैं, इनका खुलासा कर दिया गया है. इसी प्रकार डैकेती, लूट आदि मामलों में भी भाजपा शासनकाल की तुलना में वर्तमान में काफी कमी आयी है. ■

पीडीएफ को लेकर कांग्रेस में घमासान

प्रदेश में गठबंधन सरकार का हिस्सा रहे पीडीएफ की विधानसभा चुनाव 2017 की भूमिका पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है. उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत व उनकी चिंता अलग-अलग नहीं है. हरीष रावत को सरकार चलानी है और उन्हें (किशोर) संगठन. पीडीएफ के सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर जो सवाल पहले उठे वही आज भी मौजूद हैं. विधानसभा चुनाव में पीडीएफ विधायक किस पाले में होंगे अभी तय किया जाना चाहिए. पीडीएफ सरकार में रह कर सत्ता की मलाई चट करे फिर चुनाव में कांग्रेस की पीठ में छूरा भोके यह नही चलेगा. चूंकि सवाल एक नहीं सात विधानसभा सीटों का है, जहां असमंजस रहा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता मन से काम नहीं कर पाएंगे. पीसीसी अध्यक्ष ने एक भेंट में कहा कि सीएम को सरकार चलाने के लिए पीडीएफ को सहयोग जरूरी है तो उन्हें संगठन को मजबूती देने के लिए इन सभी समस्याओं का निराकरण कराना है जिससे पार्टी कार्यकर्ता आहत हैं. उपाध्याय ने कहा कि उनकी तरफ से कभी भी पीडीएफ से नाता तोड़ने की मांग नहीं की गई, उनकी आपत्ति परिवहन व समाज कल्याण जैसे विभागों की है. इतने महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज सुव्यवस्थित नहीं है. इसके अलावा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की शिकायतें भी मिल रहीं हैं. इससे संगठन कमजोर होगा और विधानसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा. किशोर उपाध्याय ने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में पीडीएफ के विधायक किस दल से चुनाव लड़ेंगे, वह अभी तय हो जाना चाहिए कि सरकार में शामिल पीडीएफ के विधायक 2017 में किस दल से चुनाव लड़ेंगे. हरीश रावत के अब तक के कार्यकाल को उत्तम बताते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अच्छे कार्यकाल की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण नयी योजनाओं का समावेश किया है. फिलहाल इस सच्चाई से इंकार नही किया जा सकता कि पीडीएफ सरकार के गले की हड्डी बन गया है, जिसे हरीश न निगल पा रहे है न कांग्रेसी मानने को तैयार है. ■

विधानसभा चुनाव में पीडीएफ विधायक किस पाले में होंगे अभी तय किया जाना चाहिए. पीडीएफ सरकार में रह कर सत्ता की मलाई चट करे फिर चुनाव में कांग्रेस की पीठ में छूरा भोके यह नही चलेगा. चूंकि सवाल एक नहीं सात विधानसभा सीटों का है, जहां असमंजस रहा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता मन से काम नहीं कर पाएंगे. पीसीसी अध्यक्ष ने एक भेंट में कहा कि सीएम को सरकार चलाने के लिए पीडीएफ को सहयोग जरूरी है तो उन्हें संगठन को मजबूती देने के लिए इन सभी समस्याओं का निराकरण कराना है जिससे पार्टी कार्यकर्ता आहत हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

26 अप्रैल को खुलेगा श्रीबद्रीनाथ धाम का कपाट

चौथी दुनिया ब्यूरो

श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष में 26 अप्रैल को सुबह पांच बजकर पन्द्रह मिनट पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे. प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए पूर्व महाराजा मनुजयेंद्र शाह ने बसंत पंचमी पर सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर नरेन्द्रनगर स्थित राजदरबार में राजपुरोहित सम्पूर्णानन्द जोशी से विचार-विमर्श कर विधि विधानपूर्वक तिथि घोषित की. बसंत पंचमी पर नरेन्द्रनगर स्थित राजमहल में हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ श्रीबद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि 26 अप्रैल घोषित की गई. महाराजा मनुजयेंद्र शाह, राज पुरोहित पंडित संपूर्णानंद जोशी और पंडित. प्रसाद उनियाल में चर्चा और पूजा-अर्चना के बाद महाराजा ने कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की. इस दौरान पूरा महल श्रीबद्रीनाथ धाम के जयकारों से गूंज उठा. 9 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए तिल के तेल का घड़ा (गाडू घड़ा) राजमहल से श्रीबद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करेगा. श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा यात्राकाल में श्रद्धालुओं को बेहतर पूजा दर्शन व्यवस्था के प्रयास किए गए हैं. जबकि यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए इसी माह समिति की बैठक होगी. उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग को पुख्ता और दुरूस्त रखने के लिए अभी से ताल ठोक दी है. राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को पूरी यात्रा का फोकस चारधाम यात्रा पर रखते हुए लगातार सुरक्षित चारधाम, सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे रहे हैं. ■

जल एवं हवा को शुद्ध रखना दुनिया के हर धर्म की जिम्मेदारी-स्वामी चिदानन्द सरस्वती

चौथी दुनिया ब्यूरो

पानी, हवा और शुद्ध पर्यावरण ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं और यह ऐसे सार्वभौम मुद्दे हैं, जिनसे इस दुनिया के हर व्यक्ति, हर धर्म एवं हर सम्प्रदाय का गहरा सम्बंद्ध है. इन्हें अपने जीवनकाल में शुद्ध रखना तथा भावी पीढ़ियों को साफ-सुथरे स्वरूप में सौंपना मानव मात्र का सबसे बड़ा दायित्व है. इस दायित्व का निर्वहन सभी से कराने के लिए धार्मिक संस्थाओं एवं धर्मगुरुओं को जाति-धर्म-सम्प्रदाय सभी से ऊपर उठकर आगे आना ही चाहिए. यह उद्गार परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज ने केरल के कोट्टायम में सम्पन्न ईसाई धर्मगुरुओं की संगोष्ठी में व्यक्त किए. जलवायु परिवर्तन और वैश्विक विकास विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ईसाई धर्मगुरुओं एवं जनसमुदाय को सम्बोधित कर रहे थे. संगोष्ठी में देश के 14 प्रान्तों तथा विश्व के आठ देशों के आर्क-विषपों एवं पादरियों ने भाग लिया. स्वामी जी ने विशेष रूप से देश की युवा शक्ति का आह्वान किया कि वह पानी और हवा को शुद्ध रखने के काम को अपनी उच्च प्राथमिकताओं में रखें. उन्होंने आद्यगुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली के समीप स्थित केरल की पेरियार नदी एवं आलवा नदी के पुराने और अब के स्वरूप की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जल एवं वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए सभी सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर जुटना चाहिए. उन्होंने चर्चों एवं उनके संचालक पादरियों एवं आर्क-विषपों का आह्वान किया कि वह देश के कोने-कोने में समाज के बीच इस विषय में जन-जागरूकता का व्यापक अभियान चलाएं. तीर्थनगरी के सन्त की अपील पर सभी धर्मगुरुओं एवं जनसमुदाय को खड़े होकर हाथ से हाथ मिलाकर जल व वायु को प्रदूषण से बचाने और उन्हें शुद्ध रखने का संकल्प व्यक्त किया. कार्यक्रम में खासकर युवाओं ने स्वामी चिदानन्द सरस्वती एवं अन्य धर्मगुरुओं से विषयगत ढेरों सवाल पूछे. उनकी जिज्ञासाओं का उचित समाधान किया गया. इस मौके पर चेन्नई स्थित यूनिसेफ के दक्षिण भारत मुख्यालय के प्रमुख श्री अरुण डोभाल तथा जीवा की महासचिव साध्वी भगवती सरस्वती ने भी अपने विचार व्यक्त किए. उपस्थित लोगों ने शुद्ध पानी की समस्या से जूझ रहे केरल प्रान्त में इस तरह से संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए जीवा, परमार्थ निकेतन और यूनिसेफ के प्रति आभार जताया. ■

पहली बार केदारधाम में गूंजा जन गण मन

रेनू शर्मा

प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर्यटन एवं धर्मिक स्थल पूरी तरह से सुरक्षित है. यह संदेश देने के लिए प्रदेश की हरीश रावत सरकार पूरी तरह से सफल रही है. देश की आजादी के बाद पहली बार 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केदारधाम में जन गण मन की गूंज से गूंज उठा. हिमालय की हिमाच्छादित शिखर के केदारधाम से उठी गूंज ने यह पुख्ता कर दिया है कि भीषण तबाही, हिमालय की सुनामी से तबाह केदारधाम में अब सब ठीक चल रहा है. अब तक की प्राचीनतम परम्परा रही है कि शीतकाल में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहां कोई नहीं रहता है. राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत की जिद्द ने हिमालय पर वह अमिट लकीर देश की सरकार, सेना की सहयोग से खींच दी है जो सदैव याद की जाएगी. इस वर्ष आपदा के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के लिए धाम में निम (नेहरू पर्वतारोहण संस्थान) उत्तकाशी की टीम मौजूद है. निम की उपस्थिति से धाम में पहली बार यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत का संदेश पढ़कर सुनाया गया. राष्ट्रगान के बाद टीम ने भगवान केदारनाथ की पूजा की. कार्यक्रम समापन पर राज्यपाल केके पॉल की ओर से लाई गई मिठाई वितरित की गई. समुद्रतल से 11, 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बाबा केदारनाथ धाम, प्रातः आठ बजे से शुरू हुआ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मध्यान 12 बजे तक चला. कार्यक्रम के दौरान धाम में धूप खिली रही. कार्यक्रम संपन्न होने के साथ ही मौसम खराब हो गया. केदारधाम में सुबह आठ बजे तक बर्फबारी होती रही. धाम में सवा दो फीट ताजी बर्फ गिरी थी. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) के प्राचार्य कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि हेलीपैड तक गिरी ताजी बर्फ हटाने का कार्य किया गया. उल्लेखनीय है कि केदारधाम में काम लगातार जारी है, विकट प्राकृतिक परिस्थितियों में केदारधाम को बसाने का काम जनमानस में कौतूहल के साथ चर्चा का विषय बना है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई. बर्फबारी का यह सिलसिला मंगलवार सुबह थमा. इससे पूरे इलाके में करारी ठंड ने एक बार पाव पसार लिया है.

उत्तरकाशी जिले के निचले हिस्सों में बारिश और ढ़ाई हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बारिश बर्फबारी का सिलसिला थमने पर लोगों ने राहत की सांस ली. ढाई हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछी हुई है. सुक्की, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरकीदून क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढके हैं. देश-विदेश के पर्यटक इन क्षेत्रों में पहुंच कर प्रकृति का आनन्द उठा रहे हैं.

केदारनाथ की यात्रा इस वर्ष पूर्व की भांति पूरी रंगत में चलाने का प्रयास हरीश सरकार द्वारा युद्धस्तर पर जारी है. गौरीकुंड से धाम तक पैदल रास्ता बन चुका है जबकि धाम में दो हेलीपैड भी बनाए गए हैं. आवागमन के साधनों के बाद यात्रियों को यहां ठहराने के लिए निम ने तंबू नगरी का खाका तैयार किया है. एमआई-26 हेलीपैड पर तंबू लगाए जाएंगे. इन तंबुओं में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो पूर्व में धाम में मिलती थी. तंबुओं पर नाम पट्ट भी लगाए जाएंगे. स्वागत की भी व्यवस्था होगी, जिससे यात्रियों को परेशानी न हो. लिनचोली में भी 15 सौ यात्रियों के ठहरने के लिए तंबू लगाए जाएंगे. केदारनाथ में 75 कॉटेज और बनाए जाएंगे, जिसमें 25 लिनचौली में बनेंगे. निम 30 से 35 लोगों को प्रशिक्षण भी देगा, जो यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को देखेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com